राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 223

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 20 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रोहित के शतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीती वन डे सीरीज

>> 14

तंत्र के गण

आइए! मिलकर मनाएं

उत्सव गणतंत्र का

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर दैनिक जागरण अपने पाठकों के लिए लेकर आया है विशेष संपादकीय आयोजन- **'तंत्र के गण'**। सप्ताहभर के इस आयोजन का ध्येय देश के समृद्धशाली गणतंत्र का उत्सव मनाना और देश-समाज को इसे और भी समृद्ध बनाने की दिशा में प्रेरित व उत्साहित करना है। इस क्रम में हम उन व्यक्ति व संस्थाओं के प्रेरक प्रयासों को सामने लाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें 'तंत्र के गण' के रूप में परिभाषित किया। आइए, इनके कार्यों-प्रयासों को समझें, सीखें और आत्मसात कर देश-समाज को समृद्धि के नए शिखर पर ले जाने का संकल्प लें। पेज-11

जश्न-ए-शाहीन का विरोध करने पहुंचे कश्मीरी पंडित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने की धक्का-मुक्की
- 30 सालों से दर-ब-दर रह रहे कश्मीरी पंडितों ने मांगा अपना घर

शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में रविवार को कश्मीरी पंडितों के पहुंचने पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शनकारियों से उन्हें उनका घर वापस दिलाने के लिए समर्थन मांगा। साथ ही उन्होंने स्वरा भास्कर के द्वारा बुलाए गए जश्न-ए-शाहीन का विरोध किया। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि आज के दिन ही 30 साल पहले उन्हें उनके घर से विस्थापित कर दिया गया था। हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर दिया गया था। यह कार्यक्रम उनकी शहादत का अपमान है। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल से मंच से उतरते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने धक्कामुक्की भी की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल बिना अपनी बात पूरी किए मंच से उतरकर वापस चला गया।

गत 16 जनवरी को स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर 19 जनवरी को शाहीन बाग की महिलाओं के समर्थन में जश्न-ए-शाहीन एक शाम गीतों के नाम कार्यक्रम की जानकारी दी थी। कश्मीरी पंडित सतीश महालदार ने कहा कि 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के दिन शाहीन बाग में इस तरह का कार्यक्रम होना हमारे समुदाय की शहादत का अपमान है। रविवार शाम को कश्मीरी पंडितों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शाहीन बाग पहुंचा और अपने लिए समर्थन की मांग की। मंच से उतरते समय कश्मीरी पंडितों द्वारा न्याय दो का नारा लगाने पर प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ धक्कामुक्की भी की।

कश्मीरी पंडितों के लिए मांगा समर्थन पेज>>5

मुजफ्फरपुर के दरधा घाट पर आथर गांव के ग्रामीणों ने रविवार को बूढ़ी गंडक की धार पर मानव शृंखला बनाकर जल-जीवन-हरियाली का संदेश दिया और नशापान व दहेज के खिलाफ हाथ जोड़कर एकजुटता का प्रदर्शन किया। आथर व दरधा गांव को जोड़ने वाली तकरीबन 200 फीट चौड़ी नदी में 18 नावें लगाई गई थीं। पंकज कुमार

बिहार में जल-जीवन-हरियाली के लिए बनाई मानव शृंखला

18034 किमी शृंखला की कुल लंबाई

5,16,71389 लोग हुए शामिल

07 हेलीकॉप्टरों से हुई मॉनिटरिंग

100 प्रयोग में लाए गए ड्रोन

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। जल-जीवन, हरियाली अभियान निरंतर चलता रहेगा तभी लोगों में जागरुकता रहेगी। -**नीतीश कुमार**, मुख्यमंत्री, बिहार

संबंधित सामग्री >> पेज 6

जागरण विशेष

किसानों के लिए आफत, जंगल के लिए बरकत!

लखनऊ : सीमावर्ती वनक्षेत्र में नेपाल से पहुंचे हाथियों की संख्या दो सौ के पार पहुंच गई है।

परदेसी हाथी हर साल जमकर उत्पात मचाते हैं। फसलें उजाड़ते हैं। लोगों पर हमला करते हैं, मगर वन्यकर्मी उनकी आमद जंगल के लिए शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। (पेज-7)

सीएए पर अमल की तैयारी

योजना ▶ गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बावजूद कानून पर आगे बढ़ेगी सरकार

नियमों को अंतिम रूप देने में जुटा केंद्र, फरवरी में किए जा सकते हैं अधिसूचित

नीलू रंजन, नई दिल्ली

गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने की तैयारी में है। 10 जनवरी को सीएए की अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार अब इसे लागू किए जाने के नियम-कायदों को अंतिम रूप देने में जुटी है। असम के लिए नियम-कायदे बाकी देश से अलग हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन नियम-कायदों को फरवरी के पहले हफ्ते में अधिसूचित किया सकता है।

गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार असम सरकार की ओर से सीएए के लिए विशेष नियम-कायदे बनाने का सुझाव आया है। इसमें इसे तीन महीने की अवधि में पूरा करना और असम में चले एनआरसी से जोड़ना शामिल है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले असम के एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार पिछले दिनों असम में एनआरसी की प्रक्रिया चली है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि 2014 के पहले राज्य में बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया हो। उनके अनुसार लोगों को सीएए के लिए भी वही दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाएगा, जो उन्होंने एनआरसी के दौरान दिखाए थे। उन्होंने कहा कि असम में सीएए विरोधियों की ओर से जताई जा रही आशंका के विपरीत लगभग तीन लाख लोग ही इसके तहत भारत की नागरिकता के हकदार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बांग्लादेश से आए लगभग पांच लाख अल्पसंख्यक एनआरसी से बाहर हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान इनमें से दो लाख लोग स्वतः ही एनआरसी में शामिल हो जाएंगे। इनमें अधिकतर हिंदू हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीएए में असम के लिए विशेष प्रावधान करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर

सरकार की नजर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर होने वाली सुनवाई पर भी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन इसका विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पूरी होने तक इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग सकते हैं। हालांकि, सरकार का मानना है कि संवैधानिक रूप से दुरुस्त यह कानून अदालत की कसौटी पर खरा उतरेगा।

कांग्रेस शासित राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव लाएंगे

नई दिल्ली : सीएए के खिलाफ पार्टी के विरोध को और तेज करने के लिए पंजाब के बाद सभी कांग्रेस शासित राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव पारित करेंगे। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही पंजाब के नक्शे कदम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं से भी सीएए को रद करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। (पेज-5)

शेख हसीना बोलीं, सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला पेज>>5

विरोध को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन का होगा प्रावधान

- केंद्र सरकार गैर-भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते विरोध और राज्य विधानसभाओं में पारित प्रस्तावों का भी इसमें ध्यान रख रही है।
- राज्य सरकारें सीएए को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, लेकिन केंद्र का मानना है कि इसे लागू करने में अड़चन डालने की कोशिश हो सकती है।
- इसे देखते हुए नागरिकता के लिए आवेदन को ऑनलाइन किया जाना तय माना जा रहा है, ताकि आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
- एक बार आवेदन हो जाने के बाद उनके सत्यापन की जरूरत पड़ेगी, जो सामान्य रूप से जिलाधिकारी के माध्यम से होता रहा है।
- चूंकि जिलाधिकारी राज्य सरकार के मातहत काम करता है, इसीलिए सीएए के नियम-कायदे में वैकल्पिक व्यवस्था का भी उल्लेख हो सकता है।

'संविधान में कुछ लिखा है तो उसका पालन करना होगा'

- कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले-सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो सीएए संविधान की किताब में बरकरार रहेगा

नई दिल्ली, एजेंसियां : कपिल सिब्बल के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सीएए पर अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो संविधान में नया कानून कायम रहेगा और उसका पालन भी करना होगा। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सिब्बल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संसद में एक बार पारित हुए कानून को राज्य सरकारें नहीं रोक सकती हैं। कपिल सिब्बल जी कानूनी तौर पर सही बात कह रहे हैं।

खुर्शीद ने रविवार को सिब्बल के शनिवार के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता है तो सीएए संविधान की किताब में बरकरार रहेगा और अगर संविधान में कुछ लिखा है तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अन्यथा इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक सीएए का सवाल है, राज्य सरकारों के केंद्र से बहुत ही गहरे मतभेद हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करेंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। तब तक सब कुछ कहा गया, किया गया या नहीं किया गया प्रयोगात्मक और अस्थाई है।

उल्लेखनीय है कि सीएए को केरल सरकार समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसके लिए वही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आवेदन कर सकेंगे जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना दी गई हो और वह 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ चुके हैं।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

तारिक अनवर ने कहा, आरिफ मुहम्मद के बयान का महत्व नहीं पेज>>5
छह वर्षों में 2838 पाकिस्तानियों को मिली है भारतीय नागरिकता : निर्मला पेज>>5
सिब्बल का सच (विचार) पेज>>8

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

साईबाबा के जन्मस्थान पर विवाद को लेकर शिरडी बंद

शिरडी : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा साईबाबा के जन्मस्थान को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में रविवार को शिरडी बंद रहा। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब ठाकरे ने परभणी जिले के पथरी को साईबाबा का जन्मस्थान बताते हुए उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देने का एलान किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

कश्मीर में इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं लोग : सारस्वत

अहमदाबाद : नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद इंटरनेट पर पाबंदी से अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि लोग वहां इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनके इस बयान पर केसीसीआइ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोप निर्लज्ज और गैरकानूनी

वाशिंगटन : सीनेट से मिले समन के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों पर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए दोनों आरोप निर्लज्जता से भरे और गैरकानूनी हैं। इन आधारहीन आरोपों के जरिये राष्ट्रपति को हटाने की साजिश रची गई है।

आजम को झटका, जमीन के दस मुकदमे हारे

जागरण संवाददाता, रामपुर

- अनुसूचित जाति के लोगों का है मामला, राजस्व परिषद ने दायर किया था मुकदमा
- रजिस्ट्री हुई खारिज, मंडलायुक्त का आदेश निरस्त

सांसद आजम खां को राजस्व परिषद से तगड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बिना अनुमति अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने के 10 मुकदमों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। आजम के खिलाफ मार्च 2018 में राजस्व परिषद इलाहाबाद में 10 मुकदमे दायर कराए गए थे। हालांकि यह जमीन सपा शासनकाल में खरीदी गई थी।

भाजपा के सत्ता में आने पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। आरोप लगाया कि आजम खां ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से यूनिवर्सिटी के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की जो जमीन खरीदीं, उनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। इन लोगों को पट्टे में जमीन मिली थी, जिसे बेचने का उन्हें अधिकार नहीं था।

आजम खां फाइल फोटो

अनुसूचित जाति के लोगों ने जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली। इस पर तहसीलदार ने 2013 में ही अपील भी दायर की थी, लेकिन उपजिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने निष्पक्ष रूप से विचार किए बिना निर्णय पारित कर दिया।

जिलाधिकारी का अनुमति संबंधी आदेश नहीं था, लेकिन यह कह दिया गया कि आदेश कहीं गुम हो गया है। इसे मंडलायुक्त ने मान भी लिया। शिकायत में उन्होंने मंडलायुक्त के सात नवंबर 2013 को दिए आदेश को निरस्त करने की मांग की। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद मार्च 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने राजस्व परिषद में 10 मुकदमे दायर करने के आदेश दिए। आकाश सक्सेना को पैरवी के लिए निगरानीकर्ता भी बनाया गया। उन्होंने बताया कि परिषद ने अब फैसला सुना दिया है। परिषद ने मंडलायुक्त के आदेश को गलत ठहराया है। अब रजिस्ट्री खारिज होंगी। करीब 100 बीघा जमीन विवि परिसर में है।

मुख्यमंत्री से अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन दिलाने की मांग करेंगे पेज>>6

मथुरा घूमने गई युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या

जागरण संवाददाता, नोएडा

- सहकर्मी युवती और दो युवकों के साथ गई थी घूमने, लौटने के दौरान हुई घटना
- अनुसूचित जाति की है युवती, उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता है परिवार

अनुसूचित जाति की युवती की दुष्कर्म के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उप्र के नोएडा की निजी कंपनी में कार्यरत 20 वर्षीय युवती शुक्रवार को सहकर्मी युवती व दो युवकों के साथ मथुरा घूमने गई थी। लौटने के दौरान घटना हुई। शुक्रवार देर रात घायल अवस्था में उसे जेवर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर हालत में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने रविवार दोपहर नोएडा कोतवाली सेक्टर-49 का घेराव व प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने दो नामजद युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिक जांच के बाद डीसीपी संकल्प शर्मा ने कहा कि मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

नोएडा कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र में रहने वाले युवती के पिता ने थाने में दी गई शिकायत में कहा है कि 17 जनवरी की सुबह वह घर से कंपनी के लिए निकली थी। रात नौ बजे के बाद उसके साथ काम करने वाली एक अन्य युवती ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी दुर्घटना में घायल हो गई है। वह जेवर स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती है। पिता ने आरोप लगाया है कि देखने से प्रतीत हो रहा है कि वह दुर्घटना में घायल नहीं हुई, बल्कि दुष्कर्म के बाद उसे काफी पीटा गया है। गढ़ी निवासी श्याम व सर्फाबाद निवासी सचिन नाम के युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। शिकायत के अनुसार, युवती के प्राइवेट पार्ट से ज्यादा रक्तस्राव होने पर उसे जीटीबी अस्पताल, दिल्ली रेफर किया गया जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में श्याम व सचिन के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

रविवार शाम डीसीपी जोन संकल्प शर्मा व डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। डीसीपी संकल्प शर्मा ने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवती अपनी सहकर्मी युवती व उसके दो परिचित युवकों के साथ मोटरसाइकिल से मथुरा घूमने गई थी। लौटने के दौरान मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में वे लोग एक्सप्रेस वे पर ही किसी कारण से रुके थे। नामजद आरोपितों से पूछताछ में पता लगा है कि वहां एक कार ने युवती को टक्कर मारी है। इसके बाद ही गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पेचीदगी

इसी कानूनी पेच का फायदा उठा रहे हैं दिल्ली दुष्कर्मकांड के चारों दोषी, फांसी पर दोषियों में से दो ने क्यूरेटिव व तीन ने दया याचिका नहीं डाली

एक जुर्म में दोषियों को अलग-अलग नहीं हो सकती फांसी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- पूर्व में एक केस में एक ही अपराध में तीन दोषियों को अलग-अलग सजाएं हो गई थीं

मृत्युदंड की सजा पाए दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठ रही है। दूसरी ओर, चारों दोषी कानूनी विकल्प में देरी का हर हथकंडा अपना रहे हैं। वे एक-एक कर अर्जी देते हैं, ताकि जब तक हो सके मौत टली रहे। ऐसे में एक वर्ग कहने लगा है कि अगर चार में से एक दोषी के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं, तो पहले उसे ही फांसी दे दी जाए। लेकिन अगर परंपरा और कानूनी स्थिति देखी जाए तो एक जुर्म में सजा पाए सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका कारण है कि मृत्युदंड के मामले में किसी भी स्तर पर किसी भी दोषी के साथ अन्याय की आशंका न रहे।

एक मामला ऐसा हो चुका है जिसमें एक जुर्म के दोषी तीन लोगों को अलग-अलग सजा मिली। एक को फांसी दे दी गई, दूसरे की फांसी सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान माफ हो गई और तीसरे की दया याचिका जब राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और उसका डेथ वारंट जारी हो गया तब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला आया और कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 1982 में दिए गए उस फैसले में कहा है कि फांसी की सजा के किसी भी मामले में फांसी तामील करने से पहले जेलर बाकी दोषियों के मामले की स्थिति जांचेगा। अगर बाकी दोषियों की फांसी माफ हो चुकी है तो तत्काल यह बात उच्च अथॉरिटी और संबंधित अदालत के संज्ञान में लाई जाएगी। उस फैसले की कानूनी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि जेलर फांसी देने से पहले चेक करेगा कि क्या किसी सह दोषी की फांसी माफ हो चुकी है और उसकी जानकारी कोर्ट को देगा। इसका मतलब यह भी निकलता है कि सह दोषी की दया याचिका पर आने वाले आदेश का असर दूसरे अभियुक्त के केस पर भी पड़ेगा यानी जेलर को फांसी देने से पहले संबंधित अदालत को यह बताना पड़ेगा कि मामले के बाकी दोषियों की दया याचिका अभी लंबित है।

एक ही जुर्म के सभी दोषियों को साथ फांसी देने की कानूनी स्थिति पर तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ अफसर सुनील गुप्ता कहते हैं कि जेल मैनुअल और कानून में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन परंपरा यही है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाती है। वह कहते हैं कि उनके कार्यकाल में 1982 से 2013 तक तिहाड़ में कुल आठ दोषियों को फांसी हो चुकी है। इसमें से तीन बार दो-दो दोषियों को एक साथ फांसी दी गई। 1982 में रंगा बिल्ला, 1989 में सतवंत सिंह और केहर सिंह तथा 1995 में करतार सिंह और उजागर सिंह को एक साथ फांसी दी गई थी। इन छह के अलावा मकबूल बट को 1983 में और अफजल गुरू को 2013 में फांसी हुई थी।

ज्ञानंत कहते हैं कि हाई कोर्ट से फांसी पर मुहर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करना मैटर ऑफ राइट नहीं है। ऐसे मामलों में या तो क्रिमिनल अपील के लिए हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लिया जाता है या फिर दोषी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करता है जिसे अपील में तब्दील करना कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। फांसी के मामले में कोर्ट कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता।

दिल्ली दुष्कर्म कांड में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चार दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय को फांसी की सजा सुनाई गई है। चारों की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दो की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज हो चुकी हैं जबकि एक दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ठुकरा चुके हैं। चारों को फांसी देने के लिए एक फरवरी की तारीख तय है। अभी तक दो दोषियों ने क्यूरेटिव नहीं दाखिल की है जबकि तीन ने दया याचिका नहीं डाली है।

एयर इंडिया ने यौन उत्पीड़न के दोषी पायलट को बहाल किया

- महिला पायलट के आरोपों पर पिछले साल किए गए थे निलंबित

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयर इंडिया ने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए वरिष्ठ पायलट कैप्टन सचिन गुप्ता को बहाल कर दिया है। कैप्टन गुप्ता पर एक सहयोगी महिला पायलट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद पिछले साल मई में उन्हें निलंबित किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि महिला पायलट के आरोपों की जांच कर रही आंतरिक समिति ने कैप्टन सचिन गुप्ता पर 'बड़ा जुर्माना' लगाया है। हालांकि, उन्होंने सजा के खिलाफ उच्च प्राधिकार से अपील की है। इस संबंध में पूछे गए विशेष सवाल के जवाब में एयर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) पीएस नेगी ने बताया, 'एयर इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) ने मामले की जांच की और कैप्टन सचिन गुप्ता को दुराचरण का दोषी पाया। समिति ने सेवा नियम के तहत उन पर बड़ा जुर्माना लगाया है।' उन्होंने कहा, 'सेवा नियमावली के तहत कैप्टन सचिन गुप्ता ने अब अगले उच्च प्राधिकार/सीएमडी (चेयरमैन व प्रबंध निदेशक) के समक्ष सजा के खिलाफ अपील की है। इस पर तय समय में विचार किया जाएगा।'

एक अन्य अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एयर इंडिया ने कैप्टन गुप्ता को बहाल कर दिया है। एयर इंडिया ने कैप्टन गुप्ता को पिछले साल यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित करते हुए कहा था, 'इस मामले में जब तक जांच लंबित है तब तक आप एयर इंडिया लिमिटेड के परिसर में बिना लिखित अनुमति के प्रवेश नहीं करेंगे।'

पीड़ित महिला पायलट की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया है कि कथित वाकया पांच मई 2019 को हैदराबाद में हुआ।

31 सीटें जीती थीं भाजपा ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इस चुनाव में उसको 33 फीसद वोट मिले थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 20 जनवरी 2020

पांच साल तक देंगे मुफ्त बिजली-पानी और बस का सफर : केजरीवाल

रणनीति ▸ विपक्ष की ओर से चुनाव के बाद मुफ्त योजनाओं को बंद करने के आरोपों के बीच सीएम ने जारी किया गारंटी कार्ड

मुख्यमंत्री का टाउन हॉल की सभाओं का दूसरा चरण 23 से होगा शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विपक्ष द्वारा चुनाव के बाद सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त योजनाओं को बंद करने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड जारी किया है। इसमें उन्होंने अगले पांच साल तक सारी योजनाएं जारी रखने का वादा किया है। इसके साथ ही कहा कि जब तक मैं हूं मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को बस यात्रा के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस गारंटी कार्ड के साथ ही मुख्यमंत्री का टाउन हॉल की सभाओं का दूसरा चरण (23 से 30 जनवरी तक) आयोजित होगा।

पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय में गारंटी कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह भ्रम फैला रही हैं कि 31 मार्च बाद मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जनता किसी के बहकावे में न आए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोषणा पत्र नहीं है। विस्तृत घोषणा पत्र अगले एक सप्ताह में जारी किया जाएगा।

केजरीवाल ने गारंटी कार्ड में अपनी सरकार की 200 यूनिट तक बिजली और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर और 20 हजार लीटर पानी के साथ जहां-झुग्गी वहीं मकान योजना का उल्लेख किया है। साथ ही छात्रों को बसों में मुफ्त सफर के साथ ही बसों की तर्ज पर ही मोहल्ला मार्शल तैनात करने की भी गारंटी दी है।

गारंटी कार्ड की प्रमुख बातें

बिजली : दिल्ली में अगले पांच साल तक 24 घंटे और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जारी रहेगी। जहां पर बिजली के तारों का जाल बना हुआ है और हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं, वहां ये सभी समस्याएं खत्म की जाएंगी।

पानी : दिल्ली में पहले मात्र 58 फीसद हिस्से में पानी की पाइपलाइन बिछी हुई थी। हमने पांच साल में 93 फीसद हिस्से में पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम किया है। अगले पांच सालों में सौ फीसद हिस्से में और हर घर तक नल से 24 घंटे स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना पांच साल तक चलती रहेगी।

शिक्षा : दिल्ली में जो भी बच्चा पैदा होगा, उसे 12वीं तक बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। चाहे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसे बेहतर शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह काम लगभग पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो भी कमियां रह गई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।

चिकित्सा : दिल्ली के हर व्यक्ति चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, उसको बेहतर एवं मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था देने की गारंटी है। इस दिशा में भी हम बहुत सारे काम कर चुके हैं। कई नए अस्पताल खोले जा रहे है। नए-नए मोहल्ला क्लीनिक खोले जा रहे हैं।

विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी कार्ड जारी करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। संजय

मौजूदा अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। 15,000 बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था बनाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो उसकी जान बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मुहैया कराई जा सके।

परिवहन : अंतरराष्ट्रीय स्तर की यातायात व्यवस्था दिल्ली में स्थापित की जाएगी। जल्द ही लगभग 11 हजार बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी। 500 किलोमीटर से भी अधिक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाएं अपने घर से दफ्तर, कॉलेज और वापस अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे। पांच साल तक महिलाओं को बस में सफर मुफ्त के साथ विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त यात्रा योजना का प्रावधान किया जाएगा।

पर्यावरण : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दो करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। वैक्यूम क्लीनिंग के जरिये धूल और मिट्टी को नियंत्रित किया जाएगा।

यमुना : यमुना की सफाई भी की जाएगी। पांच साल में यमुना के पानी को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है। दिल्ली में जो कचरा है, जो गंदगी है, उसकी सफाई करनी है। जगह-जगह जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो मलबा पड़ा है, उसको साफ करना है। दिल्ली की गलियों को, सड़कों को, नालियों को, सीवर को साफ करना है। दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है।

महिला सुरक्षा : हमने दिल्ली में महिला की सुरक्षा के लिए डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। अन्य डेढ़ लाख लगाने का काम चल रहा है। दिल्ली के कोने-कोने में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। 2.10 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं। यह संख्या बाधित नहीं है, जितने भी सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट महिला सुरक्षा के लिए लगानी पड़े हम लगाएंगे। दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। जिस प्रकार से बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की तैनाती की गई है। उसी तरह स्थानीय क्षेत्रों में भी मोहल्ला मार्शल की तैनाती की जाएगी।

कच्ची कॉलोनियां : दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। हर कच्ची कॉलोनी में सड़क, नाली, पानी, सीवर, मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी कैमरा मुहैया कराई जाएगी।

जहां झुग्गी वहां मकान : जो भाई बहन गरीबी के कारण झुग्गी में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए पक्के मकानों की व्यवस्था की जाएगी। गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। अगले पांच वर्ष में शेष लोगों को मकान दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गारंटी कार्ड में जिन कार्यों को शामिल किया गया है, वे दिल्ली की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए हैं। इनमें से कई योजनाएं लागू हो गई हैं और कुछ योजनाएं अगले कुछ सालों में लागू हो जाएंगी। इसमें 24 घंटे स्वच्छ पानी के साथ कॉलोनियों में खुले बिजली के तारों को हटाकर उन्हें भूमिगत भी किया जाएगा। इसके साथ ही 12वीं तक बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की गारंटी लेता हूं। महिला सुरक्षा की गारंटी है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। जितने कैमरों की आगे जरूरत पड़ेगी, उतने कैमरे लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट भी लगेंगी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के साथ यमुना साफ करने का कार्य भी किया जाएगा।

पांच साल पहले के वादों को दोहरा रहे सीएम : तिवारी

आरोप-प्रत्यारोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा का कहना है कि आप को दस कामों की गारंटी देने के पहले 2015 में दिल्ली की जनता से किए गए 70 वादों का हिसाब देना चाहिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि जब वादों का हिसाब देने का समय आया तो सीएम अरविंद केजरीवाल नए वादे करके दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे हैं। घोषणा पत्र जारी करने से पहले वह उन कामों की गारंटी दे रहे हैं, जिन्हें पांच साल के कार्यकाल में पूरा नहीं किया। इससे आप की कथनी और करनी में अंतर को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को मार्च तक ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का आदेश क्यों दिया है? पांच सालों में तारों का जंजाल नहीं हटाए जाने से आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आप सरकार को बताना चाहिए कि दिल्ली में कितने लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है? दिल्ली में नए बने स्कूल-कॉलेज का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू नहीं करने और अस्पतालों की दशा सुधारने में विफल रहने का कारण भी मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। मेट्रो विस्तार में बाधा डालने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं। तिवारी ने कहा कि आप सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

गारंटी कार्ड के नाम पर गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अपनी संभावित हार से हताश और निराश आप गांरटी कार्ड जारी करके दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे 'जुमला कार्ड' करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र व दिल्ली सरकार बिजली की हाईटेंशन लाइन के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों का मालिकाना हक नहीं दे रही है। अब जनता का विरोध देखते हुए इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 कॉलेज बनाने का वादा किया गया था और एक भी नहीं बनाया गया। दिल्लीवासियों को दूषित पानी पिलाने वाले केजरीवाल अब कांग्रेस की कैशबैक योजना को मिल रहे भारी समर्थन से बौखलाकर आप शुद्ध पानी की बात कर रही है। पांच वर्षों में पानी साफ करने के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। इसी तरह से एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया गया और अब अस्पताल बनाने का वादा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। 32 सौ से ज्यादा बसें सड़कों से हट गई है। मेट्रो के तीसरे चरण का काम तीन साल और चौथे चरण का पांच साल पीछे चल रहा है।

चुनावी हलचल

नामांकन से पहले रोड शो करेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को नामांकन करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सुबह दस बजे वाल्मीकि सदन पहुंचेंगे। यहां पर मंदिर में दर्शन के बाद रोड शो करते हुए नामांकन के लिए निकलेंगे। वह जाम नगर स्थित नई दिल्ली विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी को नामांकन का आवेदन देंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, सोमवार को मैं अपना नामांकन दाखिल करने जाऊंगा। अगर आप अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नामांकन में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। नई दिल्ली विधानसभा से वह तीसरी बार नामांकन करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ पहला नामांकन किया था। इसमें जीत दर्ज की थी। 2015 के में नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज केजरीवाल दूसरी बार सीएम बने थे। (जासं)

उम्मीदवारों के नामांकन के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन

नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए अब दो दिन का समय बचा है। अब तक कम नामांकन होने के कारण आखिरी दो दिन निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में उम्मीदवारों की काफी भीड़ होने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, अब तक 153 उम्मीदवारों ने नामांकन के लिए 214 पर्चे भरे हैं। इनमें ज्यादातर छोटे दलों के उम्मीदवार व निर्दलीय प्रत्याशी हैं। प्रमुख दलों में आप के करीब 50 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और 20 उम्मीदवारों का नामांकन होना बाकी है। भाजपा के एक उम्मीदवार ने नामांकन किया है। कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार ने अब तक पर्चा नहीं भरा है क्योंकि कांग्रेस ने शनिवार रात को 54 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसलिए सोमवार को कांग्रेस व भाजपा के उम्मीदवार भी पर्चा दाखिल करने निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं आप के बाकी बचे उम्मीदवार भी आखिरी दो दिन में पर्चा भरेंगे। (राब्यू)

हरियाणा भाजपा ने चुनाव में झोंकी पूरी ताकत

पार्टियों की रणनीति

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के 33 भाजपा नेता दिल्ली के 17 विधानसभा क्षेत्रों में करीब एक पखवाड़े से पहले ही काम कर रहे हैं। इसके साथ अब हरियाणा प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटें जीतने की पूरी जिम्मेदारी दे दी है। इन सीटों पर भी भट्ट हरियाणा से अतिरिक्त कार्यकर्ता काम के लिए बुलाएंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हरियाणा सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए बुलाया गया है। इन वरिष्ठ नेताओं की शनिवार रात्रि दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिम्मेदारी भी लगाई गई।

केंद्र में हरियाणा से तीनों मंत्रियों सहित 15 वरिष्ठ नेता संभालेंगे प्रचार : दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा से केंद्र सरकार में तीनों राज्य मंत्रियों के सहित 15 वरिष्ठ नेता प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। इसमें हरियाणा के दिग्गज मंत्रियों और सांसदों सहित विधायक भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु जैसे दिग्गज नेता को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान दी गई है। पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ खुद हरियाणा से दिल्ली आए नेताओं के बीच प्रांत प्रमुख के नाते संपर्क संभाल रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भाजपा की गंभीरता इसी बात से झलक जाती है कि रविवार शाम पार्टी मुख्यालय में होने वाली दोनों बैठकों में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच गए। जबकि सोमवार से हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने वाला है।

केजरीवाल के प्रचार में उतरे पत्नी व बच्चे

चुनावी हलचल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका परिवार भी प्रचार में उतर गया है। रविवार को मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटी हर्षिता और बेटे पुलकित ने वेस्ट किदवई नगर के रिहायशी इलाके में जाकर प्रचार किया। परिवार हर घर जाकर डोर-टू-डोर प्रचार कर रहा है। इस दौरान पूरे परिवार ने आप की टोपी और हाथ में 'लगे रहो केजरीवाल' के पत्रक ले रखे थे। घर-घर जाकर परिवार के सदस्य यह प्रचार सामग्री वितरित कर रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि चुनाव प्रचार में सीएम का परिवार उतरा हो।

इससे पूर्व वर्ष 2013 व 2015 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया था। उस समय उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में होने के चलते प्रचार नहीं कर पाई थी, लेकिन बाकी सदस्यों ने प्रचार में पूरी भूमिका निभाई थी। सुनीता केजरीवाल ने आइआरएस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली है तो वह भी इस वर्ष चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। उनके बेटे पुलकित आइआइटी दिल्ली में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। जिस दिन छुट्टी होती है, वह उस दिन प्रचार करने आ जाते हैं। इसी तरह केजरीवाल की बेटी आइआइटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। वह पांच माह का अवकाश लेकर प्रचार कर रही हैं।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के (बाएं से) पुत्र पुलकित, पत्नी सुनीता और बेटी हर्षिता। सौजन्य : आम आदमी पार्टी

अकाली के साथ जदयू ने भी बढ़ाया दबाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण भाजपा बची हुई 13 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद-बादल) के साथ ही जनता दल यूनाइटेड (जदयू) भी इस बार दावेदारी जता रही है। वहीं, जननायक जनता पार्टी (जजपा) भी दिल्ली में भाजपा से सीट मांग रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सोमवार तक इस बारे में कोई फैसला ले लिया जाएगा।

दिल्ली विस चुनाव में भाजपा शिअद (बादल) के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। इस बार अकाली दो अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहा है।, दिल्ली भाजपा इसके पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि अकाली के साथ गठबंधन की घोषणा में देरी हो रही है। वहीं, बिहार में सहयोगी जदयू भी दिल्ली में चार सीटों पर दावेदारी जता रही है। कुछ भाजपा नेता इसके पक्ष में बताए जाते हैं। उनका तर्क है कि इसी वर्ष बिहार में भी विस चुनाव है। इसे ध्यान में रखकर जदयू के साथ गठबंधन होना चाहिए।

दिल्ली का रण संभालने दिग्गज मैदान में

पार्टियों की रणनीति

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। भाजपा के अधिकतर सूरमा मैदान में आ गए हैं। मंगलवार को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है, जिसके बाद चुनावी लड़ाई में और तेजी आएगी। भाजपा इसे धार देने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बूथ प्रबंधन में कहीं कोई खानी न रह जाए, इसके लिए कई राज्यों के संगठन महामंत्री दिल्ली में डेरा डालेंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री व पूर्व मंत्रियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इनकी निगरानी में चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती के साथ चलाने की तैयारी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर को कई माह पहले ही दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ ही केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय सह प्रभारी हैं। अब इनके सहयोग के लिए कई वरिष्ठ नेता दिल्ली के रण में उतरने वाले हैं। प्रत्येक नेताओं को एक-एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। वह अपने लिए निर्धारित लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।

संगठन महामंत्रियों के अनुभव का उठाया जाएगा लाभ

बूथ प्रबंधन पर भाजपा का जोर है। लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी ने विस चुनाव में भी 'बूथ जीतो चुनाव जीतो' का नारा दिया है। पिछले कई महीने से बूथ स्तरीय टीम गठित करने की कवायद चल रही थी। इस महीने के शुरू में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अब बूथ प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए हिमाचल के संगठन महामंत्री पवन राणा, हरियाणा के सुरेश भट्ट, मध्य प्रदेश के सुहास भगत और राजस्थान के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व महामंत्री भजन लाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला को दिल्ली बुलाया जा रहा है। इनके संगठन कौशल का लाभ उठाया जाएगा।

दूसरी ओर मोदी सरकार के कई मंत्री और पूर्व मंत्री भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत, अनुराग ठाकुर, मनसुख लाल मंडाविया, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह, मनोज सिन्हा सहित अन्य मंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक मंत्री व पूर्व मंत्री एक-एक लोकसभा में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाएंगे। पार्टी ने दिल्ली में पांच हजार चुनावी सभाएं करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्री व पूर्व मंत्री अपनी जिम्मेदारी वाले लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तैयार करेंगे।

नेशनल कैपिटल

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड के लिए विभिन्न दल अभ्यास कर रहे हैं। राजपथ पर परेड के अभ्यास के दौरान कदम से कदम मिलाकर एक साथ मार्च करते सेना के जवान। ध्रुव कुमार

परेड रिहर्सल के चलते होगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड की रिहर्सल 20 और 21 जनवरी को भी होगी। विजय चौक से इंडिया गेट होते हुए राजपथ पर सी-हैक्सागन तक आयोजित होने वाली रिहर्सल परेड के दौरान कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश बंद होगा और कई मार्गों पर डायवर्जन किया जाएगा। यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक राजपथ पर परेड की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा।

विजय चौक से इंडिया गेट तक भी राजपथ यातायात के लिए बंद रहेगा। इस दौरान यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों, सड़क अनुशासन का पालन करने और सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देश को मानने की अपील की है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे में आया नया पेच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के चौथे चरण (डासना से मेरठ के बीच 32 किमी) में नया पेच फंसता नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट के लिए आधा दर्जन गांवों की ग्रामसभा एवं सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी भूमि होने वाला पुनर्ग्रहण लटक सकता है। शासन की ओर से एनएचएआइ के लिए की जाने वाली जमीन के पुनर्ग्रहण से जुड़े प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पहले इतनी ही जमीन का इंतजाम आसपास किया जाना नियमानुसार जरूरी है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव महेंद्र सिंह की ओर से डीएम के अलावा मंडलायुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आरक्षित श्रेणी की भूमियों का श्रेणी परिवर्तन अथवा पुनर्ग्रहण उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम सभा में उतनी ही सामान्य श्रेणी की भूमि आरक्षित करके या धारा-101 के अंतर्गत विनिमय के माध्यम से ही पुनर्ग्रहीत की जा सकती है। भेजे गए प्रस्ताव में भूमियों का सिर्फ पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रस्ताव में उक्त धारा में वर्णित व्यवस्था के अनुरुप न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। विशेष सचिव ने एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार राजस्व अभिलेखों व मानचित्र सहित भेज दें।

प्रशासन ने अमराला, मुरादाबाद, जहांगीरपुर, पट्टी, चुड़ियाला व भोजपुर गांव की जमीन के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव 16 सितंबर 2019 को शासन को भेजा गया था। प्रोजेक्ट के चौथे एवं दूसरे चरण का काम शेष है।

सियासत

अगले सप्ताह से विभिन्न दलों का चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा, लेकिन कई पुराने चहेरे इसमें शामिल नहीं होंगे

चुनाव प्रचार में खलेगी कई दिग्गजों की कमी

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव के लिए नामाकंन प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा। इस बार भाजपा, आप व कांग्रेस के स्टार प्रचारों की सूची से कई नाम गायब रहेंगे। इनमें से कुछ नेता राजनीतिक रूप से अब ज्यादा सक्रिय नहीं हैं तो कई ने आप से नाता तोड़ लिया है। इन सब के बीच अहम बात यह है कि दिल्ली की राजनीति में दबदबा रखने वाले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसे नेताओं के चेहरे नहीं दिखेंगे।

भाजपा को इस चुनाव में अरुण जेटली व सुषमा स्वराज की कमी सबसे ज्यादा खलेगी। वहीं कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भूल पाना आसान नहीं होगा। वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2012 तक लगातार 15 साल दिल्ली की सियासत में शीला शीर्ष पर बनी रहीं। यह उनका करिश्माई व्यक्तित्व ही था कि दो विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कमान उनके हाथ सौंप दी थी। उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। वह लोकसभा चुनाव में भले ही दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई लेकिन वोट फीसद के मामले में वह दूसरे नंबर पर रही।

वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय को सौंपी थी। उसमें शीला दीक्षित का भी नाम शामिल था। इसी तरह भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 40 स्टार प्रचारों की सूची सीईओ कार्यालय को दी थी। इसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का नाम शामिल था, जो दिवंगत हो चुके हैं।

राजनीति में अब नहीं रही सक्रियता

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती का भी नाम था, जो अब राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। वहीं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होने के नाते चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे।

आप में नहीं रहे ये नेता

पिछले विधानसभा चुनाव में आप के स्टार प्रचारकों की सूची में कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष, आशीष खेतान, प्रोफेसर आनंद कुमार व एचएस फुलका का नाम शामिल था। योगेंद्र यादव व आशीष खेतान तो प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल थे, लेकिन अब ये सभी पार्टी में नहीं हैं।

30 वर्ष हो चुके हैं जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को हुए। कश्मीर से यह पलायन 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ था और लगभग चार लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था।

'वकीलों को कानून स्थापित करने में मदद करनी चाहिए'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वकीलों और छात्रों को समाज में कानून का शासन स्थापित करने के लिए कानूनी प्रणाली की मदद करनी चाहिए।

16वें केके लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट 2020 को संबोधित करते हुए रविवार को जस्टिस रमना ने कहा कि यह वकीलों का दायित्व है कि वह लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि समाज वकीलों का बहुत सम्मान करता है। वकीलों को भी अपने मुवक्किलों को सही तरीके से निर्देशित करना चाहिए।

इस कार्यक्रम में जस्टिस रमना मुख्य अतिथि थे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव सहाय इंडलॉ, ज्योति सिंह और आशा मेनन गेस्ट ऑफ ऑनर थे। असम की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ज्यूडीशियल एकेडमी ने मूट कोर्ट में पहला ईनाम जीता। जबकि डॉ. अंबेडकर यूनिवर्सिटी के चेन्नई स्कूल ऑफ एक्सलेंस को दूसरा पुरस्कार मिला। इस प्रतियोगिता में विभिन्न लॉ कालेजों की 60 टीमों ने भाग लिया।

शक्ति का केंद्र संघ नहीं संविधान : मोहन भागवत

जागरण संवाददाता, बरेली

- संघ प्रमुख ने कहा, हमारे पूर्वज एक हैं, विविधताओं के बाद भी सब यहीं रहते हैं, यही हिंदुत्व है
- जर्मनी, जापान और इजराइल हमारे साथ चले, मगर वे हमसे काफी आगे निकल गए

रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भविष्य का भारत विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में शक्ति का केंद्र सिर्फ संविधान है। कोई दूसरा शक्ति केंद्र हो, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो हम विरोध करेंगे। संविधान में देश के भविष्य की तस्वीर एकदम साफ है। वही प्रारंभ बताता है और गंतव्य भी।

बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 'भारत का भविष्य' विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संघ प्रमुख ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जो संविधान लिखा, हमें उसी पर चलना है। इतना जरूर हो सकता है कि समय बदलने पर कुछ ऊपरी फेरबदल करने पड़ें। व्यवस्था के अनुसार जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, वे ऐसा करेंगे।

उन्होंने कहा कि संविधान में भविष्य के भारत की परिकल्पना स्पष्ट थी, मगर सवाल यह है कि यह 70 सालों में पूरी क्यों नहीं हो सकी? जर्मनी, जापान और इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि वे तीनों देश भी हमारे साथ चले, मगर हमसे काफी आगे निकल गए। इस पर विचार करना होगा।

उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि इस देश के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी धर्म या जाति में बदलाव चाहते हैं। हमारे पूर्वज एक हैं, विविधताओं के बावजूद सब यहीं रहते हैं, यही हिंदुत्व है। जहां हिंदू नहीं रहे या हिंदू भावना खत्म हो गई, देश का वह हिस्सा आज अलग है। जब-जब हिंदुत्व कमजोर हुआ, तब-तब भारत की भौगोलिक स्थिति बदली है।

संघ प्रमुख ने कहा कि लोग भूलवश संघ को देखने के बजाय स्वयंसेवकों के कार्य देखने लगते हैं। स्वयंसेवक तो राजनीति से लेकर संस्कार तक, हर कार्य में आगे हैं। वह उनका स्वतंत्र कार्य है जोकि अच्छा है और राष्ट्रहित में है। हमारे स्वयंसेवक हैं, इसलिए आपस में बात और सहयोग भी करते हैं। लेकिन वो संघ नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संघ का कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। संघ का एक ही मतलब है-मनुष्य निर्माण।

सत्य पर आधारित विरोध का स्वागत : मोहन भागवत ने कहा कि यदि सत्य पर आधारित विरोध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वह हमारे सुधार के लिए होता है। संघ किसी के विरोध में नहीं चलता। संघ को जानना है तो करीब आइए, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर कहा कि वे गलतफहमी कर भीड़ एकत्र करना चाहते हैं।

दो बच्चों के कानून पर बोले, आम सहमति से बने नीति

संघ प्रमुख ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अपने पूर्व के कथन पर स्थिति स्पष्ट की। कहा कि मैंने यह नहीं कहा था कि दो बच्चों का कानून बने। कितनी संतान होनी चाहिए, इस सवाल पर मैंने कहा था कि जनसंख्या एक समस्या है मगर, यह साधन भी बन सकती है। इस पर नीति और सभी का मन बनाना चाहिए। इसके बाद उस नीति को लागू करना चाहिए ताकि किसी को कठिनाई न हो।

मुस्लिमों को शाखाओं में आने का न्योता

जागरण संवाददाता, बरेली

भविष्य का भारत विषय पर मोहन भागवत ने संघ का नजरिया रखने के साथ यह भी साफ किया कि हमें किसी की पूजा पद्धति को लेकर आपत्ति नहीं है। न ही जाति या संप्रदाय को लेकर संघ भेद रखता है। हिंदू शब्द संस्कृति का प्रतीक है। इस आधार पर भारत में रहने वाले सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं। उन्होंने मुसलमानों को न्योता दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने के लिए हमारी शाखाओं और कार्यक्रमों में शिरकत करें। फिर हमारे बारे में राय बनाना बेहतर होगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 91 मिनट के संबोधन में भागवत ने यह समझाने का प्रयास किया कि उनका संगठन चाहता क्या है? उन्होंने बताया कि हम सब भारत के लोग हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, स्वभाव है। जो टुकड़ा था, उसका नाम बदलने में देर नहीं लगी, वह पाकिस्तान है। विविधता के बीच मिलकर रहने का नाम ही हिंदू है। पूजा की पद्धति बदली है। संघ चाहता है कि सभी अपने पंथ के पक्के रहें, अपनी भाषा बोले, सद्भावना के साथ रहें। फिर भी विरोधी कहते हैं कि संघ वाले तुम्हारे शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि संघ को जानें और उसके स्वयंसेवकों को देखें कि वह किस तरह रहते हैं। आगरा में मुस्लिम स्वयंसेवक अजमेर का उदाहरण भी दिया।

सराहा गया संबोधन : भागवत को सुनने मुस्लिम भी पहुंचे थे। 'जागरण' ने उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी बात कही।

> जिस तरह संघ प्रमुख ने हिंदुत्व का मतलब समझाया है, उसे सुनकर गलतफहमी दूर हुई है। बहुत सी ऐसी बातें साफ हुईं, जिन्हें कुछ और तरीके से बताया गया था। संघ के ऐसे कार्यक्रमों में जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है।
> **-डॉ. फाजिल, सर्जन।**

> हिंदू किसी धर्म को इंगित नहीं करता। संघ प्रमुख ने साफ किया कि इस शब्द की व्याख्या अनेकता में एकता है। ख्वाजा गरीब नवाज और अमीर खुसरो भी इस बात का उदाहरण हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति को सामने रखकर ही इंसानियत को संदेश दिया।
> **-डॉ. एसई हुदा, फिजिकल ट्रेनर।**

न्यूज गैलरी

मुगलसराय बना अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल

चंदौली : रेलवे में मुगलसराय नाम अब इतिहास बन गया है। रेल मंत्रालय ने इस रेल मंडल का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल कर दिया है। अब मंडल में मुगलसराय के नाम वाले रेलवे के सभी कार्यालयों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। इससे संबंधित रेलवे बोर्ड की अधिसूचना रविवार को सार्वजनिक कर दी गई। पांच अगस्त 2018 को मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किए जाने के भाजपा सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने सियासी हचचल बढ़ा दी थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन समर्थन में आवाजें बुलंद हुई तो विरोधियों को शांत होना पड़ा। हालांकि नाम परिवर्तन शहर तक सिमट कर रह गया। नगर और जंक्शन का नाम तो बदल दिया गया लेकिन मुगलसराय रेल मंडल कागजों में कायम रहा। (जासं)

एचसीएस की परीक्षा में शामिल हुए छह नए विषय

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा जिन छह विषयों को आइएएस और संबद्ध सेवाओं की परीक्षाओं के लिए शामिल किया गया है, उन्हें अब एचसीएस (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन छह विषयों को शामिल किया गया है, उनमें एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी और स्टेटिस्टिक्स हैं। इसके लिए एचसीएस नियम 2008 के अनुबंध-दो के नियम 11 के अनुसार संशोधन किया जाएगा और उसके बाद इन पदों की भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से हरियाणा लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ फिर से अधिसूचित किया जाएगा। (राब्यू)

कर्ज नहीं, मर्ज है पंजाबियों की जान पर भारी

जालंधर : पंजाब में कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या लगातार सुर्खियों में रही है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों की मानें तो यहां लोग बीमारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में पंजाब में कुल 1714 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 722 लोगों ने बीमारी से तंग आकर जान दी। यह आंकड़ा देश भर में सर्वाधिक यानी 42.1 फीसद रहा, जबकि देश के 28 राज्यों व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलकर 57.9 लोगों ने बीमारी के कारण अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इसी अवधि में कर्ज के कारण पंजाब में 323 किसानों ने खुदकुशी की। यानी इससे दो गुना से भी ज्यादा संख्या में लोगों ने बीमारी से तंग आकर जान दी। (जासं)

गैर-जरूरी शोध पर अब लगेगा ब्रेक, मंजूरी जरूरी

बड़ा फैसला ▶ शोध की मंजूरी से पहले देना होगा उपयोगिता का ब्यौरा

विश्वविद्यालयों से भी मांगा गया अब तक हुए शोध का ब्यौरा

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

शोध की गुणवत्ता के साथ अब उसकी उपयोगिता को भी परखा जाएगा। यानी अब किसी भी नए शोध को मंजूरी तभी मिलेगी, जब वह उपयोगिता के मापदंड पर खरा उतरेगा। सरकार की यह कोशिश देश भर में होने वाले ऐसे सभी शोध पर ब्रेक लगाने को लेकर है, जो सिर्फ शैक्षणिक दिखावे के लिए हो रहे हैं। समाज या उद्योगों के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। सरकार की इस पहल को शोध के क्षेत्र में एक और बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) फिलहाल इसे लेकर गाइड लाइन बनाने में जुटा हुआ है, जो जल्द ही सामने आ सकती है। हालांकि इससे पहले सरकार ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में अब तक हो चुके शोध का ब्योरा भी जुटाने के लिए कहा है। यूजीसी ने इस काम को भी शुरू कर दिया है। हालांकि इसका मकसद यह पता लगाना है कि अब तक जो भी शोध हुए हैं, वह कितने उपयोगी रहे हैं। समाज और उद्योग जगत को इससे क्या लाभ मिला है? यूजीसी ने यह सारी कवायद उस समय शुरू की है, जब विश्वविद्यालयों में पिछले पांच सालों में शोध से जुड़े मामले में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014-15 में देश में जहां कुल 21 हजार शोध (पीएचडी) हुए थे, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 41 हजार शोध हुए हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शोध को बढ़ावा देने के साथ उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी फोकस जरूरी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फाइल

नए शोध को लेकर यूजीसी जो नई गाइड लाइन तैयार कर रहा है, उसके तहत किसी भी नए शोध के लिए पहले उसकी सामाजिक, औद्योगिक उपयोगिता को परखा जाएगा। इसमें खरा उतरने के बाद ही शोध को मंजूरी दी जाएगी। शोध को बढ़ावा देने में जुटी सरकार का जोर इस बात पर है कि शोध का मकसद समाज व आम जनजीवन की समस्याओं को आसान बनाने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शोध की गुणवत्ता को परखने के लिए यूजीसी पहले से ही सख्त नियम-कायदे तैयार कर चुकी है। इसके तहत किसी पुराने शोध का दस फीसद से ज्यादा ब्योरा मिलने उसे फिर से उसे खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही उसे फिर से लिखनी होगी। इस नियम के तहत साठ फीसद से ज्यादा नकल पाए जाने पर शोध को ही रद्द करने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी की इस गाइड लाइन से गुणवत्ता में काफी सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी उपयोगिता के पैमाने पर यह खरी नहीं उतर पा रही थी। यही वजह है कि इसके लिए एक नई गाइड लाइन पर तेजी से काम किया जा रहा है।

मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत पांच को क्लीनचिट

जागरण संवाददाता, बागपत : पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत पांच आरोपितों को क्लीनचिट दे दी है। पुलिस ने सिर्फ कुख्यात सुनील राठी को ही आरोपित माना है। उसके खिलाफ पुलिस पहले ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया है। वहीं, कुछ सवाल अब भी अनसुलझे रह गए हैं।

बड़ौत के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित व उनके भाई नारायण दीक्षित से वर्ष 2017 में झांसी जेल में बंद मुन्ना बजरंगी के नाम से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी तथा उनके गांव गाधी में आकर बाइक सवार बदमाशों ने धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुन्ना बजरंगी के एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुन्ना को बी-वारंट पर नौ जुलाई 2018 को अदालत में पेश करने के लिए आठ जुलाई को पुलिस उसको झांसी जेल से लेकर बागपत आई थी। पुलिस ने रात को बजरंगी को जेल में दाखिल कर दिया था। नौ तारीख की सुबह जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। कुख्यात सुनील राठी ने हत्या करना कबूल किया था। आरोपित सुनील राठी के खिलाफ खेकड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, रिटायर्ड डिप्टी एसपी जेएम सिंह, प्रदीप उर्फ पीके, महराज सिंह व विकास उर्फ राजा पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी।

भाजपा अध्यक्ष के रूप में आज हो सकती है नड्डा की ताजपोशी

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को सोमवार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। संभावना है कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जगह निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं।

नड्डा के नामांकन के दौरान पार्टी के शीर्ष नेता, कई केंद्रीय मंत्री व भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री पार्टी मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे। माना जाता है कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पसंद हैं। संगठन का लंबा अनुभव, छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन और स्वच्छ छवि भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नड्डा की दावेदारी को मजबूत करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संगठनात्मक चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल होंगे। जरूरी हुआ तो मंगलवार को चुनाव कराया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10-12:30 बजे तक नामांकन किया जाएगा। सोमवार को ही नामांकन पत्रों की जांच होगी। सूत्र बताते हैं कि शाम तीन बजे नड्डा को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह का साढ़े पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार 2.0 में शाह के गृहमंत्री बनने के बाद भाजपा ने उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की कवायद शुरू कर दी थी। कारण है कि पार्टी में 'एक व्यक्ति, एक पद' की परंपरा रही है। नड्डा को गत वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान के प्रभारी थे। वहां बसपा-सपा के गठबंधन के बावजूद भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भाजपा को प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर जीत मिली। नड्डा मोदी सरकार 1.0 में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं।

जेपी नड्डा। फाइल

शाह ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ की बैठक : संगठनात्मक चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार की शाम केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि, कुछ भी अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें पार्टी नेताओं को संगठनात्मक चुनाव के बारे में जानकारी दी गई।

क्रिकेट की पिच पर मुख्य न्यायाधीश

देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद बोबडे रविवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दो दिवसीय दौरे पर नागपुर पहुंचे न्यायमूर्ति बोबडे ऑल जज इलेवन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से खेले जा रहे फ्रेंडली का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी टीम ऑल जज इलेवन के लिए 18 रन बनाए। यह मैच 15 ओवर का था। यह मैच में किसी खिलाड़ी की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत रन था। हालांकि ऑल जज इलेवन को हार का सामना करना पड़ा। एएनआइ

'विकास दर में कृत्रिम इजाफे न करे सरकार'

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने सरकार द्वारा आर्थिक आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी शामिल करने की कथित कोशिशों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विकास दर में 'कृत्रिम इजाफे' की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि मौजूदा आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। सिंघवी ने कहा, 'अगर यह सकारात्मक कवायद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, 4.9 फीसद विकास दर को बढ़ाने के लिए कोई बनावटी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।'

मप्र में बिना अवकाश लिए पीएचडी कर रहे आइएएस, आइपीएस

अभिषेक दुबे, भोपाल: मध्य प्रदेश के आइएएस, आइपीएस, आइएफएस समेत कई अधिकारी अपने विभाग से अवकाश लिए बिना बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) से पीएचडी कर रहे हैं। बीयू प्रशासन ऐसे अधिकारियों की पीएचडी रिसर्च को निरस्त करने जा रहा है। उन्हें कोर्स वर्क की कक्षाओं में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बीयू ने पिछले दिनों पीएचडी की अनुमति देने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इसमें आइएएस, आइपीएस, आइएफएस समेत प्रदेश के कई अधिकारी शामिल हुए थे। कुछ अधिकारियों ने प्रवेश परीक्षा पास भी कर ली है। अब यह अधिकारी कोर्स वर्क की कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। बीयू प्रशासन को शिकायत मिली है कि यह अधिकारी स्टडी लीव लिए बिना पीएचडी की कोर्स वर्क परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। नियमानुसार यह सही नहीं है। वे विभाग से वेतन भी ले रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। यदि विभाग ऐसे अधिकारियों की पीएचडी की अनुमति निरस्त करता है तो उसके बाद उन उम्मीदवारों को पीएचडी का मौका मिल सकेगा, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा-जनता के पैसे से न हो नेताओं का प्रचार

- राज्यों से कहा-विज्ञापनों की सामग्री की निगरानी के लिए बनाएं समिति
- ढीले-ढाले रवैये पर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई

नई दिल्ली, आइएएनएस : राज्य सरकारों के संदर्भ में यह शिकायत आम है कि वे जनता के पैसे से सत्ताधारी दल के नेताओं का महिमामंडन करती हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने राज्यों से कहा है कि उन्हें यह सिलसिला बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें विज्ञापनों की सामग्री की निगरानी के लिए नियामकों की नियुक्ति करनी चाहिए। पैनल ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें इस मामले में खुद अपने स्तर पर समिति नियुक्त करने के इच्छुक नहीं हैं तो वे केंद्र सरकार की तीन सदस्यीय सामग्री निगरानी समिति को इस बारे में अधिकार दे सकते हैं।

पैनल का यह कदम इस लिहाज से अहम है, क्योंकि दिल्ली में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विगत में दिल्ली, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में सरकारी धन से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के प्रचार की शिकायतें सामने आई थीं। इसी सिलसिले में तीन सदस्यीय केंद्रीय पैनल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि राज्यों को जल्दी-से-जल्दी विज्ञापन की सामग्री के लिए नियामकों की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया जाए। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इससे राज्यों को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) ने राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार की ओर से 15100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के सिलसिले में दिए गए विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की फोटो प्रकाशित किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा था।

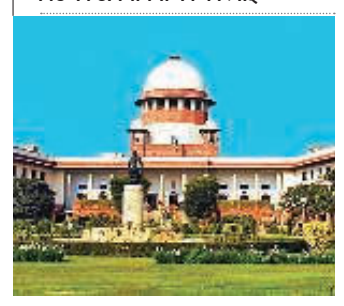
सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इसके जवाब में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गत वर्ष जवाब दिया कि विज्ञापन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनुमति से प्रकाशित हुआ था। राजस्थान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियम-कायदों का पालन नहीं किया गया।

राजस्थान ने हालांकि कंटेंट रेगुलेशन कमेटी के गठन को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत की अध्यक्षता वाली सीसीआरजीए ने इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय से फिर से राज्य सरकार से यह मसला उठाने या फिर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला ले जाने के लिए कहा।

परीक्षा पे चर्चा

बोर्ड परीक्षाओं के पहले संवाद का यह तीसरा साल है। प्रधानमंत्री ने इस तरह की चर्चा की शुरुआत 2018 में की थी

मोदी देंगे परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 'परीक्षा पे चर्चा' में जुटेंगे देशभर के दो हजार से ज्यादा स्कूली छात्र, 50 दिव्यांग छात्र भी होंगे शामिल
- 15 लाख से ज्यादा स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में देशभर के छात्रों को तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने की टिप्स देंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दो हजार बच्चों को आमंत्रित किया गया है। इनमें करीब 50 दिव्यांग छात्र भी शामिल होंगे। इनमें से एक हजार छात्रों का चयन देशभर से प्रतिस्पर्धा के जरिये किया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे पीएम से सीधे पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और प्रधानमंत्री बच्चों के सवालों का जवाब भी देंगे।

मोदी का छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं के पहले संवाद का यह तीसरा साल है। पीएम ने इस तरह की चर्चा की शुरुआत 2018 में की थी। तब से हर साल यह होती आ रही है। किसी भी देश में स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री के इस तरह के संवाद का यह पहला मामला है। इसे लेकर स्कूली बच्चों में भारी उत्साह रहता है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया सकता है कि इस कार्यक्रम में चयन के लिए जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी, उसमें देशभर के करीब तीन लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से करीब दो लाख बच्चों से प्रधानमंत्री से पूछने के लिए अपने सवाल भी भेजे थे। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर छात्रों से 20 जनवरी को सुबह 11 बजे होने वाली परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल

साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम एक बार फिर परीक्षा से जुड़े सभी विषयों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। खासकर तनाव मुक्त होकर परीक्षा में कैसे खुशी-खुशी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस चर्चा का देश भर के करीब 15 लाख स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रसारण करने का दावा किया है।

चयनित बच्चों को दिखाया गया वार मेमोरियल और लाल किला

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देशभर से चयनित किए गए एक हजार बच्चों को इस बीच रविवार को वार मेमोरियल और लाल किला का भ्रमण कराया गया। हालांकि छात्रों का सबसे ज्यादा उत्साह पीएम से सीधे रूबरू होने को लेकर है। खासबात यह है कि इस कार्यक्रम में पहली बार छात्र एंकरिंग भी करते दिखेंगे।

आइआइटी बीएचयू ने अपनाई हिंदी, विभागों को आदेश जारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : हिंदी के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव संबंधी विवाद को लेकर बीएचयू परिसर से शहरभर में पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। दूसरी ओर नए साल पर आइआइटी बीएचयू के सभी कार्यालयों को आदेश जारी हुआ है कि समस्त कार्यालयी कार्य हिंदी में ही किए जाएं। यह आदेश राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) में दिए गए प्रावधानों के तहत जारी हुआ है। पहले भी हिंदी पखवारा या दीक्षांत समारोह का हिंदी में संचालन, कई बार देखा गया है कि आइआइटी बीएचयू ने हिंदी को लेकर काफी सक्रियता दिखाई है। संस्थान में कुलसचिव कार्यालय का राजभाषा प्रकोष्ठ छुट्टी, यात्रा रियायत, भविष्य निधि जैसे 15 मानक आवेदनों का द्विभाषी प्रारूप तैयार कर हिंदी का विस्तार कर रहा है। कुलसचिव डॉ. शुभेंदु प्रकाश माथुर ने कहा कि विगत वर्षों में कार्यालय में हिंदी कामकाज को लेकर काफी प्रगति हुई है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

25,743 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं देश में, जबकि आवश्यकता 29,337 की है। इस तरह 22 फीसद पीएचसी की कमी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 20 जनवरी 2020

साई बाबा के जन्मस्थान पर विवाद को लेकर शिरडी बंद

- पथरी को साई बाबा का जन्मस्थान बताने पर शुरू हुआ विवाद
- शिरडी के निवासी सीएम उद्धव ठाकरे से बयान वापस लेने की कर रहे हैं मांग

शिरडी, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा साई बाबा के जन्मस्थान को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में रविवार को शिरडी बंद रहा। इसके तहत दुकान और भोजनालय बंद रहे और सड़कों से वाहन भी नदारद रहे। यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब सीएम उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पथरी को साई बाबा का जन्मस्थान बताते हुए उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देने का एलान किया था।

शिरडी के निवासी और स्थानीय नेता मुख्यमंत्री से उनका बयान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और अहमदनगर के जिला प्रशासन ने बताया कि मंदिर हालांकि खुला हुआ है और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जाने दिया जा रहा है। प्रसादालय और मंदिर का रसोईघर भी खुला हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रसादालय और लड्डू बिक्री केंद्र पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई।

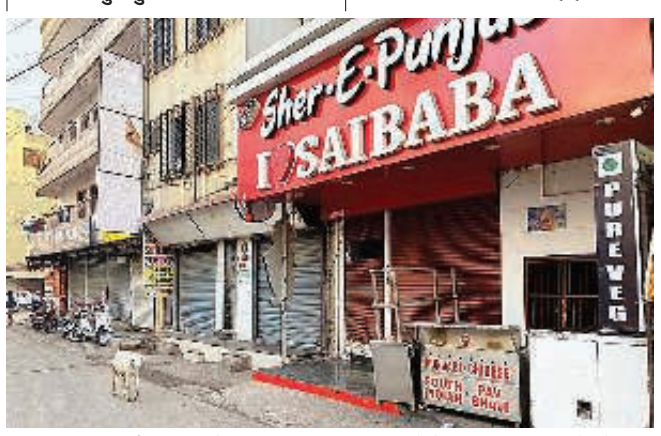

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साई बाबा के जन्मस्थान को लेकर दिए बयान के विरोध में रविवार को शिरडी में बाजार बंद रहे। एएनआइ

शिरडी से शिवसेना के लोकसभा सदस्य सदाशिव लोखंडे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व स्थानीय भाजपा विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी बंद का समर्थन किया है। लोखंडे ने कहा, 'मैं साई भक्त पहले हूं और सांसद बाद में। मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। साई बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे। उन्होंने कभी अपनी जाति या धर्म के बारे में नहीं बताया। इसलिए उनका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा।' लोखंडे ने कहा कि वे देखेंगे कि किस तरह मुद्दे का समाधान किया जा सकता है और बंद को खत्म किया जा सकता है।

बंद को सफल बताते हुए स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता सचिन तांबे-पाटिल ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, रेस्तरां पूरी तरह बंद रहे। ऑटो रिक्शा और निजी वाहन भी सड़कों पर नहीं दिखे। उन्होंने दावा किया कि शहर के अलावा आसपास के 25 गांवों में भी बंद पूरी तरह से सफल रहा।

इस बीच, साई बाबा के जन्मस्थान को लेकर उठे विवाद के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि उद्धव ठाकरे सोमवार की बैठक में साई बाबा के जन्मस्थान पर उठे विवाद पर चर्चा करेंगे।

प्रज्ञा का दावा, धमकी भरा पत्र भेजने वाला आइएस आतंकी

नईदुनिया, भोपाल

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को दावा किया कि उन्हें धमकी भरा पत्र और संदिग्ध पाउडर भेजने वाले आरोपित का संबंध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से है और संदिग्ध पाउडर में विस्फोटक मिला है। साध्वी ने भिंड में स्पष्ट किया कि अभी पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। इस बीच, मामले की जांच कर रहा पुलिस का आतंकरोधी दस्ता (एटीएस) सोमवार को पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है।

सूत्रों के मुताबिक एफएसएल जांच व विशेषज्ञों से चर्चा में सामने आया है कि पाउडर में कोई विस्फोटक मिलाया गया है। उर्दू में लिखे गए पत्र की भाषा के आधार पर जांच को विभिन्न आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एटीएस ने सांसद को धमकी मिलने के बाद से पुलिस के समानांतर जांच शुरू कर दी थी। इसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए पुणे के खड़की के स्वामी रामचंद्र अय्यर का पता लिखे जाने के पीछे के कारणों को भी एटीएस तलाश रही है।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फाइल

आरोपित नांदेड़ का रहने वाला

एटीएस ने अभी आरोपित के बारे में कोई जानकारी नही दी है, लेकिन यह नांदेड़ का सैयद अब्दुल रहमान हो सकता है, जिसके हिरासत में लिए जाने की खबरें शनिवार को आई थी। संभावना है कि सोमवार को उसे मीडिया के सामने पेश किया जा सकता है।

कैंपस में सीआइएसएफ की तैनाती का निर्णय वापस ले सकता है विश्वभारती विवि

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल के वीरभूम जिले के शांतिनिकेतन स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय ने कैंपस की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल सीआइएसफ को तैनात करने का फैसला लिया था। इसके लिए विवि प्रशासन ने केंद्र सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से लिखित अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि विश्वभारती विवि सीआइएसफ की तैनाती नहीं चाहता। इसके पीछे सीआइएसएफ की तैनाती पर होने वाला भारी-भरकम खर्च को वजह बताई जा रही है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने परिसर में सीआइएसएफ की तैनाती की मांग करने वाला विश्वभारती विवि अब इस योजना को वापस ले सकता है क्योंकि अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती पर आने वाला खर्च विश्वविद्यालय के सुरक्षा बजट से कहीं अधिक है। सूत्रों के अनुसार, सीआइएसएफ द्वारा शांतिनिकेतन परिसर के सुरक्षा ऑडिट में अनुमानित खर्च विवि के सुरक्षा बजट से चार गुना अधिक आया है।

न्यूज गैलरी

उत्तराखंड में संस्कृत में भी होंगे रेलवे स्टेशनों के नाम

देहरादून : उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों पर लगे साइन बोर्ड पर अब संस्कृत में भी स्टेशनों का नाम अंकित किया जाएगा। अब तक स्टेशनों के नाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अंकित हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्टेशनों पर लगे बोर्ड पर उस राज्य की पहली अथवा दूसरी राजभाषा में भी नाम अंकित किया जाता है। उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी संस्कृत है। इसके लिए मुरादाबाद डिवीजन की वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। मुरादाबाद डिवीजन के मंडलीय रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि रेलवे ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। अब उत्तराखंड सरकार को पत्र भेज इसकी अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि रेलवे के नियमों के तहत ही यह निर्णय लिया गया है। (जासं)

सत्ता में आए तो रद होगा देवस्थानम एक्ट : प्रीतम

उत्तरकाशी : उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन कानून का विरोध कर रही कांग्रेस ने एलान किया है कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो इस कानून को रद कर दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यह कानून तीर्थ पुरोहितों के हक-हकूकों पर चोट है। उन्होंने प्रदेश सरकार के तीन साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए कहा कि फरवरी से पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभाओं और धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगी। उत्तरकाशी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस ऑलवेदर रोड का नाम भाजपा ले रही है वो भी संप्रग सरकार की देन है। (जासं)

आज से चार दिवसीय दौरे पर उत्तर बंगाल जाएंगी ममता

कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को चार दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर जाएंगी। सचिवालय नवान्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर बाद यहां से रवाना होंगी। इसी दिन वह अठारोखाई मैदान से उत्तर बंगाल के आठ जिलों में एक साथ नौवां उत्तर बंग उत्सव का शुभारंभ करेंगी। उत्तर बंग उत्सव के दौरान टेबल टेनिस कोच भारती घोष समेत उत्तर बंगाल के कुल नौ व्यक्तियों को बंग रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं, उत्तर बंगाल के प्रत्येक जिले से 10-10 जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, 22 जनवरी को दार्जिलिंग में सीएए तथा एनआरसी के विरोध में आयोजित रैली में भाग लेकर 23 को दार्जिलिंग पहाड़ पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह में शामिल होंगी। (जासं)

भाजपा को मंजूर नहीं प्रदीप यादव की शर्तें

कवायद जारी ▸ भाजपा में झाविमो के विलय की उलटी गिनती

प्रदीप की नजर भाजपा विधायक दल के नेता पद पर

राज्य ब्यूरो, रांची

भाजपा में झाविमो के विलय की कवायद में जुटे बाबूलाल मरांडी को उनके खास सिपहसालार प्रदीप यादव का साथ मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल, प्रदीप यादव कुछ खास शर्तों पर भाजपा में वापसी करना चाहते हैं, जबकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह कतई मंजूर नहीं है। प्रदीप यादव की नजर भाजपा विधायक दल के नेता पद पर है। उनकी चाहत है कि विलय के पूर्व इस पर सहमति बन जाए तो वे साथ देने को तैयार हैं। इसके अलावा अपने करीबी नेताओं के लिए भी वे स्थान चाहते हैं। उधर, भाजपा ने बातचीत की प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थ को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रुचि बाबूलाल मरांडी में है और प्रदीप यादव की शर्तों को मानने का कोई आधार नहीं। भाजपा की चाहत है कि बाबूलाल मरांडी आकर दल का नेतृत्व झारखंड में संभालें। प्रदीप यादव अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन शर्त के साथ उन्हें संगठन में लेना संभव नहीं है।

झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और विधायक बंधु तिर्की पर कांग्रेस डोरे डाल रही है। जल्द ही दोनों की मुलाकात कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो सकती है। झाविमो के भाजपा में विलय को लेकर चर्चाओं के बीच प्रदीप यादव की बात बनती नहीं दिख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस को लग रहा है कि प्रदीप यादव को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। प्रदीप यादव के लिए कांग्रेस ने संताल परगना के एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार प्रदीप यादव अगर पार्टी में आते हैं, तो उनका स्वागत होगा, लेकिन इसकी संभावना उतनी नहीं है, जितनी बंधु तिर्की के कांग्रेस में आने की। बंधु तिर्की के लिए पार्टी पहले भी तैयार बैठी थी और उन्हें चुनाव के पूर्व बेल मिल गया होता, तो इस बात की भी संभावना थी कि वे कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरते।

प्रदीप यादव फाइल

बाबूलाल को बहुत वक्त नहीं देगी भाजपा : बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी के भीतर के आंतरिक गतिरोध पर जल्द से जल्द काबू पाना होगा। भाजपा उनकी घर वापसी की इच्छुक तो है, लेकिन इन्हें बहुत अधिक वक्त नहीं दिया जाएगा। मरांडी को इस बाबत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सूचना दे दी गई है। स्पष्ट है कि भाजपा झारखंड में अपने संगठन को बहुत दिनों तक लटकाना नहीं चाहती। सोमवार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्ष के तौर पर विधिवत ताजपोशी हो जाएगी। इसके बाद उन राज्यों में संगठन का खाका नए सिरे बुना जाएगा जहां संगठन की दृष्टि से चुनाव लंबित हैं। झारखंड में भाजपा की कार्यकारिणी का कार्यकाल अगस्त में ही समाप्त हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने भी विस चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, फिलहाल नए अध्यक्ष के कमान संभालने तक उन्हें पद पर बनाए रखा गया है। नड्डा के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यसमिति का गठन किया जाएगा और प्रदेशस्तर पर भी। इस बीच मरांडी यदि अपनी पार्टी का विधिवत विलय भाजपा में कर लेते हैं तो उनकी संगठन में भूमिका तय करने में आसानी होगी। यदि विलंब करते हैं तो भाजपा उनका इंतजार नहीं करेगी।

पद्मावती के समर्थन और गंगा की अविरलता के लिए 30 से पद यात्रा : राजेंद्र

राज्य ब्यूरो, पटना : जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने बिहार के लोगों से आह्वान किया है कि वे नालंदा की बेटी साध्वी पद्मावती के समर्थन और गंगा की अविरलता के लिए आयोजित होने वाली पद यात्रा में शामिल हों। पद यात्रा 30 जनवरी से प्रस्तावित है। राजेंद्र सिंह रविवार को राजकीय अतिथिशाला में प्रेस से बात कर रहे थे।

36 दिनों से आमरण अनशन पर हैं साध्वी पद्मावती : राजेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां ब्लॉक के मलम्मा गांव बेटी साध्वी पद्मावती पिछले 36 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैं। उनका यह प्रयास इसलिए है कि बिहार तक गंगा का जल अपनी पूरी अविरलता के साथ आए। उन्होंने कहा कि 2009 में भागीरथी को आजादी मिली, लेकिन गंगा आज भी आजाद नहीं है। गंगा सिर्फ भागीरथी से नहीं बनती, गंगा अलकनंदा और मंदाकिनी को मिलाकर बनती है, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी पर चार बांध बनाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में बिहार को गंगा का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा।

जंतर-मंतर पर चार फरवरी को मिलें: राजेंद्र सिंह ने कहा कि साध्वी पद्मावती गंगा का पानी बिहार को मिले इसके लिए आमरण अनशन कर रही हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह वक्त है कि बिहार के लोग उनके समर्थन में आगे आएं और 30 जनवरी से दिल्ली तक पदयात्रा करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर चार फरवरी को लोग मिलें और केंद्र सरकार से साध्वी के समर्थन में अलकनंदा और मंदाकिनी पर बांध निर्माण रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें।

तीन लाख से अधिक गांवों में रामोत्सव मनाएगी विहिप

- शोभायात्रा के साथ सभा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे

25 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजन, कारसेवक होंगे सम्मानित

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के जरिये अयोध्या में राममंदिर निर्माण का रास्ता खुलने के बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) देश के तीन लाख से अधिक गांवों में 'रामोत्सव' मनाएगी। यह महोत्सव 25 मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा। विहिप की अगुआई में इस उत्सव में खासकर उन गांवों में शोभायात्रा, सभा व हनुमान चालीसा के साथ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा, जहां से मंदिर निर्माण के लिए रामशिलाएं अयोध्या गई थीं। इसी तरह 18 करोड़ से अधिक उन कारसेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा, जो इस आंदोलन से जुड़े थे। इसके साथ ही उनसे एक बार फिर अयोध्या आकर मंदिर निर्माण में सेवा का आग्रह किया जाएगा।

विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि सैकड़ों वर्षों के संकल्प की सिद्धी का समय आ गया है। यह उत्सव का विषय है। इसलिए इसमें देश-विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण के लिए जल्द ही ट्रस्ट गठित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रस्ट से आग्रह होगा कि वह मंदिर निर्माण का शुभारंभ रामनवमी से करे। रामनवमी रामोत्सव के मध्य ही 2 अप्रैल को पड़ रहा है। इसी तरह केंद्र सरकार से आग्रह है कि मंदिर निर्माण के लिए धन आवंटित करने की जगह रामभक्तों को ही यह जिम्मेदारी और कारसेवा का मौका दे, जिससे कि हर हिंदू को मंदिर निर्माण में हाथ लगाने का मौका मिले।

मंगलुरु में पिछले वर्ष 27 से 29 दिसंबर तक हुए विहिप के केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक में इस उत्सव का खाका तैयार किया गया था, जबकि 20 जनवरी से प्रयागराज में प्रारंभ होने जा रहे दो दिवसीय संत सम्मेलन में इस उत्सव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि पौने तीन लाख गांव से शिलालेख आए थे। उन गांवों के साथ ही हम देश के कमोबेश सभी गांवों में जाएंगे। मंदिर, चौपाल और पार्कों में धूमधाम से रामोत्सव आयोजित होंगे। इनमें बौद्ध, जैन व सिख समाज को भी जोड़ा जाएगा। पिछले वर्ष नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। जिसमें राममंदिर निर्माण के लिए केंद्र को तीन माह में ट्रस्ट के गठन के साथ मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश था।

सावित्री बाई फुले ने बनाई कांशीराम बहुजन समाज पार्टी

- बहराइच की पूर्व सांसद ने भाजपा और कांग्रेस छोड़ पकड़ी अपनी राह
- उत्तर प्रदेश की हर सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भाजपा के बाद कांग्रेस भी छोड़ चुकीं पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले ने अब राजनीति की अलग राह पकड़ ली है। जो अनुसूचित जाति का वोटबैंक बसपा का मूल जनाधार माना जाता है, उसी को लक्ष्य बनाकर सावित्री बाई ने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की घोषणा की है।

भाजपा के टिकट से जीतकर बहराइच की सांसद बनीं सावित्री बाई फुले ने पार्टी में रहते हुए ही बगावत कर दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ीं, जिसमें वह हार गईं। पूर्व सांसद का कांग्रेस से भी जल्द ही मोहभंग हो गया। पिछले दिनों कांग्रेस का हाथ उन्होंने यह कहकर झटक दिया कि यह पार्टी भी भाजपा की तरह अनुसूचित जाति की विरोधी विचारधारा वाली है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मतभेद की बात कही थी। तभी सावित्री बाई ने कह दिया था कि वह जल्द नई पार्टी बनाएंगी। लिहाजा, रविवार को लखनऊ स्थित रवींद्रालय में नमो बुद्धाय जनसेवा समिति का सम्मेलन बुलाया गया है। इसी में पूर्व सांसद ने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की घोषणा की। दावा किया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से समर्थक शामिल हुए। नवघोषित पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री बाई का कहना है कि उनका उद्देश्य कांशीराम के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश की हर सीट पर लड़ेगी।

सावित्री बाई फुले फाइल

10 दिन तक इंतजार करूंगा, मांगें नहीं मानीं तो फिर दूंगा धरना : गोयल

राज्य ब्यूरो, भोपाल : अपने विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को पट्टे नहीं मिलने और कुछ अन्य मुद्दों पर अपनी ही सरकार के नौकरशाहों से खफा मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल रविवार को अपने गृह क्षेत्र ग्वालियर लौट गए। लौटते-लौटते गोयल ने एक बार फिर चेतावनी भरे शब्दों में कहा, '10 दिन और इंतजार करूंगा, अगर मेरी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धरना दूंगा।' उनका कहना है कि सरकार के मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है और उन्होंने मांगों पर आश्वासन दिया है।

गोयल 2014 में भाजपा सरकार के समय हुए गरीबों के सर्वे को निरस्त करने, अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेताओं को अपमानित किए जाने और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की संवादहीनता को समाप्त कर 15 दिन में संभागवार विधायकों के साथ सीएम विकास कार्यों पर समीक्षा करने की मांगों को लेकर शनिवार को भोपाल में विधानसभा के सामने धरने पर बैठे थे। इसके बाद कमलनाथ सरकार सक्रिय हुई थी। यह कहा गया कि गोयल अपने जिले के एडीएम अनूप सिंह से नाराज हैं और वे उन्हें हटवाना चाहते हैं।

कैप्टन बनाम बाजवा का मुद्दा आज उठेगा सोनिया के सामने

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा के बीच चल रहे वाक युद्ध का मुद्दा सोमवार को कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठेगा। कैप्टन सोनिया से मिलने के लिए रविवार दोपहर करीब 11.50 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री बाजवा के मुद्दे के अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पहले अकेले ही सोनिया से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी और प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ के साथ मिलने को कहा गया। पंजाब में सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली इस बैठक पर टिक गई हैं। पिछले कुछेक दिनों से कांग्रेस में जिस प्रकार से उठापटक तेज हुई है और बाजवा ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला है उससे पार्टी का पारा खासा चढ़ा हुआ है।

बाजवा कैप्टन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि विधायकों व पार्टी हाईकमान को कैप्टन से मुक्ति पा लेनी चाहिए। इसके बाद कई कैबिनेट मंत्रियों ने बाजवा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी। चूंकि बाजवा राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए प्रदेश स्तर पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उससे सरकार की भी खासी भद्द पिट रही है।

जाखड़ भी उठा चुके हैं सरकार पर सवाल

पंजाब सरकार की छवि लोगों में अच्छी नहीं है, इसलिए पार्टी के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी पिछले कुछेक दिनों से लगातार सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठा रहे हैं। शनिवार को तो उन्होंने प्री बजट बैठक में यहां तक कह दिया कि लोगों ने हम पर विश्वास करके क्या गलती कर दी? ऐसे में सोमवार को होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

गणतंत्र दिवस परेड में दिख सकती है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की झांकी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) अपनी झांकी पेश कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के तत्वावधान में केपीटी इस झांकी में समृद्ध इतिहास, बंदरगाह के आधुनिक मशीनीकृत रूपांतरण जैसी अनूठी विशेषताएं प्रदर्शित करेगा। साथ ही जब झांकी राजपथ से गुजरेगी तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का वह गीत भी बजाया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह केपीटी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लांच किया था। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विषय 'ग्लोरियस पास्ट वाइब्रेंट फ्यूचर' के पास लिए मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस पर 23 जनवरी तक कोई नतीजा आने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किए जाने की बात कही गई थी। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के पास दो बार भेजा गया।

दूसरी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया गया। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे बंगाल का अपमान बताया। अब केपीटी की झांकी को जगह मिलने की उम्मीद के बीच राज्य के लोगों में खुशी है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उक्त दौरे के दौरान केपीटी का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया था। पीएम ने केपीटी के समृद्ध इतिहास का बखान करते हुए कहा था कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने सिर्फ जहाजों की आवाजाही की जगह नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास समाया है। इसने देश को स्वराज मिलते, सत्याग्रह और देश को बदलते देखा है।

रखी बात

रांची में आदि दर्शन पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम दिन जीवन, आत्मा व मृत्यु पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश के सभी 19 टीआरआइ में शोध कार्य होने चाहिए

आदिवासियों की सहजता को कमजोरी न समझें : अर्जुन मुंडा

जागरण संवाददाता, रांची

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के सभी 19 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीआरआइ) केंद्रों पर आदिवासी जीवन पद्धति व विकास को लेकर शोध कार्य होने चाहिए, ताकि आदिवासी परंपरा, विचारों व पुरानी पद्धति पर विस्तृत अध्ययन हो सके। यह बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। वह रविवार को रांची में आयोजित आदि दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विषय में प्रचलित मत है कि ये अन्य लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं। कम बोलते हैं। ऐसा बिलकुल नहीं है आदिवासी जीवन बनावटी नहीं है। आदिवासी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी-झरने से भी बातें किया करते हैं। बाहर की बजाय आदिवासी अंदर से अधिक जगा हुआ है। इसलिए कम बोलते हैं। यह उनकी सहजता है। आदिवासियों की सहजता को कई लोग उसकी कमजोरी समझते हैं। ऐसा समझना भूल है।

तीन दिवसीय इस सेमिनार का आयोजन डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान और झारखंड कल्याण विभाग की ओर से किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज की जीवन पद्धति प्रकृति पर आधारित है। यहां प्रकृति को सहचर मानने की परंपरा है अनुचर नहीं। आज प्रकृति संरक्षण के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, लेकिन आदिवासियों के स्वभाव-संस्कार में प्रकृति की चिंता शामिल रहती है। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया में विभिन्न जनजातियों के अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं लेकिन स्वभाव-संस्कार के मामले में काफी समानता देखने को मिलती है।

रांची में कार्यक्रम आदि दर्शन के समापन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सचिव हिमानी पांडेय सम्मानित करती हुईं, साथ में रणेंद्र कुमार (बाएं) और प्रो. एसएसन मुंडा (पीछे)। जागरण

आदिवासी कौन हैं, यह समझना जरूरी

सेमिनार के अंतिम दिन आत्मा, मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, स्वर्ण-नरक और पाप-पुण्य विषय पर चर्चा की गई। राम प्रसाद सरदार ने बांग्लादेश में रहने वाले मुंडा समाज के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि झारखंड से बांग्लादेश गए लोगों को आदिवासी होने की स्वीकृति नहीं मिली। अर्जुन राथवा ने कहा, जब अधिक यर्थाथवादी होने के लिए धर्म शब्द का उपयोग किया जाता है तो मैं उन लोगों के समूह से जुड़ा होता हूं जो मानवता के अध्यात्मिक पहुलओं के बजाय स्वयं के साथ खुद को पहचानते हैं जो शायद नजरअंदाज हो गए हैं। प्रकृति द्वारा अलगाव अक्सर इसे विकसित करने की कोशिश करता है और शायद इसकी ये घटनाएं धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। डॉ. हरि उरांव ने जनजाति के संदर्भ में मृत्यु के बाद आत्मा की परिकल्पना का वर्णन किया। कहा कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तब अपने लोगों के आसपास रहने से उसे शांति मिलती है। मृत्यु के बाद रीति-रिवाज को संपन्न कर मृत आत्मा को पुकारा जाता है और उसे घर में प्रवेश कराया जाता है। पूर्वजों के आत्मा के लिए प्रतिदिन खाने के पहले कुछ अन्न दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज की आत्मा घर में ही निवास करती है।

200 से अधिक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता संशोधन कानून पर जागरूक करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) अभियान चलाएगा। आयोजन में उस शहर के आम लोगों के साथ ही प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं, समाजसेवियों व राजनीतिज्ञों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कांग्रेस शासित सभी राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे पारित

तेज होगा विरोध ▶ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी प्रस्ताव पारित करने की तैयारी

सिब्बल के बयान को पार्टी ने उनकी निजी राय करार दिया

संजय मिश्र, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पार्टी के विरोध को और तेज करने के लिए पंजाब के बाद सभी कांग्रेस शासित राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव पारित करेंगे। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही पंजाब के नक्शे कदम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं से भी सीएए को रद करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सीएए के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पार्टी शासित राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कांग्रेस केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाना चाहती है।

कांग्रेस सीएए के खिलाफ राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा न केवल इसके विरोध को तेज करना चाहती है, बल्कि इसकी वैधानिकता को भी सवालों के दायरे में लाना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो दिन पहले ही सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें इसे भेदभावकारी बताते हुए केंद्र से इस कानून को रद करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के रणनीतिकार और पार्टी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने रविवार को साफ कहा कि पंजाब के बाद दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी सीएए को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

पटेल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का स्पष्ट तौर पर नाम भी लिया। वैसे भी मध्य प्रदेश में सीएए के खिलाफ कांग्रेस के विरोध की मुखर कमान खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने थाम रखी है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी उनसे पीछे नहीं हैं। जबकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तो सीएए के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति के प्रमुख सूत्रधारों में ही शामिल हैं। सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने की शुरुआत वामदल शासित केरल ने की थी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सीएए को रद करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करने के बाद सभी विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा ही करने का अनुरोध किया था।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 13 जनवरी को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भी वामदलों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए जाने पर जोर दिया था। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सीएए के खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव की गंभीरता की अनदेखी नहीं की जा सकती। खासकर तब जब 10-12 राज्यों की विधानसभाओं से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। सीएए को रद करने के खिलाफ 60 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें केरल सरकार की याचिका भी शामिल है। ऐसे में विधानसभा से पारित प्रस्तावों की अनदेखी आसान नहीं होगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों के अलावा पार्टी की कोशिश उन राज्यों से भी प्रस्ताव पारित कराने पर है जहां वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इसमें झारखंड सबसे अहम राज्य है और विपक्षी नेता इसके लिए झामुमो नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ऐसा करना कुछ जटिल काम है, क्योंकि शिवसेना इसके लिए राजी होगी, इसमें अभी संदेह है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने कहा है, सीएए लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते राज्य

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि वर्तमान हालत में चाहे राज्य सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें मगर इसे लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते। सिब्बल के अनुसार, राज्यों के लिए इस कानून को लागू करना उनकी संवैधानिक बाध्यता है। कांग्रेस ने रविवार को सिब्बल के इस बयान को उनकी निजी राय करार दिया और कहा कि राज्यों ने अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है तो सर्वोच्च अदालत का निर्णय आने तक उसे लागू नहीं करने का अख्तियार रखते हैं।

लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत : मनमोहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने सीएए के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच कहा कि भारत में लोकतंत्र की उदार संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। संविधान की रक्षा के लिए इन पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हाल ही में देश को अहसास कराया है कि प्रबुद्ध नागरिकों की हिफाजत में देश की आजादी सुरक्षित है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार की किताब 'ह्यूमन डिगनिटी-ए परपज इन परपेट्यूटी' के विमोचन पर मनमोहन सिंह ने कहा कि जब भी मूलभूत स्वतंत्रता के लिए खतरा महसूस हुआ है हमारे उदार और उदारवादी लोकतंत्र को कई अवसरों पर परीक्षा देनी पड़ी है। वर्षों से इन संस्थाओं को पोषित किया गया है। इन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। संविधान को बचाने के लिए हम सब को और आग्रह करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून के तहत समानता के आधार पर अगर नागरिक रहेंगे तभी हमारे जीवन में स्वतंत्रता के विचार को आकार दिया जा सकता है।

मनमोहन सिंह ने ऐसे समय में यह वक्तव्य दिया है जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है और केरल सरकार ने नए कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर किताब के लेखक और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि अनंतकाल तक हमारा मकसद मानव सम्मान होना चाहिए।

सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला : शेख हसीना

▶ बांग्लादेश की पीएम ने कहा, इस कानून की जरूरत क्या थी

दुबई, प्रेट्र : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को भारत का अंदरूनी मामला बताया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में इस कानून की जरूरत क्या थी? सीएए के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबूधाबी में गल्फ न्यूज को दिए साक्षात्कार में हसीना ने कहा, मुझे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने यह क्यों किया? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हसीना का बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन के उस बयान के कई सप्ताह बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं, लेकिन अगर इसको लेकर भारत में किसी तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता है तो उससे पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश की 16 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 10.7 फीसद हिंदू जबकि महज 0.6 फीसद बौद्ध हैं।

बांग्लादेश की पीएम ने इस बात से साफ इन्कार किया कि उनके देश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते अल्पसंख्यक समुदायों ने भारत पलायन किया है। उन्होंने इन्हीं वजहों से किसी अन्य देश के नागरिकों के बांग्लादेश आने की बातों को भी नकारा। हसीना ने कहा, बांग्लादेश ने हमेशा से कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं। भारत सरकार ने भी यही बात दोहराई है। अक्टूबर, 2019 में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया था। बांग्लादेश और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रगाढ़ संबंध हैं।

असम में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 30 अगस्त को प्रकाशित अंतिम एनआरसी से 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की फाइल फोटो। रायटर

न्यूज गैलरी

'बंगाल से एक करोड़ घुसपैठियों को भेजा जाएगा बांग्लादेश'

बैरकपुर : बंगाल में एनआरसी लागू करने को लेकर पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। बंगाल में रह रहे एक करोड़ अवैध शरणार्थियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उक्त बातें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कही। वह रविवार को बैरकपुर में अभिनंदन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। यह यात्रा दिलीप के नेतृत्व में निकली थी। दिलीप ने कहा, सालों से यहां शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन वे देश के नागरिक नहीं हो पाए हैं। महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस, वाममोर्चा के नेताओं ने उन्हें नागरिकता देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें नागरिकता नही मिली। ऐसे लोगों से भाजपा ने नागरिकता देने का वादा किया था। सत्ता में आने पर हम यह जरूर करेंगे। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए के विरोध में मध्यमग्राम से बारासात तक पांच किमी पदयात्रा की थी। भाजपा के इस अभिनंदन यात्रा को उस पदयात्रा का जवाब माना जा रहा है। (जासं)

जिनके मन में पाप, उन्हें सीएए नहीं आ रहा पसंद : जैन मुनि

ग्वालियर : इंदौर से दिल्ली पदविहार कर रहे आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अच्छा और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा, जिनके मन में पाप, विकृति, अत्याचार है, उनको सीएए पसंद नहीं आ रहा है। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने ग्वालियर प्रवास के दौरान जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की। कहा, उनके कार्य करने तरीके और दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। सीएए के विरोध के सवाल पर कहा कि जिन्होंने समझा नहीं उनके लिए यह गलत है। यह देश के लिए जरूरी कानून है। (नईदुनिया)

'राज्यों के पास है केंद्र को चुनौती देने का अधिकार'

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने कहा है कि राज्यों के पास केंद्र सरकार को चुनौती देने का अधिकार है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस असंवैधानिक कानून को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सीएए संविधान पर हमला है और लोगों का कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहना चाहिए। (प्रेट्र)

शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए विहिप चलाएगा अभियान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ कहा, नागरिकता दिलाने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा

▶ अनुच्छेद-370 व राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार को साधु-संतों का साधुवाद

बंगाल, केरल और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के जोरदार विरोध के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि वह सभी शरणार्थियों को नागरिकता दिला कर रहेगी। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई वंचित न रह जाए।

कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा आयोजित आशीर्वाद सभा में अनुच्छेद 370 हटाने, सीएए लागू करने व सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर विवाद का निपटारा होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को साधुवाद दिया गया। देशभर से मठों, मंदिरों, आश्रमों और अखाड़ों से जुटे साधु-संतों के बीच संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके रहते राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। अनुच्छेद 370 हट जाएगा।

सीएए के विरोध को सियासी बताते हुए विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन शरणार्थियों की पूरी मदद करेंगे। उनके कागज दुरुस्त कराएंगे। पंजीकरण कराएंगे।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह बात मुस्लिम समुदाय को समझ आने लगी है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन हो। ताकि विपक्षी राज्य सरकारों द्वारा इस कानून को लागू करने से मना करने के बाद भी उन्हें नागरिकता मिले। सभा को महंत ज्ञानदेव सिंह, आचार्य अविचल दास, सुरेंद्रनाथ अवधूत, बलराम दास हठयोगी, नवल किशोर दास, अनुभूतांनद, यतींद्रनंद गिरी, ज्ञानदेव महाराज, कृष्णानंद व नामधारी संत अरविंद सिंह समेत अन्य संतों ने भी संबोधित किया।

सीएए को वामपंथी छात्र संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में एसएफआइ ने सीएए को भेदभाव की प्रवृत्ति वाला और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है।

एसएफआइ ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सीएए को भारतीय संविधान का उल्लंघन घोषित करने की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि सिर्फ एक तय धार्मिक समूह को वरीयता देना भारत की संवैधानिक योजना नहीं हो सकती। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (कानूनी समानता) के तहत उचित और मान्य वर्गीकरण नहीं हो सकता। याचिका में संविधान का उल्लंघन बताते हुए द पासपोर्ट एक्ट-1920 और द फॉरेन एक्ट-1946 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की भी मांग की गई है।

याचिका के अनुसार, 'एसएफआइ के सदस्य सीएए-2019 लागू किए जाने से व्यथित हैं। यह भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ है।'

छह वर्षों में 2838 पाकिस्तानियों को मिली है भारतीय नागरिकता : निर्मला

चेन्नई, एजेंसियां : देशभर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) के विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों में पाकिस्तान के 2,838 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। इस दौरान मुसलमानों सहित 914 अफगानी शरणार्थियों, 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी भारतीय नागरिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सीएए को राज्यों में लागू न करने की बात असंवैधानिक है। यह सभी राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि संसद में पारित कानून पर अमल हो।

रविवार को यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची वित्त मंत्री ने बताया कि साल 1964 से 2008 तक श्रीलंका से आए चार लाख से अधिक तमिलों को भारतीय नागरिकता दी गई है। वह यहां नागरिकता संशोधन कानून पर हो रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 से अधिक मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। मोदी सरकार के तहत 2016-18 के दौरान, लगभग 1,595 पाकिस्तानी प्रवासियों और 391 अफगानी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। वित्तमंत्री ने आगे कहा कि साल 2016 में भी इसी अवधि के दौरान, पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारतीय नागरिकता दी गई थी, जो कि यह एक उदाहरण है। सीतारमण ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को देश के विभिन्न शिविरों में बसाया गया है। वे अभी भी वहां हैं और इस बात को अब 50-60 साल हो गए हैं। यदि आप इन शिविरों का दौरा करेंगे, तो आपका दिल पसीज जाएगा।

निर्मला सीतारमण। फाइल

श्रीलंका के शरणार्थियों की स्थिति भी उसी तरह की है, जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसी की नागरिकता छीन नहीं रही है। नागरिकता संशोधन कानून लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने की एक कोशिश है। हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, हम केवल उन्हें ही प्रदान कर रहे हैं।

सीएए का विरोध असंवैधानिक : सीतारमण ने चेन्नई सिटिजन फोरम की ओर से आयोजित समारोह में एक सवाल के जवाब में कहा कि सीएए का विरोध असंवैधानिक है। केरल और कुछ राज्यों ने सीएए को लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य की विधानसभा सीएए लागू नहीं करने का प्रस्ताव तो पास कर सकती है। यह उनका राजनीतिक वक्तव्य है। लेकिन इससे आगे बढ़कर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। केरल के अलावा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी इसे लागू करने से इन्कार किया है।

सीएए के समर्थन में निकाली रैलियां, मप्र में हंगामा

नईदुनिया, ब्यावरा/राजगढ़

▶ कलेक्टर ने भाजपा नेता को मारा थप्पड़

▶ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निकाली गई थी रैली

▶ जिला प्रशासन ने रैली रोकने के लिए लगाई थी धारा 144

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रविवार को भी लोग सड़कों पर उतरे। राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के ब्यावरा में रैली में जमकर हंगामा हुआ। बहस के दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने एक भाजपा नेता को चांटा मार दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस कार्रवाई में दो लोगों के सिर फूट गए।

सीएए के समर्थन में आयोजित इस रैली को रोकने के लिए कलेक्टर ने निषेधाज्ञा लागू कर ब्यावरा की सीमाएं सील कर दी थी, बाजार भी बंद थे। दोपहर एक बजे के बाद वंदेमातरम के नारे लगाते लोग निकले तो कलेक्टर निधि निवेदिता ने उन्हें रोकने के लिए दरवाजा बंद करना चाहा। पूर्व विधायक अमरसिंह यादव को उन्होंने पकड़ भी लिया, लेकिन वे छूटकर आगे बढ़ गए।

पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना चाहा तो बहस हुई। कलेक्टर ने भाजपा के मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को चांटा मार दिया। पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान दो लोगों के सिर फूट गए। इस बीच डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा भी लोगों को पकड़ने भीड़ में घुस गईं। आरोप है कि एक युवक ने उनसे अभद्रता की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। विरोध में थाने के सामने आधा घंटे तक धरना दिया गया। भाजपा ने प्रशासन पर जहां माहौल बिगाड़ने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है, वहीं कलेक्टर निधि निवेदिता ने कहा कि बगैर अनुमति के रैली निकालने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने महिला अधिकारी के साथ भी अभद्रता की है। वीडियो से आरोपितों की पहचान की जा रही है।

पंजाब के खन्ना में सीएए के समर्थन रैली में पाकिस्तान से आए पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। राष्ट्रीय विचार मंच की इस रैली में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हाथों में कानून के पक्ष में तख्तियां भी उठा रखी थी। साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़ ने रैली निकालकर कर लोगों को सीएए के संबंध में जानकारी दी।

इस दौरान पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मवीर गाबा ने भी सीएए को समर्थन दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसके समर्थन में रैली निकाली गई। एक गोष्ठी भी आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने राजनीतिक दलों से इसका मानवता और राष्ट्रहित के लिए समर्थन करने का आह्वान किया।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएए की रैली में भाजपा मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने और कलेक्टर निधि निवेदिता में तीखी बहस हो गई। नईदुनिया

> हमने रैली की अनुमति नहीं दी थी। धारा 144 लगाई थी। जो अराजक व तत्व अपनी बात मनवाना चाहते थे, वे यहां आए थे। रैली निकालने के लिए कोशिश करते रहे। तभी पूर्व विधायक वहां पहुंचे। लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हमारी महिला अधिकारी के साथ भी अभद्रता की है। वीडियो से आरोपितों की पहचान की जा रही है।
>
> **-निधि निवेदिता, कलेक्टर, राजगढ़**

'मुसलमानों से नागरिकता साबित करने के कागज मांगे जाएंगे'

कोझिकोड, एएनआइ

▶ बोले शशि थरूर, विरोध-प्रदर्शन बंद हो जाएंगे अगर मोदी और शाह आश्वासन दें कि एनआरसी का विचार छोड़ देंगे

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मुसलमानों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजी सुबूत मांगे जाएंगे। नए नागरिक कानून के खिलाफ देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह आश्वासन दें कि एनआरसी का विचार छोड़ देंगे। और घर-घर जाकर मां-बाप का कहां पैदा हुए थे, इसका दस्तावेजी सुबूत नहीं मांगेंगे।

केरल के लिट्रेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के दौरान भी मुसलमानों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहे जाएंगे। गृह मंत्री ने साफ तौर पर सीएए और एनआरसी को बांध दिया है। सीएए में कहा गया है कि अगर आप साबित कर देंगे कि आप इन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से हैं तो आपकी नागरिकता को फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। थरूर ने दोनों मुद्दों का घालमेल करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय से दस्तावेज मांगे जाएंगे। 65 फीसद भारतीय के पास उनके जन्म प्रमाणपत्र नहीं हैं।

अगर हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्धों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं होगा तो उन्हें किसी और बात के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। जबकि बिना दस्तावेज वाले मुसलमानों से पूछा जाएगा कि हम कैसे मान लें कि आप पाकिस्तान से नहीं हैं। उनसे यह साबित करने को कहा जाएगा कि वह यहीं जन्मे थे।

तिरुअनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि पीएम को यह आश्वासन देना चाहिए कि आपके नामों के खिलाफ संदिग्ध नागरिकता लिखने के अधिकार वह अधिकारियों को नहीं देंगे। लेकिन मोदी और शाह यह सभी आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं। इससे उनके इरादों का पता चलता है। वह भारत में रह रहे लोगों की पहचान करना चाहते हैं।

केरल के राज्यपाल बोले, मूकदर्शक नहीं बना रहूंगा

▶ आरिफ मुहम्मद खान ने कहा-हर हाल में कानून का पालन सुनिश्चित करेंगे

▶ राज्यपाल ने राज्य सरकार से बिना बताए सुप्रीम कोर्ट जाने पर रिपोर्ट तलब की

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून पर केरल में वाम मोर्चा की सरकार से मोर्चा ले रहे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में 'मूक दर्शक' नहीं बने रहेंगे। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि देश के कानून का पालन हो।

बेंगलुरु से लौटने पर रविवार की शाम को केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि संविधान का पालन होना ही है। यह कोई निजी लड़ाई नहीं है। संविधान का पालन हो कर रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए मैं मूक दर्शक नहीं बना रहूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामले और सरकार के कामकाज को किसी व्यक्ति और राजनीतिक दल के जुनून पर नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को नियमों का आदर करना चाहिए।

इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके राज्यपाल ने कहा कि इसके साथ ही राजभवन ने राज्यपाल को बताए बिना केरल सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है।

उल्लेखनीय है कि केरल पहला राज्य है जिसने सीएए का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। केरल की एलडीएफ सरकार ने विगत 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती देते हुए इसे संविधान का उल्लंघन करार देने की अपील की थी। कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत राज्य सरकार को राज्यपाल को उन मामलों की सूचना देनी चाहिए जो राज्य और केंद्र के संबंधों को प्रभावित करते हैं। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल के दफ्तर को कोई चुनौती नहीं दी है।

आरिफ मुहम्मद के बयान का महत्व नहीं : तारिक अनवर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी सीएए पर कपिल सिब्बल के बयान को संवैधानिक रूप से सही बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक विद्वान वकील हैं और उन्हें संविधान की अच्छी जानकारी है। लेकिन यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वह इस मामले के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही कोई फैसला देगा। तारिक अनवर ने केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के उस बयान पर भी अपनी राय दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संसद में पारित हो जाने के बाद राज्यों के पास सीएए का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरिफ मुहम्मद खान भाजपा के नेता हैं। इसलिए उनके बयान का कोई खास महत्व नहीं है।

'सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया तो विरोध असंवैधानिक' : इससे पहले, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को ट्वीट करके दोहराया कि कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि वह नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगा। हालांकि इसकी वजह पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक घोषित कर देता है तो इसका विरोध करना असंवैधानिक कहलाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने विगत शनिवार को कोझिकोड में आयोजित केरल लिट्रेचर फेस्ट में कहा था कि राज्य सरकारें संसद में पारित कानून के खिलाफ नहीं जा सकती हैं।

कश्मीरी पंडितों के लिए मांगा समर्थन

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीरी पंडितों की बात रखते हुए सतीश महालदार ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि आप हमारे लिए आगे आएं। हम पिछले 30 सालों से अपने ही देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे घर हमसे छीन लिए गए हैं। पहले हमें हमारी जमीन वापस दिलाई जाए। वहीं आशीष पंडित ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं इस बात पर किसी को शक नहीं है, लेकिन हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमें हमारी ही जमीन से बेदखल किया गया है। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएए का विरोध करने पर आपस में ही हुआ मतभेद : सतीश महालदार ने मंच से सीएए को लेकर सवाल खड़े किए तो प्रतिनिधिमंडल के साथ ही आईं मोनिका पंडित ने उनका विरोध किया। मोनिका ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं। साथ ही कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के दिन किसी भी जश्न के कार्यक्रम का विरोध करते हैं।

शाहीन बाग में जश्न ए शाहीन का विरोध करने पहुंचे कश्मीरी पंडित। जागरण

1340 आपत्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) की खारिज कर दी गई हैं। 2019 में पूछे गए सवालों पर 2374 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इनमें से 1340 बिना शुल्क जमा किए आपत्ति दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 20 जनवरी 2020

जल-जीवन-हरियाली के लिए पांच करोड़ से भी ज्यादा ने बनाई मानव शृंखला

महा अभियान ▶ बिहार में 18 हजार किलोमीटर लंबी कतार में खड़े होकर लोगों ने दिया संदेश-जल-हरियाली है, तभी जीवन और खुशहाली है

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार में रविवार को पांच करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जल-जीवन-हरियाली एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ 18 हजार 34 किमी लंबी शृंखला बनाकर दुनिया को रास्ता दिखाया। इस महाभियान का साक्षी बना पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां बिहार के नक्शे से चारों दिशाओं में निकलकर मानव कतार पूरे प्रदेश में फैल गई। सीमावर्ती प्रदेशों उप्र, झारखंड और बंगाल के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल को स्पर्श करते हुए पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि जल और हरियाली है, तभी जीवन है, खुशहाली है।

टूटे दो रिकॉर्ड : जल-जीवन-हरियाली के समर्थन में इस बार बनाई गई मानव शृंखला ने पिछले दो रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2017 और 2018 के रिकॉर्ड के मुकाबले जहां सर्वाधिक लोग इस बार शामिल हुए वहीं लंबाई के मामले में भी इसने विश्व कीर्तिमान बनाया। प्रदेश के मुख्यसचिव दीपक कुमार ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली एवं नशा मुक्ति के पक्ष तथा दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन के लिए बनाई गई शृंखला में 5,16,71,389 लोग शामिल हुए। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कुल 18,034 किलोमीटर लंबी शृंखला का निर्माण किया। बिहारवासियों ने पहली बार 21 जनवरी, 2017 को 11292 किमी की मानव शृंखला बनाई थी। जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने हाथ से हाथ जोड़कर नशा मुक्ति के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। इसके बाद 21 जनवरी, 2018 को बिहारवासियों ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 14 हजार किमी की शृंखला बनाई। राज्य के महासचिव का दावा है कि बिहार ने ही मानव शृंखला का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है।

आधे घंटे के लिए थम गया वक्त : रविवार दोपहर घड़ी ने जैसे ही 11.30 बजाया, वैसे ही पांच करोड़ से ज्यादा हाथों ने एक दूसरे को आत्मीयता से थाम लिया। ऊंच-नीच, बड़ा-छोटा का भेद खत्म।

मुलाजिमों और हाकिमों के बीच अद्भुत समन्वय था। सबके चेहरे पर चमक थी। प्रदेश की विभिन्न जेलों में कैदियों ने भी शृंखला बनाई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जल पुरुष राजेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस आयोजन के गवाह बने। अगली पीढ़ी की हिफाजत की भावना और समर्पण की लंबी कतार में पूरा बिहार आधा घंटा खड़ा रहा।

जो जहां था, वहीं खड़े होकर प्रकृति से प्यार का इजहार किया। पिछली दो मानव शृंखलाओं के कीर्तिमान के बाद प्रकृति के पक्ष में ऐसी एकजुटता और संकल्प शक्ति के प्रदर्शन से दूसरे प्रदेशों को भी प्रेरणा मिलेगी।

गांधी मैदान में जल-जीवन-हरियाली अभियान के साथ-साथ नशामुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल-विवाह उन्मूलन के संदेश के साथ आयोजित मानव शृंखला का शुभारंभ करते बाएं से पांचवे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं बिहार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव यूनाइटेड नेशन प्रतिनिधि अतुल बगाई, मुख्यमंत्री के दाएं जलपुरुष राजेन्द्र सिंह व अन्य । जागरण

एक नजर में

मानव शृंखला की कुल लंबाई	18034 किमी
शामिल लोग	5,16,71,389
मॉनीटरिंग को हेलिकॉप्टर	7
प्रयोग में लाए गए ड्रोन	100

आकलन को आई दो संस्थाएं

बिहार में जल-जीवन-हरियाली के समर्थन में बनने वाली मानव शृंखला के विश्व रिकॉर्ड आकलन के लिए दो संस्थाएं बिहार आईं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के सदस्य पटना में थे जो यह आकलन कर रहे थे कि मानव शृंखला का विश्व रिकॉर्ड किस प्रकार से बना। संसाधनों की कमी का हवाला देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम रिकॉर्ड के आकलन को इस आयोजन में शामिल नहीं हुई। उम्मीद है कि जल्द ही इसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा।

राजद के तीन विधायकों ने भी दिया नीतीश का साथ

राज्य ब्यूरो, पटना

मानव शृंखला के रिकॉर्ड के साथ ही राजद की एकजुटता से भी पर्दा हट गया। तेजस्वी यादव की पार्टी के तीन विधायकों एवं एक विधान पार्षद ने नीतीश कुमार का साथ दिया। चारों नेताओं ने मानव शृंखला में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने-अपने क्षेत्र में पूरे समय कतार में खड़े रहे। राजद के बागियों में नया नाम पातेपुर की विधायक प्रेमा चौधरी का जुड़ गया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में मानव शृंखला में खड़ा होकर राजद को झटका दिया। प्रेमा को राबड़ी देवी की करीबी माना जाता है। वह पिछली बार राजद की प्रदेश अध्यक्ष की कतार में भी थीं। विधान पार्षद संजय प्रसाद, केवटी के विधायक फराज फातमी और गायघाट विधायक महेश्वर यादव ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में मानव शृंखला में हिस्सा लिया।

फराज फातमी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान राजद समेत सभी दलों ने जल- जीवन- हरियाली अभियान का समर्थन किया था। मैंने पार्टी लाइन से अलग कोई काम नहीं किया है। जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है, तेजस्वी यादव को पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फराज ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया था। तेजस्वी को पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संजय प्रसाद ने चकाई और महेश्वर यादव ने मुजफ्फरपुर में मानव शृंखला बनाई।

शृंखला के दौरान मृत शिक्षक के एक परिजन को नौकरी : मानव शृंखला के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में मो. दाउद नाम के एक शिक्षक और समस्तीपुर में शृंखला में शामिल एक महिला (नाम ज्ञात नहीं) की मृत्यु हृदयाघात की वजह से हो गई। शिक्षक मध्य विद्यालय केवटी में स्थायी शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे।

सरकार ने दोनों मृतकों के स्वजनों को तत्काल सहायता के रूप में चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा शिक्षक के स्वजनों को दूसरे लाभ और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी।

मिलती रही पल-पल की सूचना

सफल आयोजन में प्रशासनिक स्तर पर हुई 'माइक्रोप्लानिंग' और हर स्तर पर बरती गई सावधानी की अहम भूमिका रही। इसमें सरकार के सभी 47 विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही वजह रही कि मानव शृंखला के दिन किसी भी जिले से किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना शिक्षा विभाग के कंट्रोल रूम को नहीं मिली। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों व शिक्षकों के अलावा सभी जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, साक्षरता कर्मी, जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारी की उत्साहजनक भागीदारी से भी मानव शृंखला का नया इतिहास रचा गया। इस बार मानव शृंखला के लिए तय लक्ष्य 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हुई। यानी लक्ष्य से 90 लाख ज्यादा लोग मानव शृंखला में शामिल हुए।

आरा में मानव शृंखला में वृक्ष का दृश्य दर्शाती डॉ. नेमीचंद शास्त्री विद्यालय की छात्राएं । जागरण

तो सियासत से कुछ यूं कमान थाम लेता है समाज

मनोज झा, पटना

रविवार की सर्द सुबह और छुट्टी का दिन, बादल और कोहरे के बीच दुबका सूरज, वातावरण में सिरसिरी-सी ठंड, लेकिन आम जनजीवन में एक अजीब-सी उमंग। पौ फटते ही पूरे बिहार में सियासत की अबूझ परछाइयों से दूर नागरिक समाज एक अलग उत्साह और जल्दी में नजर आ रहा था। किसी को कोई बुलावा या न्योता नहीं, कहीं कोई वोट या चुनाव भी नहीं, लेकिन जाने और जानने की जल्दी सभी को थी। एक ऐसे मिशन से जुड़ने के लिए, जिसका तुरंत कोई नतीजा भी नहीं आना है और इसका सुखद परिणाम शायद हमारी भावी पीढ़ी को भोगना है। बावजूद इसके, पांच करोड़ से ज्यादा लोग न सिर्फ स्वतः स्फूर्त घरों से बाहर निकले, बल्कि सड़क, मैदान, पानी और पहाड़ पर साथ आते गए, एक हाथ से दूसरे का हाथ जोड़ते रहे और 18 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक कारवां बनता गया। दरअसल, यह बिहार की माटी से उठी एक समवेत पुकार है कि पानी और हरियाली ही एकमात्र रास्ता है, मानवता का मुक्तिपंथ है। इन्हें बचाना होगा, इन्हें सहेजना होगा, इन्हें संवारना ही होगा।

40 फीसद से ज्यादा आबादी जुड़ी : प्रदेश सरकार के जल-जीवन- हरियाली मिशन के इस पड़ाव की विहंगमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की 40 फीसद से ज्यादा आबादी इस अभूतपूर्व मानव शृंखला से जुड़ी। बूढ़े-बच्चे, नर-नारी, किसान-जवान, नेता-अभिनेता, शक्त-अशक्त, कामगार-बेरोजगार आखिर कौन था, जिसने हाथ से हाथ मिलाने में कोई गुरेज किया? छुट्टी के दिन आमतौर लोग थोड़े अलसाए और उनींदे-से रहते हैं। लेकिन कल (19 जनवरी) का रविवार भी पर्यावरण के प्रति समाज की आश्चर्यजनक जागृति देखकर मानो गदगद हो गया। लोग पर्यावरण की चिंता में डूबकर घरों से खुद बाहर निकले। ऐसा भी नहीं कि सभी को कहीं एक स्थान पर किसी आयोजन में पहुंचना था या किसी को सुनना था। प्रदेश भर के तमाम जिलों में शहर, गांव, कस्बे, जहां जिसे सहूलियत थी, वहां पहुंचे और मानव शृंखला की एक-एक कड़ी बनते गए। मानव शृंखला के कीर्तिमान को देखकर तो एक बार के लिए ऐसा ही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शायद यह अंदाजा न हो कि पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता में समाज इस तरह दिल खोलकर साथ देगा। इससे यह भी साबित हुआ कि पर्यावरण के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता कितनी वास्तविक और ठोस धरातल पर खड़ी है।

दिखे कई आश्चर्यजनक दृश्य: राजनीति में आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच पर्यावरण जैसे सरोकार को लेकर समाज का एकजुट हो जाना, उसका जाग जाना वाकई अभूतपूर्व है। पूरे प्रदेश में बनी मानव शृंखला के दौरान कई आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिले। मल्लाहों ने जमीन पाने का इंतजार नहीं किया और मानव शृंखला बनाने के लिए नदियों में ही अपनी नौकाओं को एक दूसरे से जोड़ लिया। कहीं अंत्येष्टि स्थल पर धधकती चिता को छोड़ लोग हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो कहीं गृहणियां चौका-चूल्हा छोड़ सड़कों पर निकल आईं और एक से दूसरे का हाथ जोड़ लिया। अवकाश के बावजूद लाखों स्कूली बच्चे इस मानव शृंखला की कड़ियां बने, बुजुर्गों ने लाठी का सहारा लिया तो दिव्यांग व्हील चेयर पर आए। गवैयों ने गा-बजाकर जल का आचमन किया तो किन्नरों ने अपनी वेशभूषा में हरियाली का हार पहना। पूरे प्रदेश ने जल-जीवन-हरियाली मिशन को अब अपनी गोद में ले लिया है।

गांधी मैदान में बिहार के मानचित्र की आकृति में मानव शृंखला बनाते स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियां एवं अन्य । जागरण

न्यूज गैलरी

वाट्सएप में आई तकनीकी बाधा, यूजर ने किया ट्रोल

नई दिल्ली : भारत समेत दुनिया के कई देशों में रविवार को वाट्सएप की सेवाएं बाधित रहीं। इससे नाराज यूजर ने ट्विटर पर हैशटैग वाट्सएपडाउन को ट्रोल कर दिया। लोगों ने तरह-तरह के मीम और चुटकुले साझा करने शुरू कर दिए। शाम करीब चार बजे शुरू हुई यह परेशानी दो घंटे से भी ज्यादा समय तक बनी रही। दुनियाभर में वाट्सएप के लाखों यूजर वीडियो, फोटो, जीआइएफ, ऑडियो व स्टीकर साझा नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारत, यूरोप, ब्राजील और दक्षिणपूर्व एशिया में यह परेशानी शाम करीब चार बजे शुरू हुई। नाराज वाट्सएप यूजर ने तकनीकी बाधा को ट्विटर पर हैशटैग वाट्सएपडाउन के साथ ट्रोल कर दिया। (एजेंसियां)

पाकिस्तानी रेंजरों ने गांवों को निशाना बना की गोलाबारी

हीरानगर : पाकिस्तानी रेंजरों ने तीन दिन बाद फिर सीजफायर का उलंघन करते हुए हीरानगर सेक्टर के चक चंगा और छन्नटांडा गांवों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक रेंजरों ने शनिवार देर रात पप्पू चेक पोस्ट से गोलाबारी शुरू कर दी, जो रविवार सुबह साढ़े चार बजे तक जारी रही। इस दौरान पाक रेंजरों ने गोलीबारी के साथ 81 व 51 एमएम के मोर्टार दागे, जो गांवों के बाहर खेतों में गिरे। (जासं)

अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन दिलाने की मांग करेंगे

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा नेता का कहना है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर उक्त जमीन अनुसूचित जातियों को ही दिलाने की मांग करेंगे, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए, जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर एससी एसटी एक्ट में भी मुकदमा कराया जाए।

जमीन को सरकारी संपत्ति में दर्ज करने की होगी कार्यवाही : डीएम : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि अभी उन्हें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जमीन को सरकारी संपत्ति में दर्ज करने के लिए प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

नीति आयोग के सदस्य बोले-कश्मीर में इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं लोग

▶ कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने बयान की निंदा की

▶ विवाद बढ़ने पर सारस्वत ने सफाई दी और माफी मांगी

अहमदाबाद, प्रेट्र : नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद इंटरनेट पर पाबंदी से अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि लोग वहां इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनके इस बयान पर कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआइ) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चैंबर ने उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की, जबकि माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सारस्वत को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है।

विवाद बढ़ने पर रविवार को सारस्वत ने सफाई दी कि उनके बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया और वह कश्मीरी जनता के इंटरनेट के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। सारस्वत ने यह भी कहा कि अगर उनके गलत तरीके से पेश किए गए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं।

सारस्वत ने शनिवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि कुछ लोग सूचना का दुरुपयोग करके कानून एवं व्यवस्था के समक्ष संकट खड़ा करने का काम न कर सकें। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन एंड टेक्नालाजी के दीक्षा समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से सारस्वत ने कहा, अगर कश्मीर में इंटरनेट नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप वहां इंटरनेट पर क्या देखते हैं? वहां इससे कौन सा बिजनेस चल रहा है। गंदी फिल्में देखने के अलावा लोग और क्या करते हैं?

केसीसीआइ ने की निंदा

सारस्वत के बयान की केसीसीआइ (कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) प्रेसीडेंट शेख आशिक ने निंदा करते हुए कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह कश्मीरी जनता की छवि खराब करने का काम करे। घाटी इंटरनेट शटडाउन के कारण पहले से बदहाल है, व्यापारिक नुकसान 18000 करोड़ रुपये हो चुका है। अगर सारस्वत सरीखे लोग जम्मू-कश्मीर के साथ कोई न्याय नहीं कर सकते तो उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के साथ ही इंटरनेट, लैंडलाइन और मोबाइल फोन की सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट को छोड़कर शेष सभी सेवाएं एक सप्ताह के भीतर ही शुरू कर दी गई थीं, जबकि कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में इंटरनेट की बहाली चरणबद्ध तरीके से की गई। शनिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की भी फिर से शुरुआत कर दी।

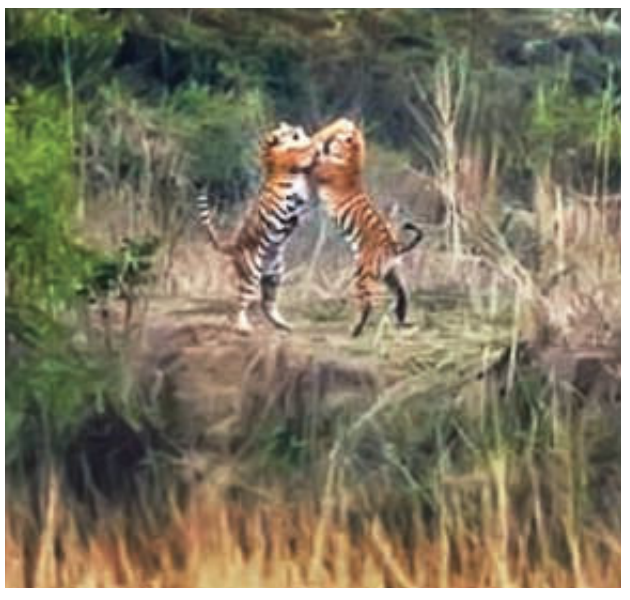

कार्बेट में वर्चस्व की जंग

कार्बेट पार्क में बाघों की संख्या बेशक बढ़ रही है, लेकिन आपसी जंग में वह अपनी जान भी गवां रहे हैं। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में वर्चस्व के लिए दो बाघ आपस में भिड़ गए। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। जब दो बाघों की लड़ाई को कैमरे में कैद किया जा सके। शुक्रवार को रेस्ट हाऊस के सामने बाघों का संघर्ष काफी देर तक चला। सीटीआर के निदेशक राहुल ने बताया कि यह फोटो उन्हें एक पर्यटक ने उपलब्ध कराई है। संघर्ष में एक बाघ के घायल होने की सूचना है। सौ. कॉर्बेट पार्क प्रशासन

परमाणु क्षमता वाली के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

नई दिल्ली, एएनआइ: भारत ने दुश्मन को हराने के लिए अपनी सामरिक क्षमता में विस्तार करते हुए रविवार को शक्तिशाली के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से दागी गई इस मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर है और यह पनडुब्बी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण दिन के समय समुद्र में पानी के भीतर बने प्लेटफॉर्म से किया गया। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है। इसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियों में तैनात किया जाना है। परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियों पर तैनाती से पहले भारत इस मिसाइल के अभी और परीक्षण करेगा। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल अरिहंत ही एक ऐसा परमाणु क्षमता वाला पोत है, जो परिचालन में है। के-4 उन दो अंडरवाटर मिसाइलों में से एक है, जिन्हें भारत नौसेना के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी मिसाइल का नाम बीओ-5 है और उसकी रेंज 700 किलोमीटर है।

आउटरीच कार्यक्रम

कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों तक पहुंचे आठ मंत्री, पांच जिलों के दस ब्लॉकों में केंद्रीय योजनाओं की दी गई जानकारी

केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर में वादे के साथ विकास की जगाई आस

राज्य ब्यूरो, जम्मू

मोदी सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रमों में पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं, ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को बताने के लिए बेहिचक पहुंच रहे हैं। वह बेबाक अपनी बात रख रहे हैं। रविवार को जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में गए केंद्रीय मंत्रियों ने ग्रामीणों में विकास की नई आस जगाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते की रुकावट अनुच्छेद 370 हट चुका है। अब तेज विकास का वादा पूरा होगा।

मोदी सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को आठ केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू संभाग के पांच जिलों के दस ब्लॉकों में लोगों के बीच जाकर उन्हें 370 हटने के बाद विकास के क्षेत्र की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने लोगों से जमीनी स्तर पर फीडबैक भी लिया। मंत्रियों में स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर, डॉ. जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी चौबे व आरके सिंह शामिल थे। मंत्रियों ने जम्मू जिले के अखनूर, डंसाल, नगरोटा, रियासी जिले के कटड़ा, पैंथल, कठुआ जिले के बसोहली, बिलावर, ऊधमपुर जिले के उधमपुर, खिलैनी व सांबा जिले के घगवाल ब्लॉकों में कार्यक्रम किए।जम्मू जिले में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे व वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार दोपहर को अखनूर, नगरोटा, डंसाल में पंचों, सरपंचों के साथ बैठकी। लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब ग्रामीण विकास की राह में फंड की कमी नहीं होगी। उन्होंने पंचों, सरपंचों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्षों के मसलों को जाना। साथ ही राज्य में विकास व केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों की तकदीर बदलने की मुहिम में पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग मांगा। अखनूर में गोयल ने सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ जियापोता घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने सैरगाह और इनडोर स्टेडियम का ई-उद्घाटन भी किया। मंत्री ने कहा कि अखनूर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

अनुराग ठाकुर ने तेज विकास के वादे को दोहराया

अनुराग ठाकुर ने नगरोटा में मोदी सरकार के तेज विकास के वादे को दोहराया। मनरेगा, जन धन जैसी योजना का उदाहरण दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए व विकास को भी बढ़ावा मिला है। केंद्रीय योजनाओं में उन्होंने पंचों, सरपंचों का सहयोग भी मांगा। राज्यसभा के सांसद शमशेर सिंह मन्हास के साथ नगरोटा में कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले केंद्रीय मंत्री ने नगरोटा से कट्टल-बटाल सड़क का भी उद्घाटन किया।

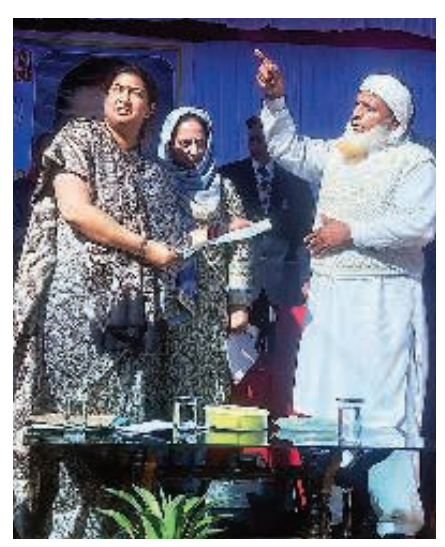
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा के मूरी गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने ईरानी को समस्याओं से अवगत कराया। जागरण

जम्मू-कश्मीर को जल्द मिलेगा बड़ा औद्योगिक पैकेज : गोयल

▶ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बोले- कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्रीय वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर देश का हीरा है। इस प्रदेश के लिए जल्द बड़ा औद्योगिक पैकेज दिया जाएगा। कश्मीर हमेशा धरती का स्वर्ग रहेगा। घाटी के सुरक्षित माहौल में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पूरी उम्मीद हैं कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। जम्मू जिले के अखूनर में आउटरीच प्रोग्राम के बाद रविवार दोपहर को जम्मू एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता में गोयल ने कहा कि अगले साल तक 111 किलोमीटर कटड़ा-बनिहाल रेल लिंक बन जाने से विकास को तेजी मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में सात महीनों में विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। यह मुहिम जून 2018 को राज्यपाल शासन लागू होने के बाद शुरू हुई थी। सात दशकों से नजरअंदाज जम्मू-कश्मीर के लोग अब तेज विकास की इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि पहले रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम धीमी गति से चल रहा था। अब इसे तेजी दी गई है। फंड खत्म हो जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीफोन पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त फंड जारी कर दिया। अन्य कई प्रोजेक्टों को भी तेजी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों का विकास हो। मोदी सरकार के मंत्री जम्मू कश्मीर में अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच असलियत रख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व उसके सहयोगी दल जम्मू-कश्मीर में विकास देखना चाहते थे।

139 कैदी रिहा होंगे झारखंड की जेलों में बंद। बंदी हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी।

कार्यक्षेत्र में भी पति की बॉस बनी आइपीएस वृंदा शुक्ला

जागरण संवाददाता, नोएडा

- उप्र के दो जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद वृंदा डीसीपी तो पति अंकुर बने हैं एडिशनल डीसीपी
- दोनों मूलरूप से अंबाला के रहने वाले हैं, फरवरी 2019 में हुई थी शादी

वृंदा शुक्ला, डीसीपी। जागरण आकाईव

अंकुर अग्रवाल, एडीशनल डीसीपी। जागरण आकाईव

पत्नी घर में तो बॉस होती है, लेकिन अगर कार्यक्षेत्र में भी वह पति की बॉस बन जाए, तो कहना ही क्या? जी हां, आइपीएस वृंदा शुक्ला और आइपीएस अफसर अंकुर अग्रवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों बचपन में साथ खेले, स्कूल में साथ पढ़े, मोहब्बत हुई, तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने की भी फिक्र हुई। मेहनत की और दोनों आइपीएस बन गए। वर्षों की दोस्ती के बाद एक साल पहले ही अपनी इसी मोहब्बत को मुकाम तक पहुंचाया और सात फेरे ले लिए। इसे संयोग ही कहें कि अब एक ही शहर में दोनों साथ काम करेंगे। बस अंतर यह है कि वृंदा पत्नी होने के नाते घर में तो बॉस हैं ही फील्ड में भी वह अंकुर अग्रवाल की बॉस ही रहेंगी।

दोनों को गौतमबुद्ध नगर में मिली है तैनाती : दरअसल, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात रहीं वृंदा शुक्ला को यहां का पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बनाया गया, जबकि अंकुर अग्रवाल को एक माह पहले नोएडा का एसपी सिटी बनाया गया था।

कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद अब वह अपर पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह मथुरा में एएसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। आइपीएस दंपती मूलरूप से हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। आइपीएस अंकुर अग्रवाल ने बताया कि दोनों ने अंबाला कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़ाई की है।

इसके बाद वृंदा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं, जबकि वह खुद बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राजस्थान चले गए। उधर, पढ़ाई पूरी करने के बाद वृंदा शुक्ला अमेरिका में नौकरी करने लगीं, जबकि अंकुर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्ष तक बेंगलुरु में नौकरी की। इसके बाद वह भी अमेरिका चले गए। गौरतलब है कि उप्र के दो जिलों लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है।

अमेरिका में ही शुरू की सिविल सर्विसेज की तैयारी

अमेरिका में नौकरी करने के दौरान ही दोनों ने सिविल सर्विसेज की तैयारियां शुरू की। वृंदा ने दूसरे प्रयास में 2014 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की व आइपीएस बनी। उन्हें नगालैंड कैडर मिला। इसके दो वर्ष बाद अंकुर 2016 में सिविल सर्विसेज में चयनित हुए व आइपीएस बने। उन्हें बिहार कैडर मिला। बाद में दोनों ही उप्र आ गए। आइपीएस अंकुर अग्रवाल ने बताया कि नौ फरवरी 2019 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। जिले के इतिहास में यह पहला मौका है जब आइपीएस दंपती की नियुक्ति जिले में साथ हुई है।

बिहार में जवान ने पत्नी को एके-47 से किया छलनी

- 13 गोलियां पत्नी को और तीन गोलियां खुद को भी मारी

जासं, सीतामढ़ी : बिहार के सीमामढ़ी में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के जवान ने रविवार तड़के 3 बजे पत्नी को एके-47 से छलनी कर दिया। इसके बाद उसने भी गोली मारकर जान दे दी। सिर से पांव तक पत्नी को उसने 13 गोलियां दागी जबकि उसने खुद को तीन गोलियां मारीं।

सूचना मिलने पर एसपी अनिल कुमार समेत पुलिस मौके पर पहुंची। पति-पत्नी पुलिस लाइन के ठीक बगल वाले मोहल्ले में किराए पर रह रहे थे। पिछले साल 18 दिसंबर को ही दंपती ने एक कमरे का मकान लिया था। फारेंसिक टीम की जांच व साक्ष्य जुटाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के कारण का पता नहीं चल सका था। जानकारी के अनुसार 2015 बैच का जवान चंद्रभूषण कुमार मूलरूप से सहरसा का निवासी था और यहां पुलिस की क्यूआरटी में कमांडो था। छह माह पहले उसकी शादी मधु देवी (24) से हुई थी। वह भी सहरसा की रहने वाली थी।

शनिवार रात 10 बजे जवान ड्यूटी के बाद कमरे पर आया था। रविवार सुबह क्यूआरटी के जवान उसकी खोज में पहुंचे। जवानों ने बताया कि मानव श्रृंखला में उसकी ड्यूटी लगी थी। फोन करने पर जवाब नहीं मिल रहा था। उसके कमरे पर आए तो दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी जब कोई सुगबुगाहट नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर खून के छींटों से कमरा लाल हो चुका था। दोनों के शव पड़े थे। सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है।

छात्रवृत्ति घोटाले में प्रबंधक समेत छह गिरफ्तार

जासं, हल्द्वानी: छात्रवृत्ति घोटाले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी के प्रबंधक और पांच दलालों को गिरफ्तार किया है। दलालों पर उप्र के दो निजी तकनीकी संस्थानों के प्रबंधन के साथ मिलकर छात्रों के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में एसआइटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही है। नैनीताल जिले में इस सिलसिले में एसआइटी ने भीमताल थाने में तीन मुकदमे दर्ज कराए थे।

पुलिस के मुताबिक छात्रवृत्ति घोटाले में वांछित उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी के प्रबंधक राकेश सिंह निवासी लालपुर थाना टांडा बादली, रामपुर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही, सुरजीत सिंह, दिनेश चौहान, संतराम तोमर, कल्याण सिंह नेगी और अनिल जुयाल को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये सभी बिचौलिये की भूमिका में थे।

न्यूज गैलरी

चंडीगढ़ से धर्मशाला की हवाई टिकट अब 1,260 रुपये में

चंडीगढ़ : पर्यटकों को रिझाने के लिए एयर इंडिया ने अपने किराये में 26 फीसद तक कटौती की है। एयर इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, अब धर्मशाला से चंडीगढ़ का किराया 1,712 की जगह 1,418 रुपये कर दिया गया है, जबकि चंडीगढ़ से धर्मशाला का किराया 1,260 रुपये प्रति टिकट कर दिया गया है। एयर इंडिया ने यह छूट 21 से 30 जनवरी तक दी है। स्टेशन मैनेजर एमआर जिंदल ने बताया कि अगर आप धर्मशाला से चंडीगढ़ में वोल्वो बस का सफर करते हैं तो 800 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। बावजूद इसके आप छह घंटे का सफर तय करते हैं। वहीं, फ्लाइट में यह टिकट आपको बेहद रियायती दर पर मिल रही है। ऐसे में यात्री इसका लुत्फ उठा सकते हैं। (जासं)

एसजीआरआइ एयरपोर्ट अमृतसर में विजिटर एंट्री बंद

अमृतसर: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय (एसजीआरआइ) एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज चंसोरिया ने शनिवार देर रात 12 बजे से विजिटर एंट्री पर रोक लगा दी है। अब एयरपोर्ट तक रिश्तेदारों को छोड़ने आने वाले मेहमानों को बाहर से ही अलविदा कहना पड़ेगा। इससे पहले लोग 75 रुपये का पास लेकर रिश्तेदारों को एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ने जा सकते थे। मनोज चंसोरिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर विजिट एंट्री 30 जनवरी तक बंद रहेगी। (जासं)

सुकमा में दो नक्सलियों ने किया समर्पण

सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा में दो नक्सलियों ने पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष रविवार को आत्मसमर्पण किया। इसमें एक रमेश पोडियामी नक्सलियों की मेडिकल टीम का सदस्य है। पुलिस ने बताया कि रमेश के साथ नक्सल संगठन का सदस्य सुकलू कवासी ने शुक्रवार को सरेंडर किया। रमेश पोडियामी ने बताया कि नक्सली संगठन में उसे प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण नक्सली विनोद की बेटी ने जंगमपाल, तोंगपाल के जंगलों में दिया था। उसके बाद नक्सलियों के साथ रहकर उनके छोटे-छोटे ऑपरेशन तक करने में दक्ष हो गया। दोनों नक्सली कटेकल्याण थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मारजूम के भीमापारा के रहने वाले हैं। (नईदुनिया)

लंदन से आई फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, नौ घंटे बाद लौटी

अमृतसर: लंदन से उड़ान भरकर श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर आई एयर इंडिया की फ्लाइट रविवार सुबह दिल्ली डायवर्ट कर दी गई। अमृतसर एयरपोर्ट पर गहरी धुंध में पायलेट सुबह 9.15 बजे विमान को लैंड नहीं करवा सका। मौसम ठीक होने के बाद यह फ्लाइट देर शाम 6.20 बजे अमृतसर वापस पहुंची, जो करीब सात बजे लंदन के लिए उड़ान भर गई। (जासं)

मौसम का मिजाजा ▶ उत्तराखंड में 300 गांव जिला मुख्यालयों से कटे, 400 गांवों में बिजली गुल

पहाड़ों में बर्फ व मैदान में हवा ने बढ़ाई ठंड

दिल्ली में हवा के चलते फिर कम होने लगा तापमान

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत में ठंड का कहर एक बार फिर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी ठंड बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर इलाके में तेज हवा के कारण रविवार को ठंड का अहसास बढ़ गया। हालांकि दोपहर में धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन हवा के चलते न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम के बदले इस मिजाज के कारण ठंढ में बढ़ोतरी हुई है।

उत्तराखंड में मौसम साफ, परेशानी बरकरार : उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के बाद रविवार को प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक धूप खिली तो लोगों ने राहत ही सांस ली। हालांकि बर्फ से लकदक गांवों में दुश्वारियां बरकरार हैं। प्रदेश में 300 से अधिक गांवों का संपर्क कटा हुआ है। करीब चार सौ गांवों में बिजली गुल है और करीब 30 सड़कों पर आवाजाही बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, लेकिन निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा।

पिछले दिनों हुई बर्फबारी से जोशीमठ-औली मोटर मार्ग बंद है। जोशीमठ-औली मार्ग पर पैदल आवाजाही करता पर्यटक। फोटो : जागरण

बर्फबारी रुकी, दिक्कत बढ़ी

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कुल्लू जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान में शामिल होने जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्फ पर फिसल कर मौत हो गई। वहीं, शनिवार को बर्फबारी और सड़कों पर कोहरे के कारण रातभर चले ढली से कुफरी के बीच गाड़ियों में फंसे 187 पर्यटकों को पुलिस ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग द्वारा 20 जनवरी से 22 जनवरी तक मौसम के खराब रहने के की संभावना जताई है। पर्यटकों को मौसम को ध्यान में रखकर यात्रा करने की एडवाइजरी जारी की है।

पहलगाम में माइनस 13 डिग्री रहा तापमान

जम्मू-कश्मीर में रविवार को खिली धूप से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन ठंडी रातें अब भी बेहाल कर रही हैं। बता दें कि कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की हल्की परत पाले की तरह जमी होती है। वादी में अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे है। दक्षिण कश्मीर में पहलगाम माइनस 13.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा क्षेत्र रहा।

पंजाब के मुक्तसर साहिब के पशु मेले में आए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के घोड़े। ब्रिटेन की फेलाबेला नस्ल के इन घोड़ों की ऊंचाई करीब तीन फीट है। जागरण

बादल के घोड़े की कीमत आठ लाख, सिर्फ देखकर लौटे लोग

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

माघी मेले में चार दिन तक चले पशु मेले में करोड़ों का कारोबार हुआ, लेकिन पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के घोड़े को कोई खरीदार नहीं मिला। युनाइटेड किंगडम से मंगवाए गए फलाबेला नस्ल के तीन फुट के इन घोड़ों पर लोग फिदा तो हुए, लेकिन कीमत आठ लाख होने के कारण सिर्फ देखकर लौट गए।

मेले में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के पशु व्यापारी आए। विभिन्न नस्ल के 1810 घोड़े पहुंचे थे, जिनमें 680 घोड़ों की बिक्री हुई। मेले में करीब 35 करोड़ रुपये के घोड़े बिके हैं।

सुखबीर के स्टड फार्म से आए थे आठ घोड़े सुखबीर सिंह बादल के स्टड फार्म से मेले में ज्यादातर घोड़े दिखाने के लिए लाए जाते रहे हैं, मगर इस बार आठ घोड़े बिक्री के लिए लाए गए थे। इनमें मारवाड़ी व नुकरा के अलावा यूके से मंगवाए फलाबेला नस्ल के घोड़े भी शामिल थे। मेला आयोजकों के अनुसार कीमत ज्यादा होने के चलते सुखबीर बादल के घोड़े नहीं बिके। सबसे महंगा घोड़ा दो लाख रुपये में ही बिका, जबकि सुखबीर के घोड़े की कीमत 8 लाख के करीब थी।

फलाबेला नस्ल के घोड़े की खासियत: मेले में आए फलाबेला नस्ल के घोड़ों की ऊंचाई तीन फुट के करीब है। एक घोड़े की कीमत करीब आठ लाख रुपये थी। दरअसल, ये सबसे छोटी नस्ल के घोड़े हैं। साहसी, बुद्धिमान और आसानी से प्रशिक्षित किए जा सकने के कारण इन्हें गाइड जानवरों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी देखभाल करने वाले ओमी सिंह ने बताया कि इन्हें सर्दी से बचाना जरूरी है। एक बार जुकाम हो जाए तो पूरी सर्दी ठीक नहीं होता।

शबाना आजमी की हालत स्थिर, चालक पर मुकदमा

- अभिनेत्री कार दुर्घटना में हो गई थीं गंभीर रूप से घायल
- मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में चल रहा उपचार

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर कार दुर्घटना में घायल अभिनेत्री शबाना आजमी (69) की हालत अब स्थिर है। वहीं, अभिनेत्री के चालक के खिलाफ तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रकाश ने बताया कि शबाना आजमी के चालक कमलेश कामत (38) को हादसे में मामूली चोट लगी है। कोल्हापुर के पास शनिवार को कमलेश एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। शबाना आजमी के पति गीतकार जावेद अख्तर दूसरी कार में थे।

प्रकाश ने बताया, 'कार चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया है। अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। कार को जांच के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भेजा जाएगा। जांच में यह पता चल पाएगा कि हादसे के वक्त गाड़ी में ही कोई कमी थी अथवा चालक के संतुलन खोने के कारण यह दुर्घटना हुई।' जांच में चालक के शराब पीने की पुष्टि नहीं हो पाई है।

हादसे के बाद शबाना को नवी मुंबई के एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संतोष शेट्टी ने बताया कि शबाना की हालत स्थिर है। उन्हें निगरानी में रखा गया है। रात में उनकी कोई सर्जरी या ऑपरेशन नहीं किया गया। दवाओं के जरिये उनका उपचार किया जा रहा है।

फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने कहा, अभिनेत्री की हालत बेहतर

फिल्म निर्माता सतीश कौशिक रविवार को शबाना आजमी को देखने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा, 'शबाना की सेहत शनिवार के मुकाबले बेहतर हुई है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना है।'

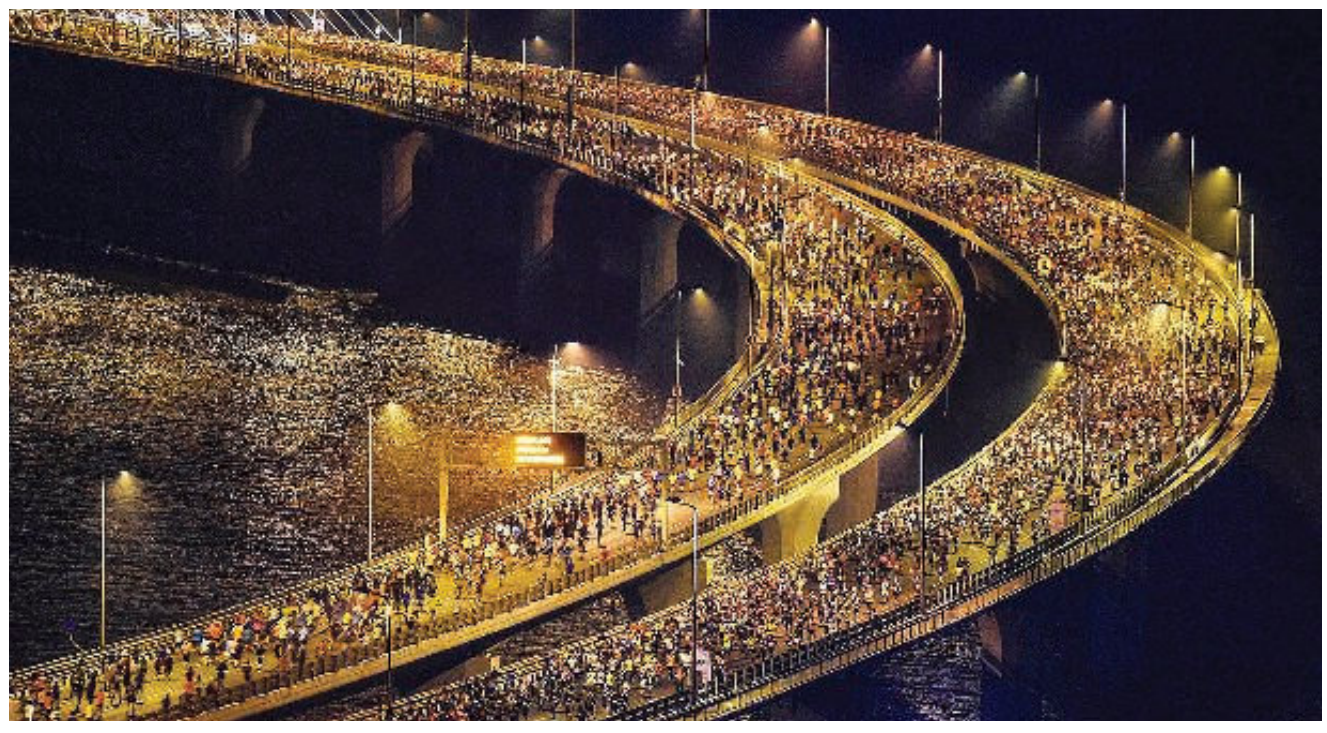

मुंबई में दौड़े 50 हजार लोग...

सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को टाटा मुंबई मैराथन 2020 में 50 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एशिया की इस सबसे बड़ी मैराथन के दौरान बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर लोग दौड़े। सात अलग-अलग श्रेणियों में आयोजित फ्री मैराथन में जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मैराथन का शुभारंभ किया। सैयद समीर (मिडडे)

जागरण विशेष

भोजन की तलाश में नेपाल से हर साल चला आता है एक झुंड, आधे से अधिक नहीं लौटते वापस, नवंबर-दिसंबर में आकर मार्च तक मचाते हैं खूब उत्पात, वनकर्मी बता रहे शुभ संकेत

किसानों के लिए आफत, तो जंगल के लिए बरकत!

अंकित कुमार, लखनऊ

- नेपाली हाथियों का डेरा शुक्लाफाटा से दुधवा, किशनपुर, मैलानी होते हुए पीलीभीत तक

जंगल की दुनिया में भी नागरिकता मुद्दे को लेकर हलचल मची है। यहां हंगामे की वजह बने हैं नेपाली हाथियों के झुंड, जो भोजन की तलाश करते हुए भारत में घुस तो आते हैं, मगर उनमें से आधे से अधिक वापस नहीं जाते। भारत की आबोहवा उन्हें इस कदर भा रही है कि यहां के जल-जंगल और जमीन पर काबिज होते जा रहे हैं। पिछले दो-तीन साल में ही ऐसे 'शरणार्थी' हाथियों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। अब ये हाथी हर साल उत्पात मचाते हैं, पर वन्यकर्मी उनकी आमद जंगल के लिए शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं।

नेपाल की शुक्लाफाट सेंचुरी और वार्दिया नेशनल पार्क तराई स्थित पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच के जंगल से जुड़े हैं। इंसानों की तरह ही बाघ, तेंदुआ, चीतल, हिरन, भालू आदि जानवर भी बिना रोक-टोक दोनों देशों की सीमाओं में हमेशा से विचरण करते हैं। बीती सदी के दसवें दशक से पहले तक हाथियों का जमावड़ा नेपाल तक ही सीमित था, लेकिन 1990 के बाद अचानक उनका रुख भारतीय जंगल की तरफ बढ़ने लगा। शुरुआत में सीमावर्ती इलाकों तक सिमटे रहे मगर धीरे-धीरे उन्होंने शुक्लाफाटा से लखीमपुर खीरी के किशनपुर, मैलानी, दुधवा, बहराइच के कतर्नियाघाट समेत पीलीभीत तक करीब 300 किमी लंबा स्वयंभू कॉरिडोर बना लिया।

तब से हर साल नवंबर-दिसंबर के बीच 50 से 70 हाथियों का झुंड भारत की सीमा में दाखिल होता है और तीन-चार महीने गुजारने के बाद वापस लौट जाता। एक समय के बाद नेपाली हाथियों की वापसी स्वतः होती रही तो वनकर्मियों ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर करीब तीन साल से इन हाथियों के व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव आया है। वे झुंड बनाकर आते तो हैं, लेकिन हर बार करीब आधे यहीं के होकर रह जाते हैं। इसी के चलते धीरे-धीरे दुधवा जंगल में शरणार्थी हाथियों का कुनबा 100 के पार पहुंच गया है, जबकि कर्तनिया घाट क्षेत्र में 50 से अधिक हाथी मुश्किल बने हैं।

नहीं निकल रहा हल

भारत में हंगामा मचाने वाले इन हाथियों का मुद्दा डिप्लोमेसी की मेज तक पहुंच गया है। अब नेपाल इन हाथियों को अपना नहीं मान रहा। इसी टकराव के चलते दोनों देशों के बीच बैठकें जारी हैं। पिछले महीने पीलीभीत में प्रदेश के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सुनील पांडेय शुक्लाफाटा, नेपाल के वाइल्ड लाइफ वार्डन लक्ष्मण प्रसाद कौड़ियाल के बीच बैठक हुई, मगर कोई हल नहीं निकल पाया।

मैलानी के जंगल में जलाशय किनारे जुटा नेपाल से आया हाथियों का झुंड की फाइल फोटो। जागरण

नेपाली हाथियों के आने का चलन पुराना है, मगर अब हालात बदल रहे हैं। नेपाल के सीमाई इलाके जंगल कटने से उनका आशियाना सिमट रहा है। भोजन का संकट भी है, जिसकी तलाश में वे भारत का रुख करते हैं। यहां उन्हें रहने के लिए पर्याप्त जगह और खाने के लिए वनस्पति, गेहूं, गन्ने की फसल मिल जाती है। चूंकि जंगली हाथी अपने निर्धारित कॉरिडोर पर चलते हैं, इस कारण अक्सर रास्ते में पड़ने वाली फसलें और छप्पर आदि भी उजाड़ देते हैं। उत्पात मचाते हैं। किसानों पर हमला करते हैं। कुछ को मौत के घाट भी उतार चुके हैं।

-संजय पाठक, फील्ड डायरेक्टर, दुधवा नेशनल पार्क

हाथियों का झुंड सीमावर्ती किसानों के लिए बेशक मुश्किल है, मगर जंगल के लिए शुभ संकेत है। यह चलायमान होता है और अत्याधिक भोजन करता है। इसलिए भविष्य में नेपाली हाथी ग्रास लैंड प्रबंधन में मददगार साबित हो सकते हैं।

-डॉ. वीपी सिंह, सचिव, तराई नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

परिवारों को टूटने से बचाएगी विहिप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) विशेष अभियान चलाकर परिवार टूटने से बचाएगी। इसके लिए देशभर में एक हजार कार्यकर्ताओं को परिवार संस्कार का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्यकर्ता अपने जिलों में कमेटियां बनाकर हर जिले में दो-दो हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे, जो विशेष वर्ग लगाकर परिवारों को संस्कार सिखाएंगे। मकसद परिवारों को टूटने से बचाना है।

माघ मेला में त्रिवेणी मार्ग स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में 20 जनवरी को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। 21 जनवरी को संत सम्मेलन होगा। शिविर में ही 21 जनवरी से परिवार संस्कार प्रशिक्षण होगा। इसमें देश के हर जिले से जिला मार्गदर्शक मंडल के संयोजक व जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शामिल होंगे। विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र ने बताया कि स्वामी सत्यमित्रानंद के कृपापात्र व कांची कोटि शंकराचार्य के शिष्य गोविंद देव गिरि प्रशिक्षक के तौर पर बुलाए गए हैं।

दैनिक जागरण
बेहतर भविष्य की बुनियाद वर्तमान में रखी जाती है

सिब्बल का सच

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने यह कहकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों और साथ ही राजनीतिक दलों को आईना ही दिखाया कि कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से इन्कार नहीं कर सकती। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं। कपिल सिब्बल ने तो वही कहा जो विधिसम्मत और न्यायसंगत है। विडंबना यही है कि यह सीधी-सच्ची बात कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को भी नहीं समझ आ रही है। वास्तव में यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे बुनियादी संवैधानिक स्थिति को न समझने का दिखावा करने में लगी हुई हैं। शायद वे भाजपा विरोधी अन्य दलों की सरकारों से होड़ ले रही हैं और इसीलिए पंजाब विधानसभा ने यह जानते हुए भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि उसका कोई मूल्य-महत्व नहीं। यही काम केरल विधानसभा भी कर चुकी है। यह और कुछ नहीं, संवैधानिक अपरिपक्वता का शर्मनाक उदाहरण ही है। ऐसे उदाहरण पेश कर न केवल भारतीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को खुराक देने का काम भी किया जा रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने में लगे हुए हैं।

यह शायद पहली बार है जब विपक्षी राजनीतिक दल सच को झूठ की शक्ल देकर आम लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। यह तय है कि सच से अवगत होने पर लोग न केवल खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, बल्कि अपने को बरगलाने वाले दलों को कोसेंगे भी। इस पर आश्चर्य नहीं कि कपिल सिब्बल के बयान को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी सही माना। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद भी हैं। कम से कम अब तो कांग्रेस को नागरिकता संशोधन कानून के मामले में झूठ की राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। इस राजनीति का औचित्य इसलिए भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चंद दिनों बाद उन तमाम याचिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई हैं। इनमें एक याचिका तो कांग्रेस के नेता की ही है और एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील खुद सिब्बल हैं। आखिर जब इस कानून के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी सक्रिय है तब फिर वह लोगों को उकसा कर सड़कों पर क्यों उतार रही है? शायद उसके ऐसे ही आचरण पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी को एक अक्षम नेता करार दिया। कांग्रेस उनसे नाराज हो सकती है, लेकिन उनका यह आकलन सही है कि नरेंद्र मोदी के आगे राहुल कहीं नहीं ठहरते और उनके प्रभावी रहते कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।

संदेश देती पहल

जब समाज का हर पक्ष जागरूक हो तो कुरीतियों से पार पाना संभव हो सकेगा। हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां थीं, लेकिन जागरूकता के साथ उनका अंत हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि अधिकतर कुरीतियों से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं ही होती रही हैं। समाज में अब भी यदि किसी के पति का छोटी उम्र में ही निधन हो जाए तो उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जो कुरीतियों से लड़ने का मादा रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की रखोह पंचायत के गध्यानी गांव के ब्रह्मदास ने समाज के समक्ष मिसाल पेश की है। शादी के कुछ समय बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने बहू का बेटी की तरह विवाह करवाया और अपने आंगन से विदा किया। यही नहीं बहू की शादी पर उन्होंने धाम (भोज) का भी आयोजन किया। बहू की शादी की बात करने में उन्हें संकोच भी होता था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए इसे अंजाम तक पहुंचाया। निःसंदेह यह उन लोगों के लिए एक सबक है, जो आज भी विधवा विवाह को बुरा समझते हैं। ऐसे जागरूक एवं संवेदनशील लोगों के कारण ही कुरीतियों का खात्मा हुआ है। सोलन जिले में भी अर्की पंचायत में एक बेटी ने मुखाग्नि दी। इस तरह के मामले हिमाचल प्रदेश में पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां बेटियों ने अपने स्वजनों के अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं। यह उन लोगों के लिए आईना है जो यह समझते हैं कि बेटे ही घर का चिराग हैं। यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि अगर बेटे घर का चिराग हैं तो बेटियां भी लक्ष्मी हैं। बेटियों ने अपनी काबिलियत से अपना ही नहीं अपने परिजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह भी सुखद है कि यहां पर कई परिवारों ने बेटियों को अहमियत दी है। कई लोगों ने एक ही बेटी के बाद परिवार नियोजन कर लिया और उसे ही अच्छी बेहतर शिक्षा दिला रहे हैं। इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि कुरीतियों को चंद लोग ही ढो रहे हैं जबकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग पुरानी बातों को नहीं मानता है। जागरूक समाज में कोई भी कुरीति अधिक समय तक नहीं रह सकती है। इस बात को समझना होगा कि जब समाज तय कर ले तो किसी भी कुरीति का अंत कर सकता है।

सोच में बदलाव लाकर ही कुरीतियों से पार पाया जा सकता है। मंडी में बहू को बेटी बना विदा करना समाज को सार्थक संदेश दे रहा है

राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन

हृदयनारायण दीक्षित

भारत के राज्य और उनके मुख्यमंत्री स्वायत्त संस्था नहीं हैं, लेकिन कुछ सूबों के सत्ताधीश सीएए पर संवैधानिक संघ से टकराने का आचरण कर रहे हैं

संविधान की दुहाई और संविधान पर ही हमला। कई मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी पर सीधा हमला किया है। उन्होंने अपने राज्यों में कानून न लागू करने की असंवैधानिक घोषणा भी की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 'आप कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने का काम राज्य सरकार का है। हम उसे लागू नहीं करेंगे।' पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संसद की विधायी क्षमता पर ही सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसे लागू न करने की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसे विभाजनकारी बताते हुए राज्य में लागू न करने का हठ प्रदर्शित किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बयान भी संविधानसम्मत नहीं हैं। इनका आचरण राज्यों के विधि निर्वाचित शासक जैसा नहीं है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्रीगण अपने राज्यक्षेत्रों को भारतीय राष्ट्र राज्य से भिन्न अलग देश मान रहे हैं? क्या वे अपने राज्यों के संप्रभु सम्राट हैं? वस्तुतः सभी राज्य भारतीय संविधान के अधीन भारत संघ के अविभाज्य अंग हैं। मुख्यमंत्रियों के अधिकार व कर्तव्य संविधान में सुस्पष्ट हैं। संसद द्वारा पारित कानून लागू करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। संसद द्वारा पारित कानून लागू न करने की घोषणा संवैधानिक अराजकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी संसद द्वारा पारित कानून के न लागू करने को असंवैधानिक कहा है।

कानूनों का प्रवर्तन राज्यों का ऐच्छिक अधिकार नहीं है। यह राज्यों का बाध्यकारी कर्तव्य है। संविधान में अनुच्छेद 256 शीर्षक 'राज्यों की और संघ की बाध्यता' है। संविधान के अनुसार 'प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे।' संसद द्वारा बनाए कानून व राज्य में प्रवर्तित अन्य कानूनों का प्रवर्तन राज्य की ही जिम्मेदारी है। इसी अनुच्छेद में केंद्र के लिए भी निर्देश हैं, 'संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देना है, जो केंद्र को उक्त प्रयोजनों के लिए जरूरी प्रतीत हो।' कानून लागू कराने के संबंध में केंद्र को सिर्फ निर्देश देना है। राज्य उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 257 में राज्यों को निर्देश है कि 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाए जिससे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। केंद्र इसके लिए भी राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है।' तब मुख्यमंत्री बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन न करने के दोषी क्यों नहीं हैं? संविधान की शपथ लेकर भी संविधान पालन से इन्कार करने का औचित्य वही बता सकते हैं।

कानून लागू न करने का एलान असाधारण संवैधानिक अवमानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद में विश्वास करते हैं। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी भी इसे बर्दाश्त करतीं? संविधान के एक उपबंध (अनुच्छेद 365) के शीर्षक 'संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव' वाला हिस्सा पठनीय है, 'जब इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।' ऐसी परिस्थिति के लिए ही अनुच्छेद 356 में 'राष्ट्रपति शासन की वैकल्पिक व्यवस्था है।' मुख्यमंत्रीगणों के लिए उनकी घोषणा से जुड़े यह संवैधानिक उपबंध पुनर्पाठ योग्य हैं। वे कह सकते हैं कि वे इससे नहीं डरते, लेकिन संविधान से उनका बेखौफ होना लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है।

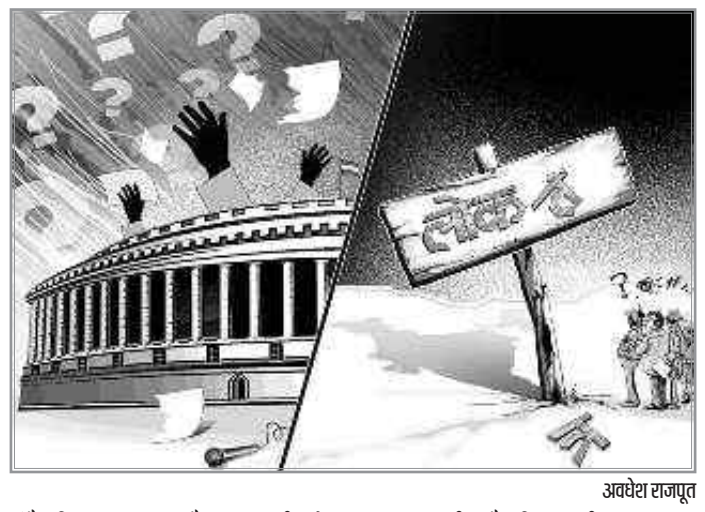

अवधेश राजपूत

कानून की संवैधानिकता की बहस अलग विषय है, लेकिन मुख्य प्रश्न यही है कि क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानूनों के प्रवर्तन के कर्तव्य पालन से मुकर सकती है? यह संवैधानिक अराजकता जैसा है। केरल और पंजाब में सरकारों ने तो विधानसभा में भी प्रस्ताव कराए हैं। अनुच्छेद 246 में संसद व विधानमंडलों की विधायी शक्ति के विषयों का बंटवारा है। वहीं सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में नागरिकता है। विधानसभा को इस विषय पर बहस का अधिकार नहीं है। वे जानते हैं कि इस प्रस्ताव का प्रभाव शून्य है, बावजूद इसके विधानसभा के सम्मानित मंच का दुरुपयोग किया। ऐसे प्रहसन दलीय मंचों के लिए बेशक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सदनों की गरिमा को गिराने वाले हैं।

कुछेक टिप्पणीकारों ने इस कृत्य को संघीय ढांचे की मजबूती बताया है। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि 'प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। इसके दो लाभ हैं। (क) भारतीय परिसंघ राज्य इकाइयों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। (ख) संघटक इकाइयों को उससे विलग होने के अधिकार नहीं हैं।' भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिकी राज्यों ने मिलकर 'संयुक्त राज्य अमेरिका परिसंघ बनाया था।' अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने इसे 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा था। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 'भारतीय संघ को ढीली-ढाली संरचना बताया और कहा कि यह नाशवान इकाइयों का अनाशवान संघ है।' यहां राज्य बनाए जाते हैं, छोटे या बड़े भी किए जाते हैं। भारत के राज्य और उनके मुख्यमंत्री स्वायत्त संस्था नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्यों के सत्ताधीश संघ से टकराने का आचरण कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा के क्षरण से राजनीति हास्यास्पद हो रही है। ऐसा आचरण संघवाद नहीं, अलगाववाद है।

पांच दिन बाद हमारा गणतंत्र 70 वर्ष पूरे कर रहा है। संसदीय व्यवस्था ने कई अनुभव दिए हैं, लेकिन इस दौरान चुनावी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बेशक हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, फिर भी व्यावहारिक राजनीति में संविधान और जनतंत्र के प्रति निष्ठा वाला राष्ट्रभाव नहीं है। आखिर संसद द्वारा पारित कानूनों के पालन से मुख्यमंत्री कैसे इन्कार करेंगे। वे इसका गलत औचित्य भी सिद्ध करेंगे तो आम नागरिक को जनतंत्र और संविधान का पाठ कौन पढ़ाएगा? यहां संसदीय विधि की ही अवमानना नहीं, बल्कि विधि स्थापित धारणा को भी चुनौती है। भारतीय ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते। सो ऐसी राजनीति का समर्थन लगातार घट रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता समय का आह्वान सुनें। आत्मनिरीक्षण करें। संविधान और लोकतंत्र की निष्ठा का कोई विकल्प नहीं है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

सिनेमा में धर्म की महत्ता

धीरज शर्मा

हैरानी होती है कि क्या बॉलीवुड भारतीय समाज में धर्म के महत्व की जानबूझकर अनदेखी करता है

कुछ दिन पहले 'तान्हाजी' फिल्म देखी। उसे देखकर लगा कि 'भगवान' ने बॉलीवुड की धारा में फिर से दस्तक दी है। इसमें दिखाया गया कि दुर्ग पर धावा बोलने से पहले तान्हाजी मंदिर में पूजा करते हैं। ऐसे दौर में जब लगा कि बॉलीवुड ने भगवान को लगभग भुला ही दिया, वहां रुपहले पर्दे पर भगवान यकायक प्रकट हुए। प्रख्यात दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने 135 साल पहले दावा किया था कि 'गॉड इज डेड' यानी ईश्वर मृतप्राय हो गया है। उनकी दलील थी कि दुनिया को अब ईश्वर की जरूरत नहीं रह गई है और विज्ञान मानव जाति को सब कुछ उपलब्ध कराने में सक्षम है। नीत्शे का कहना था कि साहस, हौसला और आकांक्षा ही किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तब अमेरिकी समाज पर नीत्शे के प्रभाव का अनुमान लगाया गया। हालांकि साक्ष्य इसके उलट रहे। बीते एक दशक के कई सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि दुनिया में सबसे आधुनिक देश माने जाने वाले अमेरिका में धार्मिक आस्था खासी मजबूत बनी हुई है। करीब 60 से 85 फीसद अमेरिकी धर्म को बहुत महत्व देते हैं। यह नीत्शे के अनुमान के एकदम उलट है।

ऐसे में किसी को हैरानी हो सकती है कि दुनिया के सबसे आधुनिक देश को भी आखिर धर्म का सहारा क्यों चाहिए? भारत में भी कुछ यही रुझान दिखता है। तमाम लोग मानते हैं कि आर्थिक विकास के साथ धर्म की आभा फीकी पड़ती है। हालांकि अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी फिल्मों में भी देश की धार्मिक आस्था प्रतिबिंबित होती है। अतीत में हुए तमाम शोध-अध्ययन बताते हैं कि फिल्में अमेरिकी संस्कृति का एक प्रभावी पहलू हैं। हाल में देखा गया है कि ईसाई धर्म पर आधारित फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी भारी कमाई की। अधिकांश अमेरिकी मानते हैं कि वे अपने समाज में धर्म को उचित स्थान दिलाएं। जब माइक पेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति बने तो उनके एक बयान ने सुर्खियां बटोरीं जिसमें धर्म की अहमियत स्पष्ट रूप से दिखती है। पेंस ने कहा था, 'सबसे पहले मैं एक ईसाई हूं, फिर परंपरावादी और आखिर में रिपब्लिकन।' पहले से प्रभावी धर्म के रूप में ईसाइयत अमेरिकियों के जीवन में अहम है जो हमें हॉलीवुड फिल्मों में दिखता भी है।

इसे देखते हुए भारत में पहले से प्रभावी धर्म (हिंदू) के भारतीय समाज और बॉलीवुड पर उसकी छाप की पड़ताल खासी दिलचस्प होगी। इसके लिए तमाम पुरानी फिल्मों को याद किया जा सकता है जिनमें दर्शकों की आस्था को चुनौती देने के साथ ही भगवान की शरण में जाने वाले दृश्य भी थे। ऐसी फिल्मों का अंत अमूमन आस्था और अच्छे मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ होता। इसमें 'दीवार' फिल्म में ईश्वर के साथ अमिताभ बच्चन के संवाद का यादगार दृश्य हो या फिर तमाम फिल्मों में अदालती कार्यवाही के दौरान गीता पर हाथ रखकर गवाही देने वाते दृश्य याद आते हैं। बहरहाल इसकी व्यापक पड़ताल के लिए मैंने और मेरी शोध टीम ने 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 और 2010 के दशक की पचास-पचास फिल्में चुनीं। इसमें सामने आया कि 1960 के दशक की शीर्ष फिल्मों में से तकरीबन 68 प्रतिशत में भगवान से जुड़ा कोई न कोई संदर्भ अवश्य रहा। इनमें या तो भगवान से मनुहार की गई या फिर उनसे रोष व्यक्त किया गया। 1970 में 62 प्रतिशत के साथ यह आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। फिर 1980 के दशक में यह 60 प्रतिशत पर पहुंचा, लेकिन 1990 के दशक में इसमें बहुत तेजी से गिरावट आई और यह 42 प्रतिशत पर आ गया। फिर 2000 के दशक में यह और गिरकर 20 प्रतिशत हो गया और 2010 के दशक में तो महज 12 प्रतिशत पर आकर ठिठक गया। साथ ही साथ इस दौरान बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना भी की गई।

तब यह समाज को कैसे प्रभावित करता है? इसके समाज पर प्रभाव की पड़ताल के लिए हमने एक प्रयोग किया। यह प्रयोग सौ एकाएक चुने गए विषयों को लेकर 21 से 25 वर्ष आयुवर्ग को आधार बनाकर किया गया। हमने किसी खास बॉलीवुड फिल्म को देखने से पहले और देखने के बाद लोगों की धार्मिकता का जायजा लिया। हमने पाया कि इसमें लोगों की धार्मिकता के स्तर में वृद्धि या कमी देखने को मिली। इस परिप्रेक्ष्य में रणनीतिक स्तर पर हमें 1960 और 1970 के दशक में तमिल फिल्मों के प्रभाव की पड़ताल भी अवश्य करनी चाहिए जिन्होंने भाषा, राष्ट्र और समाज के बारे में तमिलों के नजरिये को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस बात पर हैरानी ही होती है कि क्या बॉलीवुड भारतीय समाज में धर्म के महत्व की जानबूझकर अनदेखी करता है।

भारतीय समाज की सामर्थ्य एवं सफलता आस्था के इर्दगिर्द घूमती है। मिसाल के तौर पर क्या हमें लगता है कि हमारे पास कानून एवं व्यवस्था का अचूक तंत्र या त्वरित न्याय करने वाली प्रणाली है? अगर इसका जवाब 'नहीं' है तब हमारी इतनी बड़ी आबादी व्यापक रूप से शांतिप्रिय और नैतिकता से ओतप्रोत कैसे है? यह संभवतः उन मूल्यों के कारण ही है जो भारतीयों में मजबूत आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जो शायद कानून की किताब और आइपीसी जैसी जटिल चीजों को नहीं समझते, परंतु अपने दृढ़ मूल्यों के कारण उपद्रव या कुटिलता से बचते हैं। हालांकि बॉलीवुड अतीत की तुलना में आस्था को अब उतना महत्व नहीं देता, बल्कि उसका उपहास ही अधिक उड़ाता है। इससे भारत में आस्था की विकृत व्याख्या का जोखिम बढ़ा है और तमाम स्वयंभू इसका फायदा उठाते हैं। इस तरह हम शायद उस स्थिति से परे जा चुके हैं जिसमें धर्म का ऐसा महिमामंडन होता जो हमारे मूल्यों को संरक्षित करता था। उसके उलट अब ऐसी स्थितियों से दो-चार हो रहे हैं जहां धर्म को नुकसान पहुंचाकर हमारी उन पोषित परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है जिनके महत्व की भारतीय समाज में व्यापक स्वीकृति रही। इस दौर में हमें धर्मांधता से बचते हुए धर्म के शाश्वत मूल्यों और उसकी भली परंपराओं का लाभ उठाना चाहिए।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निष्काम कर्म

कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म ही सृष्टि का आधार है। कर्म के बिना जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर कर्म किए बिना कोई कैसे रह सकता है? स्वयं ईश्वर भी कर्म से रहित नहीं हो सकते। कर्म की बड़ी महिमा है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण भी है और बंधन से मुक्ति का कारण भी। अशुभ कर्म बंधन का कारण है तो शुभ कर्म बंधन से मुक्ति का कारण है। सकाम कर्म बंधन का कारण है तो निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति का कारण है। जाहिर है यदि हमें अपने जीवन में बंधनों से मुक्त रहना है, द्वंद्वों से मुक्त रहना है, दुखों से मुक्त रहना है और सदा आनंदित रहना है तो हमारे कर्म भी निष्काम होने चाहिए।

हम सदैव शुभ कर्म करें, पर सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि कामना के साथ किए गए शुभ कर्म भी अंततः हमारे लिए बंधन का ही कारण बनेंगे, दुखों का ही कारण बनेंगे। कामना पूर्ण कर्म भी हमारे आनंद में बाधक होंगे, हमारी मुक्ति एवं मोक्ष में बाधक होंगे और ईश्वरोपलब्धि में बाधक होंगे। इसलिए हमें शुभ कर्म करना तो है, पर कामनारहित होकर, अनासक्त होकर, कर्म में कर्तापन की भावना से मुक्त होकर, कर्म में सफलता मिले या असफलता उससे अविचलित होकर, जीवन में मान मिले या अपमान, जीवन में हर्ष हो या विषाद दोनों में सम रहकर, दोनों ही स्थिति में अविचलित रहकर, क्योंकि जब हम स्वयं को कर्म के परिणाम से जोड़ लेते हैं, कर्मफल से जोड़ लेते हैं तो हम सदैव ही सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हैं। हम सदैव ही व्यथित और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि कर्म का परिणाम कभी हमारी आशा के अनुकूल आ सकता है और कभी प्रतिकूल भी।

अनुकूल परिणाम पाने पर हम हर्षित होंगे तो प्रतिकूल परिणाम पाने पर हम दुखी तो होंगे ही। अतः हमें कर्म में कर्मफल की आशा और आसक्ति का त्याग करना है तभी हम सुख और दुख, हर्ष और विषाद, आशा और निराशा से ऊपर उठकर उन दोनों से मुक्त होकर स्थायी आनंद की अनुभूति कर सकेंगे।

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

जिंदगी कम कर रहा अकेलापन

अनीश कुमार

एक शोध में यह बात सामने आई है कि आपको जितना नुकसान मोटापा, शराब और सिगरेट से होता है, उतना ही नुकसान अकेले रहने से भी होता है। अकेलापन भले ही आपको कोई बीमारी नहीं लगे, पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सेन डियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन विभाग के शोधकर्ताओं की मानें तो स्वास्थ्य के मामले में आज यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है, खासकर वयस्कों में। यह शोध अकेलेपन को लेकर लोगों को चेताने की कोशिश कर रहा है। इसमें पाया गया है कि अकेला जीवन जीने या अकेलापन महसूस करने से आप विकलांगता, यहां तक कि असमय मृत्यु के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं।

यह शोध जर्नल एजिंग एंड मेंटल हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। अकेलेपन का सबसे पहला कारण उम्र बढ़ने पर होने वाले बदलाव और सामाजिक कौशल का न होना ही माना जाता है। बुढ़ापे में लोग अक्सर खुद को बहिष्कृत महसूस करने लगते हैं। वहीं नए जमाने के साथ वे खुद को काफी पीछे समझते हैं। इसलिए भी अकेलेपन की भावन उनमें जन्म ले लेती है। बढ़ती उम्र में अकेलापन महसूस करने का दूसरा कारण अपने साथी या करीबी की मौत होता है और खास बात यह भी होती है कि इस उम्र में लोग नए दोस्त नहीं बना सकते। अकेलेपन की भावना ज्यादातर जीवन में उद्देश्य की कमी के साथ भी जुड़ी होती है। अवसाद और अकेलापन यूं तो अलग-अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की वजह से भी हो सकते हैं। अवसाद का कारण अकेलापन हो सकता है, लेकिन अकेलापन की वजह अवसाद हो ये जरूरी नहीं। अकेले होने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से अकेले होना नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार में भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि कोई उन पर ध्यान नहीं देता और उनसे प्यार नहीं करता। अकेलेपन की वजह से नकारात्मक विचार पैदा होते हैं और यह मानसिक अवसाद को जन्म देता है।

आज भले ही अकेले रहकर आप मन की करते हों, लेकिन उम्र बढ़ने पर यही अकेलापन आपके लिए परेशानी ला सकता है

अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि अकेले रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी होने का खतरा बाकियों की तुलना में 29 प्रतिशत ज्यादा होता है। स्ट्रोक होने का खतरा 32 प्रतिशत ज्यादा होता है। जो लोग अकेलेपन से जूझते हैं वे ठीक से सो नहीं पाते। अच्छी नींद न होने की वजह से स्ट्रोक, दिल की बीमारी होने का खतरा होता है। साथ ही डायबिटीज का भी बढ़ जाता है। अकेलापन दूर करने के लिए कुछ लोग नशा, धूम्रपान आदि को अपनाते हैं और इसके दुष्प्रभावों का शिकार होते हैं। एक शोध में पाया गया है कि अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आप किसी भी वायरल बीमारी का शिकार जल्दी होते हैं। अकेलापन खत्म करने के लिए लोगों से मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब अकेले हों तो अपने शौक और प्रतिभा पर ध्यान दें। अपनी पसंद का काम करने में आप कभी बोर नहीं होंगे और अकेला भी महसूस नहीं करेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विपक्ष की संविधान विरोधी अराजकता

सीएए पर सस्ती राजनीति शीर्षक से युक्त अपने लेख में संजय गुप्त ने सीएए का बेजा विरोध करने वाले विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट किया है कि यह मुस्लिम वोट बैंक की दूषित राजनीति है, जिसे सीएए की ओट में अंजाम दिया जा रहा है। वस्तुतः सीएए के नाकाम विरोध से खीजा हुआ विपक्ष अब जिस संविधान विरोधी अराजकता की ओर बढ़ रहा है वह शरारतपूर्ण हठधर्मिता है, जिसे दरकिनार करने की जरूरत है। चूंकि केंद्र सरकार के फैसले राष्ट्रहित में हो रहे हैं और देश की संसद उसका समर्थन कर रही है, ऐसे में विधिसम्मत नागरिकता संशोधन कानून का विरोध न केवल असंवैधानिक है, अपितु यह मुस्लिम वर्ग को बरगला कर की जाने वाली वोटबैंक की विकृत राजनीति का नग्न प्रदर्शन भी है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रायोजित धरना इसका उदाहरण है जो अब विपक्षी नेताओं के लिए सत्ता विरोधी भड़ास निकालने का मंच बन गया है, लेकिन जब सत्तापक्ष ने संयम बरतते हुए इस मुद्दे पर विपक्ष के झूठे दुष्प्रचार को अनदेखा कर सीएए को अधिसूचित कर दिया तो विपक्ष सन्न रह गया। सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका नाजायज विरोध करने में नाकाम विपक्ष अब मरता क्या न करता की तर्ज पर अपने द्वारा शासित राज्यों में सीएए कानून को लागू न करने का असंवैधानिक प्रस्ताव पारित कर रहा है। केरल, पंजाब और बंगाल इसके उदाहरण हैं जहां पर इस तरह की संविधान विरोधी अराजकता बरती जा रही है। क्या देश की संसद से पारित किसी विधिसम्मत कानून को कोई राज्य सरकार अपने यहां लागू करने से मना कर सकती है? इस प्रश्न पर मंथन होने से पूर्व ही कानूनविद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार के सीएए कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकता। सिब्बल के इस बयान से समूचा विपक्ष इस सांसत में फंस गया है कि अब वह क्या करे? दूसरी ओर इन सबसे बेफिक्र सत्तापक्ष अब राष्ट्रहित में सीएए के बाद एनआरसी और एनपीआर लागू करने में व्यस्त है। देश के जन-मानस को राष्ट्रहित में कार्यरत सत्तापक्ष और संविधान विरोधी अराजकता की बढ़ते विपक्ष की विरोधाभासी मानसिकता को समझने की जरूरत है।

डॉ. वीपी पांडेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़

इतिहास लेखन

दैनिक जागरण के 17 जनवरी के अंक में प्रकाशित प्रो. मक्खन लाल का लेख, इतिहास के पुनर्लेखन में देरी, में इतिहास को फिर से लिखने व उसमें संशोधन की आवश्यकता का जिक्र किया है। लेकिन इसमें इतिहासकारों की भूमिका पर प्रकाश नहीं डाला है, जबकि इतिहासकार के विचार इतिहास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न यह है कि इतिहास लिखने वाला किसी पंथ या विचारधारा से तो नहीं जुड़ा है? यदि वह किसी पंथ अथवा विचारधारा से जुड़ा है तो कई बार वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते और हम ऐतिहासिक सच्चाई से दूर रह जाते हैं। आगे जाकर यही एतिहासिक घटनाएं विवाद बनकर अराजकता का रूप ले लेती हैं। जैसा कि अभी हाल में ही राजा सूरज मल के अधूरे चित्रण को लेकर फिल्म पानीपत में हुआ। इससे पहले भी कई बार एतिहासिक फिल्मों के विवाद सामने आ चुके हैं। अतः इतिहासकारों वा फिल्मकारों को अपने इतिहास लेखन व इसके चित्रण के इस कार्य को बखूबी पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता से ओतप्रोत होकर करना चाहिए। ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भारतीय इतिहास की वास्तविक और सटीक जानकार प्राप्त कर सकें।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

चुनावी हथकंडे

दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए नेता लोग ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाने में जुटे हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधाएं दे रखी हैं। इधर कांग्रेस के नेता सुभाष चोपड़ा ने भी यह एलान किया है कि सत्ता में आने के बाद वह मुफ्त पानी तो देंगे ही, साथ ही पानी बचाने पर कैश बैक भी देंगे। यह सुविधा तो किराएदारों को मिलनी चाहिए जो मकान मालिक उनसे मनमाने ढंग से किराया और बिजली पानी का पैसा वसूल रहे हैं, इसका समाधान कौन करेगा?

गौतम कुमार, मदनगीर, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -

1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया।

आजकल

बेनकाब हो रहे हैं तथाकथित उदारवादी

हर्षवर्धन त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले एक माह से अधिक समय से नागरिकता संशोधन कानून समेत अन्य मामलों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नागरिकता कानून के विरोध में देश की सबसे बड़ी आवाज शाहीन बाग बन गया है। तथाकथित उदारवादी खेमे की ओर से शाहीन बाग के आंदोलन को देश का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है, लेकिन यह स्वयं उजागर हो रहा है कि ये तथाकथित उदारवादी इस मामले में किस तरह की राजनीति कर रहे हैं

देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध ने सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े कर रखे हैं। हालांकि यहां धरने पर बैठी महिलाओं को तथाकथित उदारवादियों ने प्राइम टाइम बहस का हिस्सा भी बनाया है। लेकिन पहले यहां के प्रदर्शन में 500 से 700 रुपये देकर प्रतिदिन के लिए प्रदर्शनकारियों को लाने वाला वीडियो आया और उसके बाद एक बेहद खतरनाक वीडियो आया जिसमें एक बच्चे को नागरिकता कानून के जरिये मुसलमानों को कैंपों में ठूंस दिया जाएगा और खाना सिर्फ एक समय खाने को मिलेगा जैसी बातें कहते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द कहते सुना जा सकता है। इस आंदोलन का चेहरा महिलाओं को बनाया गया है और बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं को टीवी की प्राइम टाइम बहस का हिस्सा बनाने से हुई शुरुआत को छोटे-छोटे प्रदर्शनकारी बच्चों तक पहुंचाया गया। शाहीन बाग से यह आवाज मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि देश में फासीवाद आ गया है।

तथाकथित उदारवादी मुस्लिम महिलाओं को आगे करके इस आंदोलन को देश का रचनात्मक आंदोलन बता रहे हैं, लेकिन इसी रचनात्मकता की आड़ जब खत्म होती है तो इस प्रदर्शन का असली वीभत्स चेहरा सामने आने लगता है। बच्चों के जहरीले वीडियो वायरल हो गए हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता साबित होने तक उसे छोड़ भी दें तो पाकिस्तान के लाहौर में मोदी और शाह के बीच मतभेद की खबर देकर आए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान उदारवादियों का चेहरा बेनकाब कर देता है। दरअसल तथाकथित उदारवादी खेमे की तरफ से राममंदिर बनने और अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय पर ऐसे ही बयान लगातार आ रहे थे और इस भड़काऊ बयानबाजी ने देश के मुसलमानों के दिमाग में जहर भर दिया है। देश के मुसलमान इतना ज्यादा जहर भरने के बावजूद नागरिकता कानून में बदलाव को स्वीकार करने के लिए मन बना चुका था, क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि रामंदिर निर्माण का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो या फिर 370 खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला, दोनों पर ही कोशिश करके भी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। नागरिकता कानून के मामले में भी देश के दोनों सदनों से बाकायदा चर्चा कराकर मतदान कराने के बाद अध्यादेश को मंजूरी मिली और कानून बना। संवैधानिक दायरे में आए निर्णयों की वजह से देश का मुसलमान मन में भले ही दुखी हुआ हो, पर इनमें से किसी फैसले के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ।

देश के तथाकथित उदारवादी, प्रगतिशील और जाहिर तौर पर डेढ़ दशक से नरेंद्र मोदी विरोधी और जन्मना संघ, भाजपा विरोधी खेमे को अपनी प्रासंगिकता खत्म होती दिख रही थी। इस खेमे को हमेशा यह गुमान रहा कि भारत में सिर्फ उसी तरह से वैचारिक बहस चल सकती है जैसा उनका खेमा चाहता है। इस कष्टित खेमे ने नई रणनीति निकाली। उसी नई रणनीति के तहत देश के विश्वविद्यालयों के छात्रों को तैयार किया गया। जेएनयू में कब्जा जमाए बैठे वामपंथियों को पूरा भरोसा था कि यहां चल रहे छात्र आंदोलन को देशव्यापी बनाया जा सकेगा। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली तो मुस्लिम विश्वविद्यालयों- जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया। यह आसान भी था, मुसलमानों को समझाया गया कि आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। यही कोशिश नदवा कॉलेज लखनऊ में भी की गई थी, लेकिन प्रशासन की चौकसी ने उनकी रणनीति पर पानी फेर दिया। जामिया में यह कोशिश सफल रही और सीएए विरोधी आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदला गया। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्रों के हाथ में विरोधी तख्तियां पकड़ाकर उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया। परिसरों में ज्यादातर छात्र इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि सरकारी, पुलिसिया दमन के खिलाफ लड़ना है, इस स्वाभाविक मानसिकता का फायदा उठाकर आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदला गया। उधर उत्तर प्रदेश में पीएफआइ और दूसरे कट्टर इस्लामिक संगठनों के साथ हिंसक आंदोलन की रणनीति बनाई गई। काफी हद तक यह रणनीति कामयाब भी रही, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वीडियो प्रमाण के आधार पर दंगाइयों पर मामला दर्ज करके उनसे वसूली शुरू की तो खेमे की चुनौती बड़ी हो गई।

अपने विचार के विरुद्ध किसी को भी बर्दाश्त न करने वाले इस खेमे को लग रहा है कि हमने देशव्यापी आंदोलन तैयार कर लिया है। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अपनी उपकुलपति से अभद्रता करने लगे और उनसे सवाल करने लगे कि कक्षाओं में हम तब आएंगे, परीक्षा तब देंगे, जब वह यह बता देंगी कि नागरिकता कानून के विरोध में हैं या नहीं। तथाकथित उदारवादी, प्रगतिशील पूर्णतः फासीवादी खेमे के भरे जहर का प्रभाव है कि जामिया के बच्चे अपने प्रॉक्टर को गालियां देते हैं। जेएनयू के वामपंथी छात्र अपने उपकुलपति के घर को तब घेर लेते हैं जब घर में उपकुलपति नहीं होते हैं, घर में सिर्फ उपकुलपति की पत्नी होती हैं।

वामपंथी और कट्टर इस्लामिक गठजोड़ के जहरीले विचारों का प्रभाव मेरठ में भी दिखा जब अनीस उर्फ खलीफा ने पुलिस पर गोली चला दी और पकड़े जाने पर कहा कि उसके भाई को 1987 के दंगे में पुलिस की गोली लगी थी, उसी का बदला ले रहा था। देश में बरसों से फैलाए जा रहे जहर की साक्षात तस्वीर है शाहीन बाग का आंदोलन। शाहीन बाग से दिल्ली एनसीआर लाखों लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन मोदी-शाह विरोध में इस आंदोलन की उम्मीद से बैठे लोगों को यह कीमत बहुत छोटी लग रही है। अच्छी बात यह है कि बरसों से निष्पक्ष बुद्धिजीवी का चोला ओढ़े बैठे खेमेबाजों के चेहरे का परदा हट गया है। शाहीन बाग को इसलिए भी ऐतिहासिक माना जाएगा कि देश में जहरीले विचारों के पोषक, जनता के सामने बेनकाब हो गए।

शाहीन बाग में सीएए के विरोध में धरनारत महिलाएं। फाइल फोटो

विपक्ष का हथियार मुस्लिम महिलाएं

डॉ. नीलम महेंद्र
स्तंभकार

सीएए को कानून बने एक माह से भी अधिक हो चुका है, लेकिन विपक्ष द्वारा इसका विरोध जारी है। बल्कि यह विरोध 'विरोध' की सीमाओं को लांघ कर हताशा और निराशा से होता हुआ विद्रोह का रूप अख्तियार कर चुका है। शाहीन बाग का धरना इसी बात का उदाहरण है। जो राजनीतिक दल इस धरने को अपना समर्थन दे रहे हैं और इन आंदोलनरत लोगों के जोश को बरकरार रखने के लिए यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा का यह जहर कहीं देश की फिजाओं में भी ना घुल जाए, क्योंकि हाल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक कह रहा है कि यहां महिलाओं को बैठने के रुपये दिए जा रहे हैं। ये महिलाएं शिफ्ट में काम कर रही हैं और एक निश्चित संख्या में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित रखती हैं। इस वीडियो की सत्यता की जांच गंभीरता से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस युवक द्वारा कही गई बातों में जरा भी सच्चाई है तो निश्चित ही विपक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में है।

दरअसल विपक्ष आज बेबस है, क्योंकि उसके हाथों से चीजें फिसलती जा रही हैं। जिस तेजी और सरलता से मौजूदा सरकार इस देश के वर्षों पुराने उलझे हुए मुद्दे, जिन पर बात करना भी विवादों को आमंत्रित करता था, सुलझाती जा रही है, विपक्ष खुद को मुद्दा विहीन पा रहा है। वर्तमान सरकार की कूटनीति के चलते संसद में विपक्ष की राजनीति भी नहीं चल पा रही जिससे वो खुद को अस्तित्व विहीन भी पा रहा है, शायद इसलिए अब वह अपनी राजनीति सड़कों पर ले आया है। खेद का विषय है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभी तक विपक्ष आम आदमी और छात्रों का सहारा लेता था, लेकिन अब वह महिलाओं को मोहरा बना रहा है। इस देश की मुस्लिम महिलाएं और बच्चे अब विपक्ष का नया हथियार हैं, क्योंकि शाहीन बाग का मोर्चा महिलाओं के ही हाथ में है।

अगर शाहीन बाग का धरना वाकई में प्रायोजित है तो इस धरने का समर्थन करने वाला हर दल सवालों के घेरे में है। संविधान बचाने के नाम पर उस कानून का हिंसक विरोध जिसे संविधान संशोधन द्वारा खुद संसद ने ही बहुमत से पारित किया हो, क्या संविधान सम्मत है? जो लड़ाई आप संसद में हार गए उसे महिलाओं और बच्चों को मोहरा बनाकर सड़क पर लाकर जीतने की कोशिश करना किस संविधान में लिखा है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में लिखा है? संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन हर राज्य का कर्तव्य है (अनुच्छेद 245 से 255), संविधान में उल्लिखित होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में विपक्ष की सरकारों का इसे लागू नहीं करना या फिर केरल सरकार का इसके खिलाफ न्यायालय में चले जाना क्या संविधान का सम्मान है? जो लोग महीने भर तक रास्ता रोकना अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं उनका उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विषय में क्या कहना है जो लोग उनके इस धरने से परेशान हो रहे हैं? अपने अधिकारों की रक्षा करने में दूसरों के अधिकारों का हनन करना किस संविधान में लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन मुस्लिम महिलाओं से जो धरने पर बैठी हैं। आज जिस कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर जैसे नेताओं का भाषण उनमें जोश भर रहा है, उसी कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो के हक में आए न्यायालय के फैसले को संसद में उलट कर शाहबानो ही नहीं, हर मुस्लिम महिला के जीवन में अंधेरा कर दिया था।

यह दुर्भाग्यजनक ही है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण तीन तलाक से छुटकारा पाने वाले समुदाय की महिलाएं उस विपक्ष के साथ खड़ी हैं जो एक राजनीतिक दल के नाते उन्हें केवल वोटबैंक समझ कर उनका उपयोग करता रहा और आज भी कर रहा है।

खरी-खरी

नेताओं का वार्षिक राशिफल

डॉ. पिलकेंद्र अरोरा

नगर के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पं. अनुमानश्री महाराज ने नेताओं का 2020 का वार्षिक राशिफल जारी करते हुए कहा है कि नया वर्ष नेताओं के लिए सामान्य रहेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए यह शुभ, कुछ के लिए अशुभ, जबकि कुछ के लिए मिश्रित रहेगा। विस्तृत राशिफल इस प्रकार है-

मेष : हाईकमान की किरपा बनी रहेगी। कद, पद में वृद्धि होगी तो 'बद' भी बढ़ेगी। ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ने का शुभ योग है।

वृषभ : गुटबाजी के कारण पार्टी में अप्रिय विवाद होंगे। हनी ट्रैप की संभावना बनेगी, जिसमें पहले देह, फिर जेब और प्रतिष्ठा का ह्रास होगा।

मिथुन : भूमाफिया से संबंधों का पर्दाफाश होने से कोर्ट की यात्रा का सुख प्राप्त होगा। पद से निलंबन संभव है। किंतु आलाकमान के तलवे चाटने पर इसका कुप्रभाव कम हो जाएगा।

कर्क : अनर्गल बयानबाजी से विवाद उत्पन्न होंगे। हाईकमान की नाराजगी बढ़ेगी। कट ऊपर तक पहुंचाने पर नाराजगी का शमन होगा।

सिंह : पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। किंतु जातक की दूसरे शहरों में होने वाली यात्राओं और होटलों के प्रवास के चलते वह इससे होने वाला नुकसान मैनेज कर लेगा।

कन्या : नए कोटा, नए परमिट, नए लाइसेंस आदि के सुयोग बनेंगे। आर्थिक पक्ष प्रबल होगा।

तुला : निरंतर यात्रा एवं प्रवास से अपच और अनिद्रा जैसे रोग होंगे। कार्यकर्ताओं से विवाद होगा।

वृश्चिक : जैसा कि इस राशि का नाम ही वृश्चिक है, इसलिए इसके जातक-नेता साल भर बिच्छू की तरह जनता को डंक मारते रहेंगे।

धनु : चुनाव क्षेत्र में आपकी हरकतें देखते हुए जनता 'सार्वजनिक अभिनंदन' करेगी।

मकर : स्टिंग ऑपरेशन का खतरा रहेगा। सदन में मारपीट से अंग-भंग की आशंका रहेगी। पुराने प्रकरण में जेल-यात्रा का दुर्योग रहेगा।

कुंभ : पुत्र-पुत्री, दामाद-बहू के राजनीति में भाग्योदय के अवसर मिलेंगे। न्यूज चैनलों की लाइव डिबेट में पिटाई का प्रबल योग है।

मीन : वरिष्ठ नेताओं का चरण-अमृत मिलता रहेगा। आगामी चुनाव में टिकट का विकट योग है। यह योग धन से सध सकेगा।

ट्वीट-ट्वीट

गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर से मिली। नेहरू का टाइटल पंडित उनकी जाति से जुड़ा था। आखिर सावरकर को वीर की उपाधि किसने दी? किसी को कोई जानकारी है?

देवदत्त पटनायक@devduttmyth

यह 1924 की बात है। सावरकर काला पानी में 11 साल और अन्य जेलों में तीन साल सजा काटकर रिहा हुए थे। तब नासिक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सेल्युलर जेल में उनके साथ कैद रहे वामनराव जोशी ने उसी कार्यक्रम में ही सावरकर को 'स्वातंत्र्यवीर' की उपाधि दी थी।

विक्रम संपत@vikramsampath

कश्मीरी पंडितों पर जुल्मोसितम को लेकर भारतीय और विदेशी मीडिया ने चुप्पी ही साधे रखी। यदि अल्पसंख्यक वर्ग के चार लाख लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ता तो वही मीडिया इसे लेकर आसमान सिर पर खड़ा कर देता।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

बीते पांच साल में दिल्ली में इन्वर्टर बिक्री 67 फीसद बढ़ी है। यदि 24 घंटे बिजली मिलती तो क्या इतने इन्वर्टर बिकते? आम आदमी पार्टी चाहे तो इस उद्योग में तेजी का श्रेय ले सकती है। उसके प्रचार अभियान में झूठी बातों की भरमार जो है।

गौरव पांधी@GauravPandhi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ग्राहकों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड स्विच ऑफ करने की सुविधा मिलने से डिजिटल फ्रॉड के मामले रुकेंगे?

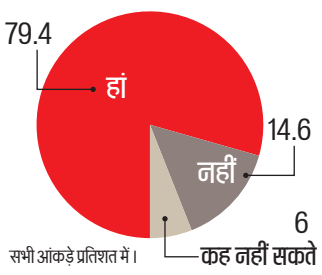

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पर्यावरण संरक्षण पर मानव शृंखला जैसी पहल जन जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आबादी विस्फोट पर अगर न जागे आज,
अगली पीढ़ी के लिए होगा नहीं अनाज।
होगा नहीं अनाज न पाएंगे हम पानी,
होगी हवा अशुद्ध दिखेगी विकट कहानी।
जेएनयू में मांग रहे हैं जो आजादी,
आगे आकर आज जरा रोकें आबादी!

– ओमप्रकाश तिवारी

शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक विकास पर हो जोर

अलका आर्य
स्वतंत्र टिप्पणीकार

देश में इन दिनों अनेक घटनाएं सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी आई है कि सरकारी संस्थाओं जैसे आंगनबाड़ी व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ज्ञान कौशल निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में कम है। लोगों का भरोसा सरकारी शिक्षण तंत्र पर कम होता जा रहा है। इसका असर सबसे वंचित तबके के बच्चों पर पड़ता है।

सरकार द्वारा देश भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह आयुवर्ग के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा, शिक्षापरक गतिविधियां उन्हें प्राइमरी स्कूल में भेजने की तैयारी कराने में अपेक्षित भूमिका निभाती नजर नहीं आती। संभवतः यह उनकी प्राथमिकताओं में शमिल नहीं हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पोषण व अन्य काम अधिक महत्व रखते हैं। अहम सवाल यह है कि अगर अरली चाइल्डहुड एजुकेशन (ईसीई) को नजरअंदाज किया जाता है तो उसका खामियाजा सिर्फ बच्चे को ही नहीं, बल्कि देश को भी भुगतना पड़ता है। हाल ही में 'प्रथम' नामक गैर सरकारी संगठन ने अपनी सालाना रिपोर्ट 'असर' जारी की है। प्रथम ने 2019 में मुल्क के 24 राज्यों के 26 जिलों में एक सर्वे कराया। इस सर्वे से यह जानकारी सामने आई है कि 9.4 प्रतिशत बच्चों के पास ही पठनीय सामग्री मिली। लखनऊ और वाराणसी में चार से आठ वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी-सरकारी स्कूलों में भेजने से परहेज किया जाता है। चार वर्ष के लगभग 30 प्रतिशत बच्चे उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं जाते।

वर्ष 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, तब करीब 20 प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता था, लेकिन अभी हर 100 में से दो बच्चे ही वंचित हैं। दाखिले संबंधी आंकड़ों के साथ-साथ यह सवाल भी चलना चाहिए कि बच्चों के पढ़ने-लिखने का स्तर क्या है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार कक्षा पांच के आधे से भी कम छात्र कक्षा दो का पाठ पढ़ पाते हैं। कक्षा तीन के केवल 27.2 प्रतिशत छात्र कक्षा दो के पाठ को पढ़ पाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता का यह क्रम आगे तक जारी रहता है। बच्चे की सीखने की क्षमता का उसकी आयु से गहरा संबंध होता है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। असर-2019 रिपोर्ट बताती है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले 20 प्रतिशत से अधिक बच्चों की आयु छह साल से कम हैं, उन्हें प्री स्कूल में होना चाहिए था। इसी तरह पहली कक्षा के 36 प्रतिशत बच्चों की आयु छह साल से अधिक है। यहां समझने की बात यह है कि अगर बच्चा कक्षा के लिए नियत आयु से कम है तो वह पढ़ाई में पीछे रह जाता है और अगर उसकी आयु अधिक है तो वह दूसरों के मुकाबले बेहतर नतीजे लाता है। बच्चे की जिंदगी में प्रारभिंक वर्षों का काफी महत्व होता है। इन्हीं सालों में बच्चे ज्ञान संबंधी, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक कौशल को विकसित करते हैं जिनकी उन्हें जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरत होती है।

इसके साथ ही ईसीई यानी अरली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। मुल्क में शिक्षा का अधिकार कानून तो पारित हो गया जिसमें छह से 14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान है। इस कानून के तहत ईसीई को अनिवार्य नहीं कहा गया, लेकिन राज्यों से तीन साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त प्री-स्कूल शिक्षा देने की अपील की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना ने भी ईसीई और स्कूल जाने की तैयारी कराने में इसके महत्व को पहचाना। भारत सरकार ने 2013 में ईसीई और शिक्षा नीति को पारित किया। यह नीति छह साल से कम आयु के सभी बच्चों के लिए है और सभी बच्चों की गुणात्मक ईसीई तक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कागजों व जमीनी हकीकत में काफी फासला है। असर के सर्वे से सामने आया कि पांच साल की आयु के 7.2 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में कक्षा एक में हैं और सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 16.7 प्रतिशत है। भारत में हर चौथा बच्चा औपचारिक स्कूल में दाखिल है, जबकि उसे अपनी आयु के हिसाब से प्री-स्कूल में होना चाहिए था, इनमें से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। यानी यहां पर सरकारी शिक्षा का तंत्र ही कटघरे में खड़ा है। नई शिक्षा नीति 2019 में छोटे बच्चों के सीखने के संकट पर चर्चा है। इसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा प्राथमिक शिक्षा के करीब पांच करोड़ बच्चों के पास बुनियादी साक्षरता व गणित तक का कौशल नहीं है।

अगर मुल्क को प्राथमिक व हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है तो उसके लिए अरली चाइल्डहुड एजुकेशन पर निवेश करना होगा, अभिभावकों के बीच इसके महत्व बावत जागरुकता की मुहिम छेड़नी होगी, सरकारी तंत्र को आंकड़ों को लेकर वाहवाही लूट कर छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

अच्छी पहल

कमिश्नर प्रणाली से बदलेगी तस्वीर

बृजलाल
पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू करते हुए उनकी नियुक्ति से राज्य में शासन-प्रशासन की तस्वीर बदलने की उम्मीद है जिससे सुशासन और विकास की राह आसान हो सकती है

देश में पुलिस आयुक्त प्रणाली बहुत पुरानी प्रणाली है जिसे अंग्रेज शासकों ने कलकत्ता (कोलकाता) बॉम्बे (मुंबई) तथा मद्रास (चेन्नई) में सबसे पहले लागू किया था। उन्होंने इस प्रणाली को इन शहरों में लागू किया था जहां से वे न केवल अपना व्यापार करते थे, बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाली कानून व व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखते थे।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सीआरपीसी के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए मजिस्ट्रियल पावर पुलिस आयुक्त को दिए जाते हैं। भीड़ को तितर-बितर करने, लाठीचार्ज से लेकर गोली चलाने तक की आवश्यकता पड़ जाती है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के यह संभव नहीं होता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट में एक मत न होने के कारण आवश्यक बल प्रयोग में देरी हो जाती है जिसका असर यह होता है कि उपद्रवी भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और जहां टीयर गैस और लाठीचार्ज करने के काम चल जाता है वहां पुलिस को मजबूर होकर गोली चलानी पड़ती है। कभी कभी तो मजिस्ट्रेट समय से मौके पर नहीं जाते जिससे पुलिस सामान्य प्रक्रियाओं के तहत शांति व्यवस्था बनाने में अक्षम महसूस करने लगती है। कुछ मजिस्ट्रेट बल प्रयोग करने के आदेश पर दस्तखत ना कर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। इस तरह से पुलिस विषम परिस्थितियों में अधिकार विहीन दायित्वों का निर्वहन करती है। मैं वर्ष 1992 में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत को मेरठ मंडल में ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मेरठ के किठौर में डीएम, एसएसपी, बुलंदशहर, गाजियाबाद को भी कहा गया कि सभी मौजूद रहेंगे। दोनों जिलों के डीएम, एसएसपी आ गए, लेकिन मेरे साथ तैनात रहे डीएम तुलसी गौर न तो खुद गए और न ही किसी मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने टिकैत को गिरफ्तार कर लिया और मेरे पास उस वक्त कोई मजिस्ट्रेट नहीं था जो गिरफ्तारी के वारंट पर हस्ताक्षर कर सके। वायरलेस पर एसडीएम निखिल शुक्ला की आवाज सुन कर मैंने उन्हें बुलाया और वारंट पर दस्तखत कराए और महेंद्र सिंह टिकैट को प्रयागराज (इलाहाबाद) की नैनी जेल भिजवाया।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह। फाइल फोटो

पुलिस आयुक्त प्रणाली में ये पूरे अधिकार पुलिस कमिश्नर में निहित होते हैं।

बहुत सी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं कि पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं जो अब इस व्यवस्था के लागू होने से समाप्त हो जाएंगे और पुलिस को भी यह मौका नहीं मिलेगा कि वे असफलता का आरोप किसी अन्य पर टाल सके। अपराध नियंत्रण में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून धारा 107/ 116/ 151 सीआरपीसी धारा 109/ 110 सीआरपीसी में कार्रवाई अपराध नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक होती है जिसमें कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट स्तर से की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि एसडीएम कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और कभी होती भी है तो बहुत देर बाद जिससे आपराधिक घटना घटित हो जाती है और उसके लिए पुलिस को ही जिम्मेदार माना जाता है। यह धारा 107/ 116/ 151 में गिरफ्तारी के साथ दो पार्टियों को पाबंद करने के अधिकार पुलिस उपायुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त को होगा जिससे त्वरित कार्रवाई कर संभावित शांति भंग और आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकेगा।

पुलिस द्वारा अवैध असलहों की बरामदगी भारी मात्रा में की जाती है, लेकिन जब तक जिलाधिकारी की अनुमति नहीं मिलती तब तक विवेचक न्यायालय में चार्जशीट नहीं लगा सकता है। इसमें विवेचकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जिलाधिकारी की अनुमति के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब यह अधिकार पुलिस आयुक्त को मिलने पर समय से न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की जा सकेगी। धरना, प्रदर्शन, मनोरंजन के कार्यक्रमों में लोग अनुमति के लिए जिलाधिकारी को आवेदन करते हैं, पुलिस द्वारा आख्या मांगी जाती है। अब ऐसे आयोजनों पर पुलिस आयुक्त अपने स्तर से सीधे निर्णय ले सकेंगे। कानून व्यवस्था का कार्य जिलाधिकारी तथा उनके अधीनस्थों के पास से हटने के कारण उन्हें अपने जिले में विकास कार्यों में पूरा समय मिलेगा जो पहले संभव नहीं पाता था।

धर्मवीर आयोग ने आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार में रिपोर्ट दी थी जिसमें महानगरों में बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की संस्तुति की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने 1978 में कानपुर में यह प्रणाली लागू की थी। वासुदेव पंजानी को कानपुर का पुलिस आयुक्त नियुक्त भी कर दिया था। परंतु बाद में उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। तब से यह मामला लंबित रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रणाली को प्रदेश के दो शहरों में लागू कर ऐतिहासिक काम किया है। इससे पुलिस की भी जवाबदेही बढ़ी है और अब उनका कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और पुलिसिंग का ऐसा आयाम कायम करें जिससे वहां की जनता को लाभ मिले और कानून व्यवस्था की स्थिति को बहुत अच्छा बनाया जा सके। विकास तब तक संभव नहीं हो पाता, जब तक वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इस प्रणाली से इन महानगरों में विकास को गति मिलेगी और बेहतर कानून व्यवस्था होने से व्यापारी व निवेशकों को उद्योग-धंधे लगाने में प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार सृजित होंगे और प्रदेश के विकास की रफ्तार तेज होगी।

27 फीसद आदिवासी महिलाएं बच्चों को अपने घर में जन्म देती हैं। पूरे देश के लिए शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 10.8 फीसद और ग्रामीण इलाकों के लिए 16.2 फीसद है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 20 जनवरी 2020

उत्तराखंड

शर्तों का उल्लंघन करते बांडधारक चिकित्सक

उत्तराखंड में बांडधारक चिकित्सकों पर अभी तक विभाग की लचर पकड़ चिंताजनक है। यही कारण है कि बांड की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ये चिकित्सक पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने से लगातार कन्नी काट रहे हैं। इनके सेवा न देने पर कार्रवाई के नाम पर विभाग केवल इनकी सेवाएं समाप्त कर किसी तरह फजीहत से बचने की कोशिश कर रहा है। आलम यह है कि विभाग अभी तक बांडधारक चिकित्सकों द्वारा अनुबंध तोड़ने पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। यह स्थिति तब है जब अनुबंध में ही यह साफ है कि सरकारी सेवाएं न देने पर ऐसे चिकित्सकों को सरकार द्वारा फीस में दी गई रियायत मय ब्याज लौटानी होगी। बावजूद इसके विभाग अपने इस अनुबंध का भी पूरा तरह अनुपालन नहीं करा पाया है।

दरअसल प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने बांडधारक चिकित्सकों को रखने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरकार ने योजना बनाई की मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रियायती दरों पर शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा। जो भी रियायती दरों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चिह्नित होंगे, वे पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रदेश में ही अपनी सेवा देंगे। इसके लिए एक बांड भरा जाएगा। शुरुआत से ही इस योजना में खामी नजर आने लगी थी। इस योजना के तहत मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों में से कई ने प्रदेश में अपनी सेवाएं नहीं दी और दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करने लगे। इसके लिए विभाग ने उन्हें चेतावनी पत्र जारी किए, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। कारण यह कि जो पता अनुबंध पत्र में दिया गया था, कई बार वह सही नहीं पाया गया। इस कारण विभाग कुछ नहीं कर पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे अनुबंध की समयसीमा पूरी होने से पहले ही कई अन्य चिकित्सक भी सेवाएं छोड़ कर चले गए। इन घटनाओं को देखते हुए विभाग ने शासन को ऐसे चिकित्सकों की सूची भेजी। शासन ने भी कार्रवाई के नाम पर केवल इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। साफ था कि विभाग के पास इन पर कोई विधिक कार्रवाई करने का ठोस आधार नहीं था। अब विभाग की तवज्जो इस ओर नजर आ रही है। विभाग अब बांडधारक चिकित्सकों के लिए समिति बना रहा है। यह कदम ठीक कहा जा सकता है, बशर्ते इस समिति को कानूनी कार्रवाई करने के सारे अधिकार दिए जाएं। सरकार को भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए विभाग को इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने होंगे। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी चिंताजनक बात है। जब वहां पर्याप्त डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीजों का इलाज फिर कैसे होगा? समाज को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी चिकित्सकों के कंधों पर भी होती है। इस बात को सब कोई जानता है कि एक स्वस्थ समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है तो फिर सरकारें डॉक्टरों की भयंकर कमी को दूर करने के प्रति गंभीर क्यों नहीं हैं? दुख की बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहने चाहिए, लेकिन वे अभी हाशिये पर हैं।

बांडधारक चिकित्सकों पर नजर रखने और अनुबंध का पालन करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तब ही चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सकता है।

बिहार

देश को नई राह दिखा रहा बिहार

भारतीय इतिहास के अनगिनत पृष्ठ पर बिहार के गौरव की गहरी छाप है। दुनिया में लोकतंत्र और विविध धर्म के पौराणिक आख्यान का पाठ जिस भूमि ने पढ़ाया, उस भूमि पर नए-नए कीर्तिमान से 'बिहारी अभिमान' में श्रीवृद्धि हो रही है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भारी औद्योगीकरण और ऊर्जा संसाधनों के बेतहाशा दोहन का नतीजा हैं। यह राज्य की सीमा में बंधने वाला विषय नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अक्सर बहस होती है और एक राज्य, दूसरे पड़ोसी राज्य पर ठीकरा फोड़ते हैं। इसके बरक्स कम औद्योगीकरण के बावजूद बिहार का जलवायु परिवर्तन के वैश्विक चिंतन में प्रतिबद्ध होना यहां की नीतीश नीत सरकार की जागरूकता का परिचायक है। पर्यावरण प्रदूषण पर इमरजेंसी घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है।

दुनिया देख चुकी है कि विकसित राष्ट्र भी कार्बन उत्सर्जन के संकल्पित मानक को पूरा नहीं कर सके। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सभी देशों पर कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की नीतियां तय करने का जोर है और इस लक्ष्य को 2050 तक हासिल करना है। भारत पर भी इसका दबाव है। ऐसे अवसर कम होते हैं, जब हम अगली पीढ़ी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जल, जीवन-हरियाली का बिहार का यह मिशन आने वाली पीढ़ी की सांसें सुरक्षित रखेगा। यह पहला मौका नहीं है जब बिहार अग्रसर की भूमिका में देश को नई राह दिखा रहा है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण हो या फिर शराब बंदी का दृढ़ संकल्प हो या हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना हो, ऐसे कई मौकों पर बिहार ने अगुआ की भूमिका अदा की है। कीर्तिमान रचने से ज्यादा अभिमान यह है कि बिहार खुद के लिए नए प्रतिमान भी गढ़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सवा पांच करोड़ लोगों ने मिलकर जल और जीवन फिर उससे उपजने वाली हरियाली के लिए लगभग 18 हजार किलोमीटर लंबी जो मानव श्रृंखला बनाई, उसने बिहारी मन को नए अभिमान से भर दिया।

मानव श्रृंखला में शिरकत करते बिहार के पुलिसकर्मी।

मुख्यमंत्री केवल विचार में नहीं, कर्म में भी सक्रिय रहते हैं। इस समय वे बिजली से चलने वाली कार से चलते हैं जो उनकी दूरदृष्टि का द्योतक है। इससे पूर्व शराबबंदी के समर्थन में भी इस प्रकार की मानव श्रृंखला उनके नेतृत्व में बनी थी। आज राज्य में जो अमन चैन कायम है, उसमें शराब पर निषेध भी बड़ा कारक है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान के काम को धरातल पर लाने की शुरुआत होने के बाद यह आयोजन हुआ और मानव श्रृंखला का नया कीर्तिमान बना। अभी मीलों चलना है, लक्ष्य दूर है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़कर चलने का जो संदेश गांधी मैदान से शुरू होकर राज्य के कोने-कोने तक पसरा, निश्चय ही इससे संकल्प का वटवृक्ष घनीभूत होगा।

कीर्तिमान रचने से ज्यादा गर्व की बात यह है कि बिहार खुद के लिए नए प्रतिमान भी गढ़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सवा पांच करोड़ लोगों ने मिलकर जल-जीवन-हरियाली अभियान के लिए जो मानव श्रृंखला बनाई, उसने बिहारी मन को नए अभिमान से भर दिया।

बंगाल

इलेक्शन मोड में बंगाल की सियासत

नए साल में एक बार फिर बंगाल की सियासत इलेक्शन मोड में आने लगी है। राज्य चुनाव आयोग ने सूबे के 93 नगर निकायों की सुरक्षित सीटों की सूची जारी कर संकेत दे दिए हैं कि चुनावी प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, यानी अघोषित रूप से चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ सभी राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार के नगर निकाय के चुनाव काफी अहम हैं, खासकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए। कारण बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की राह इसी चुनाव से होकर निकलने वाली है। यह चुनाव 2021 के लिए लिटमस टेस्ट होगा।

भाजपा के खिलाफ सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर तृणमूल समेत सभी विपक्षी दलों के तेवर तल्ख हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि नगर निकाय चुनाव तक सीएए-एनआरसी के खिलाफ आंदोलन जारी रहना तय है। हर दिन कभी बुद्धिजीवी तो कभी अन्य संगठन की ओर से सीएए-एनआसी के खिलाफ जुलूस निकाला जा रहा है, वहीं पार्क सर्कस व धर्मतल्ला इलाकों में धरना भी चल रहा है। माना जा रहा है कि अप्रैल के मध्य में चुनाव हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए तृणमूल व विरोधी दल तैयारियों में जुट गए हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

राज्य चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को सुरक्षित सीटों की सूची जारी की गई। इस बार एक, तीन व छह के फॉर्मूले पर सीटों को सुरक्षित किया गया है। कोलकाता नगर निगम के 144 वार्ड में से आठ को अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित किया गया है, जबकि कुल 45 वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। टेंगरा इलाके में पड़ने वाले 58 नंबर वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिए जाने से मेयर परिषद के सदस्य (बस्ती) स्वपन समाद्दार इस बार वहां से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

इसी तरह मेयर परिषद के सदस्य (आवास) वैष्णानर चट्टोपाध्याय भी 10 नंबर वार्ड से नहीं लड़ पाएंगे। वार्ड नंबर 13 व 16 से क्रमशः मेयर परिषद के सदस्य (सड़क) रतन दे और (सफाई) देवब्रत मजुमदार अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर पाएंगे। मेयर परिषद के ये चारों सदस्य अपने वार्ड से अपने किसी करीबी को खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर आकलन करने पर भाजपा ने तृणमूल को करीब 50 वार्ड में मात दी थी। हालांकि पिछले आठ माह में स्थिति काफी बदल चुकी है। ऐसे में अब निकाय चुनाव को लेकर मुद्दे क्या होंगे, यह तो स्पष्ट है और शोर भी शुरू हो चुका है।

पंजाब

आर्थिक बदहाली का विकास पर असर

पंजाब की कमजोर आर्थिक स्थिति का अब विकास कार्यों पर भी गहरा असर पड़ने लगा है। विकास के कोई नए कार्य तो शुरू हो नहीं रहे, साथ ही जो पहले से प्रस्तावित हैं या जारी हैं, उन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बठिंडा में तीसरे रिंग रोड का निर्माण होना था। इस प्रोजेक्ट में पचास फीसद राशि पंजाब सरकार को देनी थी, लेकिन प्रदेश सरकार इसे देने में असफल रही, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रद कर दिया। इससे पहले भी कई प्रोजेक्टों की रफ्तार या तो धीमी हो चुकी है या फिर थम चुकी है। बठिंडा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का लोकसभा क्षेत्र है और यहां पहले भी एम्स के निर्माण में विलंब को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में यहां के प्रोजेक्टों में देरी के लिए प्रदेश सरकार पर सियासत के आरोप भी लगते रहे हैं।

उम्मीद है कि ऐसे आरोपों में सच्चाई नहीं होगी और यदि तनिक भी सच्चाई है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, समूचे प्रदेश का समान विकास उसका प्राथमिक दायित्व होता है। आशा है कि सरकार आर्थिक मजबूरी के कारण ही रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की धनराशि नहीं दे सकी। हालांकि गंभीर आर्थिक संकट के लिए प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदार है। एक तरफ तो सरकार के पास सड़कों का निर्माण करवाने के लिए धन नहीं है, वहीं दूसरी ओर सरकार के कई ऐसे विभाग हैं, जिन्हें बिना किसी काम के वेतन वितरित किया जा रहा है। मोगा स्थित पीडब्ल्यूडी का इलेक्ट्रिकल विंग भी ऐसा ही एक विभाग है, जिसे विगत दस वर्षों में बिना किसी कार्य के सात करोड़ से अधिक की धनराशि स्टाफ और दफ्तरी कार्यों के लिए दे दी गई। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे विभागों पर पुनर्विचार करे, बचत के अन्य मार्ग भी तलाशे ताकि खजाने की सेहत सुधरे और पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास के कार्य जारी रह सकें।

एक तरफ तो सरकार के पास सड़कों का निर्माण करवाने के लिए धन नहीं है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विभाग हैं, जिन्हें बिना किसी काम के वेतन दिया जा रहा है।

बहरहाल पंजाब सरकार यदि गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है तो कहीं न कहीं वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। आर्थिक संकट कोई ऐसी समस्या नहीं है, जो एक दिन में खड़ी हो जाए। इसके संकेत तो पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं और प्रदेश सरकार को भी निःसंदेह इसके संकेत पहले मिल गए होंगे। कम से कम भारी-भरकम कर्ज की स्थिति देखकर तो कुछ अंदाजा लगाया जा ही सकता था। इसके बावजूद सरकार ने इससे निपटने के लिए उचित समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जबकि पानी सिर से ऊपर निकलने लगा है तब सरकारी खर्च घटाने की कवायद की जा रही है। सरकार को अपने समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की स्थिति दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें फिलहाल दस हजार करोड़ से अधिक का अंतर है। यदि सरकार ने अभी इसमें सुधार नहीं किया जो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

टिहरी झील के किनारे वीरान पड़ी है साहसिक खेल अकादमी

टिहरी में कोटी कॉलोनी स्थित साहसिक खेल अकादमी का भवन। जागरण

जागरण संवाददाता, नई टिहरी

15 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड में टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी में बनाई गई साहसिक खेल अकादमी छह साल से वीरान पड़ी है। यहां स्थानीय युवाओं को वाटर, एयरो और एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन पर्यटन विभाग की लापरवाही के चलते आज तक इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया।

कोटी कॉलोनी में 2014 में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का निर्माण हुआ। इसी वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। बावजूद इसके संचालन न होने पर 2018 में स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी ने पर्यटन विभाग को गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के विशेषज्ञों से अकादमी का संचालन शुरू कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। स्थानीय युवा एवं टिहरी झील बोटिंग एसोसिएशन के संरक्षक कुलदीप पंवार का कहना है कि सरकार की लापरवाही स्थानीय युवाओं की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है।

इन खेलों का मिलना है प्रशिक्षण

वाटर स्पोर्ट्स : वाटर पैरासिलिंग, स्कल्स, लाइफ सेविंग टेक्निक, क्याकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, बोर्ड हैंडलिंग व स्कूबा डाइविंग

एयरो स्पोर्ट्स : पैरासिलिंग, पैराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून

एडवेंचर कोर्स : रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग व आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग

गोवा के साथ करार हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक अकादमी का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है।

-एसएस यादव, जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल

पंजाब में खाने की होम डिलीवरी के लिए कंपनियों को करानी होगी रेटिंग

सुरेश कामरा, पटियाला

- जोमैटो व स्विगी सहित अन्य कंपनियों को जारी किया नोटिस
- तीन से पांच रेटिंग वाली खाद्य सामग्री होने पर ही सप्लाई कर पाएंगी कंपनियां

पंजाब में खाने की होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए सेहत विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे खाद्य सामग्री की रेटिंग करवाएं। तीन से पांच रेटिंग वाली खाद्य सामग्री होने पर ही कंपनियां खाने की सप्लाई कर पाएंगी। सरकार के मिशन तंदुरुस्त पंजाब के निदेशक काहन सिंह पन्नू ने कहा कि राज्य में मौजूदा समय में खाद्य पदार्थों की दुकानों से चार से पांच कंपनियां तैयार फूड सप्लाई कर रही हैं।

ये कंपनियां ऑनलाइन ऑर्डर पर घर, ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्टलों तक तैयार खाद्य सामग्री पहुंचाती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री किस स्तर की है और इसमें मसाले सहित अन्य सामान की गुणवत्ता क्या है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। आम तौर पर कंपनियां अपनी मार्केटिंग की रेटिंग तो करवाती हैं, लेकिन खाद्य सामग्री की नहीं। आजकल लोग बड़ी संख्या में फूड डिलीवरी कंपनियों के जरिये खाने-पीने की सामग्री मंगवाते हैं। सेहत विभाग के अधिकारी छह महीने से इन कंपनियों को कह रहे थे कि वे सामग्री की हाईजीन का विशेष ध्यान रखें। मिशन तंदुरुस्त के पास पहुंची कुछ शिकायतों के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।

मिशन तंदुरुस्त के पास पहुंची शिकायतों के बाद उठाया गया है कदम। प्रतीकात्मक

30 जनवरी तक जवाब देने को कहा : मिशन तंदुरुस्त पंजाब के निदेशक काहन सिंह पन्नू ने बताया कि उन्होंने पंजाब में ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली जोमैटो व स्विगी सहित अन्य कंपनियों को नोटिस देकर कहा है कि वे 30 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करें कि उनकी ओर से सप्लाई की जा रही सामग्री की रेटिंग क्यों न करवाई जाए। उन्होंने कहा कि तीन से पांच तक अंक लेने वालों को ही खाद्य सामग्री सप्लाई करने की इजाजत दी जाएगी। एक या दो अंक वालों को इजाजत नहीं मिलेगी।

केंद्रीय एजेंसियों की मदद से होगी जांच : काहन सिंह पन्नू के मुताबिक, खाद्य सामग्री की रेटिंग पंजाब सरकार के सेहत विभाग और केंद्र सरकार की करीब 25 एजेसियों की मदद से होगी। इसमें किस तरह के मसाले व अन्य सामान इस्तेमाल होते हैं, इसकी जांच करके रेटिंग दी जाएगी। स्वच्छ सामान के बल पर ही एजेंसियां अंक तय करेंगी। यह सारी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

गुरुग्राम में तय होगा देशभर में नेशनल हाईवे के विस्तार का खाका

आदित्य राज, गुरुग्राम

- 23-24 जनवरी को देशभर में कार्यरत एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों की होगी बैठक

देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) के विस्तार से लेकर नए राजमार्ग बनाने का खाका इसी हफ्ते गुरुग्राम में खींचा जाएगा। आइएमटी मानेसर स्थित होटल हेरिटेज में 23 एवं 24 जनवरी को देशभर में कार्यरत एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। इस दौरान जहां केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे वहीं आगामी दिनों में कहां क्या कार्य करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों के अनुरूप आगे योजनाएं बनाई जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों में जहां राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और तेजी से हो, वहीं कुछ नए राजमार्ग बनाए जाएं जिससे कि कनेक्टिविटी तेजी से बढ़े। इसके लिए लगातार दो दिनों तक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मंथन किया जाएगा। इससे सामने निकलकर आएगा कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को विस्तार दिया जाना आवश्यक है। किसकी लंबाई बढ़ाना आवश्यक है तो किसकी की चौड़ाई। यही नहीं किस-किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर एवं अंडरपास बनाने की आवश्यकता है आदि जानकारी सामने आएगी। जहां कहीं भी प्रोजेक्ट पूरा करने में समय लग रहा है, उसके बारे में संबंधित अधिकारियों से सवाल किए जाएंगे? साथ ही अधिकारियों से नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बारे में सुझाव लिए जाएंगे।

बताया जाता है कि दो दिवसीय बैठक से एक दिन पहले ही यानी 22 जनवरी को ही शाम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा होनी है, इस बारे में कुछ अधिकारियों से पहले ही चर्चा करेंगे ताकि बेहतर आउटपुट निकलकर सामने आए। केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन राज्यमंत्री वीके सिंह के साथ ही मंत्रालय के सचिव, एनएचएआइ के चेयरमैन सहित मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी मंथन में शामिल होंगे। इसे देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के गुरुग्राम कार्यालय ने तैयारी तेज कर दी है। जगह-जगह स्वागत को लेकर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे ताकि देश भर से आने वाले अधिकारियों को परेशानी न हो। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बैठक में शामिल होने वाले सभी अधिकारी 22 जनवरी की रात तक पहुंच जाएंगे। एनएचएआइ के निदेशक (प्रोजेक्ट) एके शर्मा का कहना है कि तैयारी में किसी भी स्तर पर कमी न रहे, इसे लेकर पूरी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्य रूप से कार्यों की समीक्षा की जाती है।

झारखंड में किसके आदेश से रद हुई नेताजी जयंती की छुट्टी, लगाया जा रहा है पता

आशीष झा, रांची

2014 तक 23 जनवरी को रहती थी सरकारी छुट्टी, 2015 से हो गई थी बंद

- विश्वविद्यालयों में अभी भी मिलती है नेताजी जयंती की छुट्टी
- बंग परिषद के आवेदन पर कार्मिक विभाग कर रहा कारणों की पड़ताल

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी मिलती रही है, लेकिन झारखंड में 2015 से इसे बंद कर दिया गया। बंग परिषद के आवेदन पर अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसके आदेश पर सुभाष जयंती की छुट्टी रद हुई। आवेदन सरकार के माध्यम से कार्मिक विभाग में पहुंचा है और जाहिर सी बात है कि छुट्टी रद हुई होगी तो सरकार के तमाम वरिष्ठ लोगों की अनुमति मिलने के बाद ही, लेकिन अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। कारण यह कि सत्ता बदल गई है और फाइलों में कोई ठोस कारण दर्ज नहीं है। अलग राज्य बनने के बाद से 2014 तक नेताजी के नाम पर सरकारी छुट्टी मिलती रही है, लेकिन 2015 से इसे बंद कर दिया गया।

आजादी के दशकों बाद भी नेताजी की अहमियत पूरे प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अहम है। झारखंड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा रिश्ता रहा है और आखिरी बार वे गोमो रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर रवाना हुए थे। यहां कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में वे पहुंचे थे और गांधी के समानांतर सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर अलग सभा की थी। रांची में लालपुर स्थित डॉ. सिद्धार्थ मुखर्जी के पिता क्रांतिकारी यदुगोपाल मुखर्जी से भी वे मशविरा लिया करते थे।

सरकार का पत्र लिखकर फिर से छुट्टियों को बहाल करने की मांग : झारखंड में रहने वाले बंगाली समाज के लोग और बंगभाषी समुदाय नेताजी को इन्हीं कारणों से लगातार याद रखे हैं और उनकी जयंती पर तरह-तरह के आयोजन होते हैं। छुट्टियां रद होने से समुदाय आहत है और इसी आलोक में सरकार का पत्र लिखकर हिनू बंग परिषद ने फिर से छुट्टियों को बहाल करने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मामले में सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। कोशिश यह है कि जब विश्वविद्यालयों में इसकी छुट्टी अभी भी दी जा रही है, तो सरकारी छुट्टी क्यों बंद हो। ज्ञात हो कि राज्य में कार्यपालक आदेश से यह छुट्टी लोगों को मिल रही थी, जिस पर राज्य सरकार का निर्णय ही मान्य होता है।

सुभाष जयंती पर न सिर्फ छुट्टी होनी चाहिए, बल्कि संस्थानों में उनके योगदान को देखते हुए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। नेताजी का नाम सबसे बड़े देशभक्तों में शुमार किया जाता रहेगा।

- डॉ. पंपा सेन विश्वास, जोनल सचिव, निखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन

उत्तराखंड में 200 पंचायतों में प्रधान की कुर्सी अभी भी खाली

राज्य ब्यूरो, देहरादून : हरिद्वार को छोड़ उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में 202 ग्राम पंचायतों में अभी भी पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। सामान्य निर्वाचन और फिर उपनिर्वाचन में भी इनमें दो दर्जन से ज्यादा ग्राम प्रधान और शेष ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रह गए हैं। ऐसे में इन पंचायतों में प्रधानों की कुर्सी अभी भी खाली है। हालांकि, अब इन पदों के उपनिर्वाचन के लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है।

पिछले साल जुलाई व अगस्त में 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद शासन ने इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर में इन जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के 30636 पद रिक्त रह गए थे। इसके चलते कोरम पूरा न होने के कारण 4600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पंचायतों का गठन नहीं हो पाया। इसके बाद रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन के बावजूद 202 ग्राम पंचायतें ऐसी रह गई हैं, जहां गठन नहीं हो पा रहा है।

स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रयागराज की ऊंची छलांग, उप्र में चौथे स्थान पर

रमेश यादव, प्रयागराज

- सितंबर माह में टॉप-50 शहरों की सूची से हो गया था बाहर
- नगर निगम प्रयागराज का स्मार्ट सिटी के रूप में जून 2017 में हुआ था चयन

पिछले माह स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 के दो तिमाही के नतीजों में प्रयागराज स्वच्छ शहरों की फेहरिस्त में देश में नौवें स्थान पर था। अब स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश में 22वें पायदान पर आ गया है, जबकि सितंबर-2019 में टॉप-50 शहरों की सूची से बाहर होकर 51वें पायदान पर पहुंच गया था। प्रयागराज अब उत्तर प्रदेश में सिटी रैंकिंग में चौथे स्थान पर है।

नगर निगम प्रयागराज का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन जून 2017 में हुआ। 2019 में कुंभ मेले को लेकर यहां तेजी से निर्माण कार्य कराए गए। इस कारण प्रयागराज स्मार्ट सिटी की ऑल इंडिया रैंकिंग में उस समय 34वें स्थान पर आ गया था। कुंभ मेला बीतने के बाद यहां पर स्मार्ट सिटी के कामों की रफ्तार धीमी पड़ गई तो सितंबर में संगम नगरी टॉप-50 शहरों की सूची से बाहर हो गया। अब दूसरे चरण के काम जल्द शुरू होने वाले हैं। सभी कार्यों की कार्ययोजना वेबसाइट पर अपलोड हो गई है तो प्रयागराज की रैंकिंग ने लंबी छलांग लगा दी है। जनवरी माह की रैंकिंग में यह 22वें पायदान पर आ गया है। 29 पायदान का इजाफा हुआ है। रैंकिंग में प्रयागराज से ऊपर कानपुर (सातवें), आगरा (13वें) और वाराणसी (14वें) स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों की रैंकिंग में सुधार होने पर सूबे की रैंकिंग भी सुधरी है। उत्तर प्रदेश राज्यों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया। पहले 11वें स्थान पर था। नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ रवि रंजन का कहना है कि शहर में जल्द ही आठ स्मार्ट रोड, 200 ओपन एयर जिम, मल्टीलेवल पार्किंग आदि का कार्य शुरू होने वाला है। इसके कारण प्रयागराज की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

प्रयागराज में कुंभ मेला। फाइल फोटो

टॉप-3 सिटी रैंकिंग

प्रथम : अहमदाबाद (गुजरात)
द्वितीय : नागपुर (महाराष्ट्र)
तृतीय : तिरुप्पुर (तमिलनाडु)

टॉप-3 स्टेट रैंकिंग

प्रथम : झारखंड
द्वितीय : गुजरात
तृतीय : आंध्र प्रदेश

तंत्र के गण

उत्सव गणतंत्र का...

जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग-अलग करके नहीं बल्कि समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है, जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी है।

राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट

निजता का अधिकार

अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे में अब निजता का अधिकार भी शामिल है।

निजता के अधिकार के लिए लड़ने वाले जस्टिस पुट्टास्वामी और कर्मण्य सिंह को सलाम

निजता अस्तित्व का अभिन्न अंग...

शोषण के विरुद्ध अधिकार

बालश्रम के खिलाफ आवाज

बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ विनीत जे. मेहरा ने आवाज बुलंद की है। मेहरा ने रोमी हवात के साथ मिलकर के 2015 में ग्लोबल सस्टेनेबल नेटवर्क (जीएसएन) की स्थापना की। अब तक करीब तीन हजार से ज्यादा बच्चों को अपने परिवार से मिलवा चुके हैं। वे बाल श्रम के साथ मानवता के खिलाफ खड़े अन्य विषयों के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। विमानों में प्रयोग होने वाली चेहरा पहचानने वाली तकनीक के जरिए वे बच्चों की पहचान करते हैं। उन्होंने दिल्ली के भीड़भरे बाजारों से बच्चों को वापस उनके घर तक पहुंचाया है। यह इस तकनीक और मेहरा के साहस से ही संभव हो सका है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर के भी बच्चों को अपने परिजनों से मिलवा चुके हैं। इसके साथ ही जीएसएन बाल श्रम और मानव तस्करी के शिकार बच्चों के पुनर्वास में भी जुटा है। साथ ही उन्होंने कॉमिक्स फोर चेंज कार्यक्रम का आयोजन किया था। उनका कहना है कि युवाओं को बेहतर और सतत भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। युवाओं को कॉमेडी की भाषा पसंद आती है और इसके साथ मनोरंजन, शिक्षा, विचारों के आदान-प्रदान और एकता भी होती है। इसके अतिरिक्त वे मानते हैं कि दुनिया में आधुनिक दौर की शरणार्थी संकट, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और असमानता को खत्म करना बेहद जरूरी है तभी हम अपनों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। आधुनिक जीवन की दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने पर विशेष ध्यान के साथ सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए।

विनीत जे. मेहरा

बदल गई परिभाषा, खुली नई राह

अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और न्यायपालिका ने पहले भी कई निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, त्वरित न्याय, बेहतर पर्यावरण आदि को जोड़ा है। 2017 में निजता के अधिकार ने इसे विस्तार दिया। अब जब निजता भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है तो कोई नागरिक अपनी निजता के हनन की स्थिति में याचिका दायर कर न्याय की मांग कर सकता है। दरअसल, संविधान का भाग 3 जो कुछ अधिकारों को मौलिक मानता है, इसमें निजता के अधिकार का उल्लेख नहीं था। निजता का अधिकार, समानता का अधिकार है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का? ऐसे बुनियादी विषयों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया।

सोशल मीडिया से लेकर आधार तक, कई बातों को लेकर निजता का सवाल लगातार उठा। 24 अगस्त 2017 को जस्टिस केएस पुट्टास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वह 21वीं सदी में भारतीय नागरिकों के अधिकारों के मामले में अहम साबित हुआ। इस निर्णय ने न सिर्फ पुराने कुछ निर्णयों को पलट दिया बल्कि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक प्रगतिशील और सार्थक व्याख्या की राह भी खोल दी। इस निर्णय में निजता को सिर्फ संविधान के दायरे में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और व्यापक सिद्धांतों के दायरे में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर जो निर्णय दिया, उसने आमजन के लिए कुछ अहम बातों पर आधार की अनिवार्य निर्भरता को समाप्त कर दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएस पुट्टास्वामी निजता का अधिकार मामले के साथ ही आधार मामले में निजता के पहलू को चुनौती देने वाले पहले याचिकाकर्ता हैं। दोनों ही मामलों में उन्हें जीत मिली।

इस मामले में पहले याचिकाकर्ता रहे 93 साल के जस्टिस केएस पुट्टास्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज और आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं। आधार के साथ-साथ निजता के अधिकार मामले के भी वह पहले याचिकाकर्ता हैं। निजता के अधिकार मामले में शीर्ष अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना।

दरअसल, तकनीक के विकास के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय के जरिए निजता की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कानूनों के साथ की गई है। आज तकनीकी सरकार को नागरिकों के बारे में हर तरह की सूचनाएं जमा करने की सुविधा दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र में असहमति का सम्मान करने वाला सिद्ध हुआ। इस निर्णय को सिर्फ डेटा सुरक्षा और सरकारी निगरानी से जोड़कर देखना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह मानकर कि निजता के तहत न सिर्फ सूचनाएं आती हैं बल्कि अपने खुद के शरीर से संबंधित निर्णय लेने की आजादी भी आती है, लोगों को एक मजबूत औजार थमा दिया, जिसका इस्तेमाल लोग निजता हनन के खिलाफ कर सकते हैं। खास तौर पर उन मामलों पर इसका असर पड़ेगा जहां लोगों को स्वतंत्र तौर पर निर्णय लेने से रोका जाता है और पितृसत्तामक सरकार उन पर अपना निर्णय थोपती है। इस निर्णय की सबसे अहम बात यह है कि इसमें यह नहीं माना गया है कि भारत के नागरिक सरकार के अधीन हैं बल्कि माना गया है कि लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है।

गौरतलब है कि देश में 100 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन और 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। कुछ समय पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 10 सरकारी खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर डेटा पर निगरानी रखने यानी उसे खंगालने का अधिकार दिया गया। सरकार का कहना है कि 2009 के कानून में इसका पहले से ही प्रावधान है। अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत अगर एजेंसियों को ऐसा लागता है कि कोई व्यक्ति या संस्था देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद डेटा को खंगाल सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

वाट्सएप-फेसबुक को दी चुनौती

मैसेजिंग एप वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली निवासी छात्र कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेयस सेठी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया था कि निजता को लेकर फेसबुक और वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी या निजता संबंधी नीति संदेहपूर्ण है, जिसमें बदलाव किए जाने की मांग की गई। फेसबुक ने वाट्सएप का अधिग्रहण किया था। जिसके बाद वाट्सएप के करोड़ों यूजर्स का डाटा सीधे फेसबुक को हस्तगत हो गया।

जबकि वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को फेसबुक ने परिवर्तित कर दिया। इसे लेकर 19 वर्षीय कर्मण्य सिंह सरीन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई और इस कृत्य को चुनौती दी। कर्मण्य ने बताया कि हमने तर्क रखा कि इस तरह नई पॉलिसी लागू करना गैरकानूनी है और यह पूरी तरह से यूजर्स की प्राइवेसी का हनन है। दिल्ली हाई कोर्ट से जब हमें इसमें राहत नहीं मिली तो हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

कर्मण्य का साथ उनके दोस्त श्रेयस सिंह सेठी ने भी दिया, जो कि तब विधि के छात्र थे। छात्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका की सुनवाई करते हुए फेसबुक और वाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और बाद में मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपने का आदेश दिया। कर्मण्य बताते हैं, फेसबुक ने जब वाट्सएप का अधिग्रहण किया और प्राइवेसी पॉलिसी बदल दी, तब स्पष्ट किया गया था कि यह अधिग्रहण उन मूल सिद्धांतों को नहीं बदलेगा जो वाट्सएप पर आधारित थे और अधिग्रहण के बाद भी वाट्सएप अलग और स्वायत्त रूप से कार्य करेगा। वहीं, वाट्सएप ने स्पष्ट किया था कि फेसबुक के साथ हम एक साझेदारी बना रहे हैं जो हमें स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से संचालन जारी रखने की अनुमति देगी। हमारे मौलिक मूल्यों और विश्वासों में बदलाव नहीं होगा...। लेकिन जो हुआ वह इस भावना से बहुत दूर था। फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं की निजता के साथ गंभीर रूप से समझौता करने का फैसला किया था।

वाट्सएप की नई पॉलिसी आई तो फेसबुक ने यह कहा कि वाट्सएप यूजर्स के डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कर सकता है। यही नहीं, वाट्सएप की पुरानी नीति में शामिल एक नियम- इन्फॉर्मेशन वाट्सएप वाट्स नॉट कलेक्ट, को पूरी तरह से हटा दिया गया था। यानी अब यह स्पष्ट नहीं था कि यूजर की वे कौन सी सूचनाएं होंगी, जिन्हें वाट्सएप द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। हमने कोर्ट में इसे चुनौती दी।

कर्मण्य सिंह सरीन बनाम फेसबुक केस, जो देश ही नहीं दुनियाभर में द वाट्सएप केस के नाम से मशहूर है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यूजर्स को विश्वास में लिए बिना प्राइवेसी पॉलिसी में फेरबदल किए जाने को कर्मण्य ने चुनौती दी है।

बकौल कर्मण्य, मेरे लिए यह प्रसंग अचरज भरा था। क्योंकि यूजर्स की सहमति के बिना, उन्होंने अपनी गोपनीयता नीति को पूरी तरह से बदल दिया था और यूजर बिना इसे जाने, बिना इसके परिणामों को जाने इस पर सहमति जताने को विवश थे। कोर्ट में जाने से पहले मैंने अपने सर्कल में इसकी जांच की और पाया कि मेरे चचेरे भाई जो एक डॉक्टर थे, मेरे पारिवारिक मित्र जो वकील थे, मेरे माता-पिता और अन्य शिक्षित पेशेवर जो मेरे परिचित थे, अनजाने में नई नीति के लिए सहमत हुए थे। मेरा मानना था कि यह उपयोगकर्ताओं के विश्वास का उल्लंघन था। हो यह रहा था कि अब विज्ञापन से जुड़ें हितों सहित बेहद अस्पष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी फेसबुक और इससे जुड़े अन्य मीडिया प्लेटफार्म के साथ साझा की जा रही थी। हमने इसे भी चुनौती दी। मैंने अपने अधिवक्ता मित्र प्रभास बजाज और श्रेयस सेठी से सलाह लेने के बाद इसे चुनौती देने का फैसला किया। कर्मण्य के अधिवक्ता ने बताया कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

नहीं डिगने दिया विश्वास, अब विकास की आस

जीने का अधिकार

श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर दूर है बडगाम जिले का गांव कनिहामा। सुर्खियों से परे इस गांव के कारीगर अपने हुनर से कश्मीर की अनूठी हस्तकला को न केवल आगे बढ़ा रहे हैं वरन दुनियाभर में नई पहचान देने की मशक्कत में जुटे है। कश्मीरी कालीन और पश्मीना की चकाचौंध के आगे इनकी कानी शॉल गुमनामी में कहीं खो गई पर न इनका विश्वास डगमगाया और न इन्होंने अपने हुनर से किनारा किया। अब 370 के खात्मे के बाद अब इस गांव में भी उम्मीद की रोशनी जगी है कि इन्हें भी विकास के साथ कदमताल करने का भरपूर अवसर मिलेगा।

रजिया नूर ● श्रीनगर

कानी शॉल के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। इसकी गुणवता पश्मीना शॉल से भी कई गुना अधिक है। एक कानी शॉल की कीमत 30 हजार से चार लाख रुपये तक है। चीरू भेड़ की ऊन से बनने वाली शॉल की बारीक कढ़ाई और डिजाइन गढ़ने में एक कारीगर को लगभग एक से डेढ़ साल लग जाता है। यह शॉल वजन में हलकी होती है जबकि इसकी गर्माहट काफी अधिक होती है। बुनकरों का गांव कहा जाने वाले कानीहामा की बड़ी आबादी इसी पर ही निर्भर है। गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है।

कानीहामा की पहचान भी कानी शॉल से ही है। इसका असली नाम गुंड कारहामा था, लेकिन कानी शॉल की बदौलत गुंड कारहामा का नाम कानीहामा पड़ गया। इस गांव में जेके स्टेट हैंडलूम का कारखाना है और इसके अलावा कुछ अन्य लोगों ने यहां हैंडलूम खोले हैं। इनके माध्यम से गांव के कारीगर इस हुनर को बढ़ाने में जुटे हैं।

कानी शॉल आम हस्तकलाओं से अलग है। यह शॉल कानी यानी विशेष प्रकार के पेड़ की पतली टहिनयों पर बुनी जाती है। कानी को पहले पैंसिल की शक्ल दी जाती है। इसके लिए अलग से कारीगर होते हैं। बाद में कानी हथकरघे पर चढ़ाए पशमीने के धागों में घुसाई जाती है और शॉल बुनने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह शॉल दूसरे बुने जाने वाले शॉलों से अलग होता है। एक कानी शॉल को बुनने के लिए 25-30 कानियों की दरकार होती है। इनकी मदद से शॉल पर कारीगर विभिन्न रंगों के डिजाइन बनाते हैं। यह डिजाइन कानी शॉल बुनने वाला कारीगर बनाता है।

कानी शॉल चूंकि हथकरघे पर कानियों के माध्यम से बुना जाता है। डिजाइन, आकार तथा शाल की लंबाई, चौड़ाई के हिसाब से कारीगर को एक कानीशॉल बुनने में औसतन 10 से 18 महीने लगते हैं। एक कारीगर प्रतिदन औसतन चंद इंच (एक से दो इंच) कानी शॉल ही बुन पाता है। डिजाइन व शॉल के साइज के हिसाब से इसका रेट तय होता है। भारी कीमत के चलते यह शॉल गरीबों की पहुंच से दूर है।

मिला जीआइ का दर्जा: कानी शाल के बिलकुल मिलते-जुलते शॉल मार्केट में है। खरीदारों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शॉल असली है और कौन सा नकली। नकली शॉल 4000 से 6000 रुपये तक बेचे जाते थे। सरकार ने यह दिक्कत दूर करने के लिए कानी शॉल को ज्योग्राफिकल ऑर्डेटिफकेशन (जीआइ) का दर्जा दे दिया है। इस ट्रेड मार्क से असली कानी शॉल की पहचान करना आसान हो गई है।

हथकरघा गांव बनेगा कानीहामा...: कानीहामा हथकरघा गांव के तौर पर विकसित होगा। कारीगर शब्बीर अहमद डार को बेहतरीन कानी शॉल डिजाइन करने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। कुछ बुजुर्ग कारीगर करीब 60-70 वर्षों से इस काम से जुड़े हैं और उनके बुने कानी शॉल विश्व प्रसिद्ध संग्रहों की जीनत बने हुए हैं। ऐसे कारीगर गुमनामी व गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव को विकास की डग्गर पर ले जाने तथा कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रशासन ने हाल ही में कानिहामा को हथकरघा गांव को विकिसत करने का फैसला किया है। तैयारियां भी शुरू की है। इसके लिए प्रशासन ने गांव का सर्वे भी किया है।

कानीहामा गांव में हैंडलूम पर काम करतीं कानी शॉल कारीगर। ● जागरण

धागा तैयार करता कानी शॉल कारीगर। ● जागरण

मुहैया कराई जाएंगी मौलिक सुविधाएं...

गांव को हैंडलूम विलेज के तौर पर विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। गांव के कारीगरों से संपर्क कर जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कारीगरों के लिए कई स्कीमें उपलब्ध रखी जाएंगी, जिसमें उन्हें हथकरघे, सोलर लाइट्स व अन्य मौलिक सुविधाओं के साथ-साथ गांव में कारखाने और शोरूम स्थापित किए जाएंगे। कानी शॉल व अन्य हस्तकलाएं सीखने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

तारिक हुसैन गनई, उपायुक्त, बडगाम

उम्मीद है कि गांव की तकदीर बदलेगी...

हमारा तैयार किया कानी शॉल लाखों में बिकता है। बदले में हमें चंद पैसे थमाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि कानी शॉल की तरह इस काम से जुड़े हम कारीगरों को इज्जत मिले। उम्मीद है कि गांव की तकदीर बदलेगी। गांव में सरकार ऐसी कोई जगह बनाए, जहां हम अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकें। कारीगर अपने तैयार किए माल को राज्य से बाहर किसी डीलर को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। कानी शॉल के कद्रदान केवल देश ही नहीं विदेश तक में हैं।

अब्दुल मजीद भट, बुनकर

गुरबत की बेड़ियां तोड़ सम्मान से हुई खड़ी

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा की बदलती तस्वीर अब नजीर बनने लगी है। अभाव और गरीबी से जूझती आदिवासियों महिलाओं को स्वालंबन की पतवार थमाई है- मेहरार चो मान यानी औरत का सम्मान योजना ने।

समता का अधिकार

दंतेवाड़ा की नई दिशा महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष निकिता मरकाम (बीच में) व समूह की महिलाएं। ● नईदुनिया

संजीत कुमार ● रायपुर

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा क्षेत्र में मेहरार चो मान (औरत का सम्मान) योजना ने आदिवासी महिलाओं को समता और सम्मान के साथ जीने की नई राह दिखाई है। इस योजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की अनेक महिलाएं ई-रिक्शा चलाने से लेकर कड़कनाथ मुर्गा पालन, सैनेटरी पैड निर्माण जैसे स्वउद्यम कर अपनी और परिवार की तरक्की तय कर रही हैं। अति पिछड़े जिलों को विकास की धारा में लाने के लिए पीएम आकांक्षी जिला योजना में दंतेवाड़ा भी शामिल है। यह प्रयास इसी दिशा में अमल में लाया गया है। अब महिलाओं को उनके घर में ही रोजगार मिल रहा है। यही कारण है कि ई-रिक्शा चलाकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली महिलाओं की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में कर चुके हैं।

नई दिशा महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष निकिता मरकाम कहती हैं कि ग्राम संगठन के माध्यम से सैनेटरी पैड के निर्माण का काम किया जाता है, ग्राम संगठन में कुल 19 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े हुए हैं। समूह की 10 महिलाएं सैनेटरी पैड बनाने का काम करती हैं, वहीं कुछ महिलाएं कड़कनाथ मुर्गा पालन, मध्याह्न भोजन और चूड़ी खरीद कर बेचने का काम करती हैं। इससे उन्हें पांच से छह हजार रुपये महीने की कमाई हो जाती है। यह राशि उनके परिवार को सम्मानपूर्ण आजीविका देने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। इससे उनमें जीवन के प्रति विश्वास जागा है और अब बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुई हैं।

मरकाम ने बताया कि उनके समूह ने बैक लिंकेज के माध्यम से पहले तीन लाख, उसके बाद दोबारा एक लाख रुपये का लोन लिया था। इसका पूरा भुगतान कर दिया है। अब काम के लिए फिर से तीन लाख रुपये लेने की योजना बना रहीं हैं। समूह की सदस्या निकिता कहती हैं कि पहले थोड़ी घबराहट थी पर अब उन्हें विश्वास है कि सभी मिलकर बैंक का पूरा पैसा समय पर वापस कर देंगी। 12वीं तक पढ़ी निकिता ने बताया कि उसके समूह की 3-4 महिलाएं ही 8वीं से 12वीं तक पढ़ी हैं। कम पढ़ी-लिखी होने के कारण उनके पास रोजगार की समस्या थी, लेकिन समूहों और ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और महिलाएं बहुत खुश हैं।

कड़कनाथ पालन से 1.20 लाख की कमाई

समूह की सदस्या अनीता ठाकुर ने बताया कि जिले के सेनेटरी पैड निर्माण से महिलाएं हर माह चार से पांच हजार रुपये की कमाई कर लेती हैं, तो वहीं समूह की दूसरी महिलाएं ईंट बनाने, साग-सब्जी उत्पादन और बेचने, मध्याह्न भोजन बनाने के अलावा कड़कनाथ मुर्गा पालन का काम करती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें मुर्गा पालन के लिए शेड निर्माण करके दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा पालन से लगभग एक लाख 20 हजार रुपये की आमदनी हुई है।

मुस्लिम महिलाओं के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ रहे यासिर जिलानी

यासिर जिलानी ● जागरण

नेमिष हेमंत ● नई दिल्ली

पिछले वर्ष अगस्त में जब संसद से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में तीन तलाक कानून लागू किया तो यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक क्षण था, उन्होंने कहा था 'तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।' लेकिन इतने भर से महिलाओं का शोषण नहीं रुकना था। जरूरत थी कि इसके लिए रूढ़ीवादी परंपराओं और मान्यताओं में पले-बढ़े समाज को जागरूक किया जाए।

यह काम आसान नहीं था, पर दिल्ली के अधिवक्ता यासिर जिलानी जैसे प्रगतिशील लोग इसके लिए आगे आए। उन्होंने न केवल मुस्लिम समाज की महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि पीड़ित बहनों को कानूनी मदद भी पहुंचाने लगे। उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई भागों में ऐसे अधिवक्ताओं की टीम तैयार की जो इस अभियान को जमीन तक ले जाएं और माहौल बदले।

समता का अधिकार

205 से अधिक महिलाओं को तीन तलाक मामले में कानूनी सहायता

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े यासिर उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने महिलाओं के शोषण के खिलाफ कानून बनने से पहले एक सकारात्मक माहौल तैयार किया, बल्कि प्रगतिशील मुस्लिम युवाओं को इस अभियान में जोड़ा। वह कहते हैं कि इस राह में कई रोड़े थे, क्योंकि उन्हें ही काफिर बोला जा रहा था। उन्हें समाज से बाहर करने की चेतावनी दी जा रही थी। पर वह डिगे नहीं। उन्होंने एनएंडवाइ लीगल सर्विसेज नाम की संस्था खड़ी की, जिसमें देशभर के सक्रिय 25 से अधिक अधिवक्ता शामिल हैं। संस्था से और भी अधिवक्ताओं को जोड़ा जा रहा है।

टीम के सदस्य उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों में है। जहां वह इस तरह के मामलों को अपने हाथों में लेते हुए पीड़ित परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि यह किस तरह अपराध है। यह किस तरह से धर्म के विरूद्ध है। इस टीम ने अब तक 250 से अधिक तीन तलाक के मामले अपने हाथ में लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक किया है। उनपर पीड़ित महिलाओं या उनके जानकारों के फोन आते हैं।

जिलानी बताते हैं कि उन लोगों का प्रयास होता है कि मामला सुलझ जाए। इसके लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों से बात की जाती है। उन्हें इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जाती है। इसके लिए टीम के सदस्य एक राज्य से दूसरे राज्य और गांवों तक का सफर तय करते हैं। 65 फीसद मामलों में पति अपनी गलती मान लेता है। नहीं तो आगे पीड़ित महिला को मुफ्त कानून सहायता मुहैया कराई जाती है। इसी तरह विभिन्न राज्यों में तीन तलाक पर गोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं। इस तरह के अब तक 15 से अधिक सफल गोष्ठियां हो चुकी हैं। जो मुस्लिम समाज के लोगों को कानून और तीन तलाक को लेकर जागरूक करने में सफल रही हैं।

एयर इंडिया के कर्मचारी मांगेंगे वीआरएस

मुंबई : एयर इंडिया के कर्मचारी संगठन विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ सोमवार को प्रस्तावित मुलाकात के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की मांग कर सकते हैं। पुरी सोमवार को एयर इंडिया के दर्जनभर से ज्यादा संगठनों से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले दो जनवरी की बैठक में विमानन मंत्री ने कर्मचारी संगठनों से दो-टूक कहा था कि कंपनी का निजीकरण उसे बचाने का एकमात्र उपाय है। (प्रेट्र)

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कटौती का वक्त आ गया है। इसके साथ ही सरकार को व्यक्तिगत टैक्स में भी सुधारों पर जोर देना चाहिए।
– सुभाष चंद्र गर्ग
पूर्व वित्त सचिव

ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को उम्मीद, बजट से मिलेगी रफ्तार

बजट से उम्मीदें

- एफटीए ने तोड़ी भारतीय ऑटो पार्ट्स उद्योग की कमर, ई-वाहनों का भी दिख रहा असर
- इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बजट में हो कुछ प्रावधान : उद्यमी

राजीव शर्मा, लुधियाना

पिछले साल ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से गुजरा और इसका सीधा असर ऑटो पार्ट्स उद्योग पर पड़ा। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण रहे जिस कारण देश में ऑटो पार्ट उद्योग पटरी से उतर गया है। घरेलू बाजार की सुस्त रफ्तार, विभिन्न देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के तहत ऑटो पार्ट्स का सस्ता आयात, बाजार में ई-वाहनों की आहट से भारत में पिछला वर्ष ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा। भारत में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी से प्रतिस्पर्धा में भी कई कंपनियां पिछड़ी हैं। इसलिए ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस आम बजट में सरकार घरेलू बाजार को रफ्तार देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगी। उद्यमियों का कहना है कि आम बजट में सरकार को इन चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेष फंड उपलब्ध कराना होगा।

जानकारों का कहना है कि विदेश से ड्यूटी फ्री पार्ट्स का आयात हो रहा है। थाइलैंड से आने वाले पुर्जे करीब 25 फीसद तक सस्ते हैं, जिनमें इंजन एवं ट्रांसमिशन पार्ट्स प्रमुखता से शामिल हैं। घरेलू उद्योग इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार में स्पेशल स्टील भी जरूरत के मुताबिक उपलब्ध नहीं है। स्पेशल स्टील के आयात को ड्यूटी फ्री कर सरकार घरेलू इंडस्ट्री को नई संजीवनी दे सकती है।

वहीं, ई-वाहन सेग्मेंट ने भी ऑटो पार्ट्स उद्योग जगत की की नींद उड़ा दी है। क्योंकि बैटरी चालित वाहनों में डीजल-पेट्रोल वाहनों के इंजन के मुकाबले 10 फीसद तक ही पुर्जे इस्तेमाल होते हैं। यह ऑटो पार्ट्स उद्योग के लिए बड़ा संकट है।

ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी ने भी चिंता बढ़ा दी है। है। प्रॉडक्ट डेवलपमेंट में कमियां हैं और बाजार की चुनौतियों ने निपटना मुश्किल हो रहा है। विदेश से आने वाले पुर्जों की लाइफ ज्यादा है। गुणवत्ता में सुधार से पार्ट्स की लाइफ एक से बढ़कर पांच साल हो गई। इससे रिप्लेसमेंट मार्केट 60 फीसद तक खत्म हो गई। बेहतर गुणवत्ता के मामले में भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया एवं फिलीपींस से भी मुकाबला नहीं कर पा रही हैं।

ई वाहन और पेट्रोल-डीजल वाहनों में संतुलन बनाया जाए : अपैक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव और ऑटो पार्टस निर्माता रजनीश इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन रजनीश आहूजा का कहना है कि ऑटो पार्टस उद्योग के लिए ई वाहन सबसे बड़ा खतरा हैं। ई-वाहनों में इंजन न होने से उद्योग जगत को बड़ा धक्का लगा है। इंजन न होने से मूविंग पार्ट्स बनाने वाला उद्योग खत्म हो जाएगा। कार में बोनट की जगह डिक्की बन जाएगी। सरकार को ई-वाहनों एवं मौजूदा वाहनों के बीच संतुलन बनाना होगा।

जीएसटी की दर 28 से 12 फीसद की जाए

ऑटो पार्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गुरपरगट सिंह काहलों ने कहा कि उद्योग को सबसे बड़ा नुकसान 28 फीसद जीएसटी से हो रहा है। पार्ट्स पर जीएसटी की दर को 28 से कम कर 12 फीसद करना अनिवार्य है। इससे उद्योग में जान आएगी। इंडस्ट्री की उत्पादन लागत कम करने के लिए कैपिटल गुड्स की खरीद पर ब्याज दर चार फीसद की जाए। लागत कम करने के लिए कॉमन सुविधाएं, रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाए।

तकनीक के विकास पर देना होगा जोर

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष और प्रमुख ऑटो पार्ट्स निर्माता न्यू स्वैन ग्रुप के चेयरमैन उपकार सिंह आहूजा ने कहा कि कॉरपोरेट, नए कारपोरेट, पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप कंपनियों के लिए आयकर एक समान किया जाए। छोटे उद्योग संसाधनों की कमी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ) का लाभ भी उद्योग को मिले। आहूजा ने कहा कि बजट में रिसर्च एंड डवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करने होंगे। ओवरसीज रेट पर कर्ज उपलब्ध कराना होगा।

वाहनों पर जीएसटी दर घटाए सरकार तो बने बात

- वर्ष 2019 में वाहनों की बिक्री में आई दो दशक की सबसे बड़ी गिरावट
- ऑटोमोबाइल की एमएसएमई को बजट में विशेष रियायत देने की मांग

यशलोक सिंह, गुरुग्राम : ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आगामी आम बजट से कई उम्मीदें हैं। वर्ष 2019 वाहन उद्योग की दृष्टि से संकटकाल जैसा रहा है। आगे भी ऐसा माहौल नहीं रहे, इसके लिए उद्यमियों द्वारा केंद्र सरकार से आने वाले बजट में विशेष रियायत मांगी जा रही है। इस समय ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग यह है कि वाहनों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की दर को घटाया जाए। गुरुग्राम देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। यहां मारुति, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प और सुजुकी मोटरसाइकिल जैसी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां हैं। इनके लिए ऑटो उपकरण बनाने वाली कंपनियों की संख्या सैकड़ों में है।

पहली फरवरी को केंद्रीय आम बजट लोकसभा में पेश होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार को विभिन्न औद्योगिक संघों एवं संगठनों द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा भी बजट से संबंधित सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि इस क्षेत्र के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को विशेष प्रोत्साहन की दरकार है। जबसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुस्ती का दौर शुरू हुआ है, तब से अब तक एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों की हालत काफी खराब है। बैंकों से मिलने वाले कर्ज में विशेष रियायत की मांग हो रही है। वहीं मशीनों की खरीद में विशेष सब्सिडी के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी से भी इस श्रेणी के उद्योगों को अपग्रेड किया जाए। उद्यमी कह रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले शुल्क को समाप्त किया जाए। पिछले एक साल से वाहनों की बिक्री में गिरावट से जूझ रहे ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए कबाड़ नीति जल्द लाने की मांग हो रही है।

जीएसटी दर में रियायत के साथ-साथ इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। संभावना है कि इलेक्ट्रिक कार इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में भी यह बजट बेहतर साबित होगा।
– मनोज जैन, डायरेक्टर, सुप्रीम रबड़ इंडस्ट्रीज

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन की दरकार है। उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री इस क्षेत्र के लोगों की दिक्कत समझते हुए सुधारवादी कदम उठाएंगी।
–जेएन मंगला, अध्यक्ष, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन

आने वाले केंद्रीय आम बजट से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। इसकी पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर प्रभावी जीएसटी दर 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करेगी। यदि ऐसा होता है, तो इस क्षेत्र के लिए बड़ा कदम होगा।
– दीपक मैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डीएम ऑटोमोटिव

ऑटोमोबाइल क्षेत्र की लंबी सुस्ती से यह क्षेत्र पूरी तरह से परेशान हो गया है। आने वाले आम बजट से इस क्षेत्र की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। यदि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला, तो रौनक फिर से लौट आएगी। वहीं इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का भी विकास होगा।
– केके गांधी, चेयरमैन, राहुल वायर रोप्स

गैर-टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर राहत पर हो रहा विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट से पिछले सप्ताह राहत नहीं मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के सामने 23 जनवरी तक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मद का बकाया भुगतान चुका देने की बाध्यता है। ऐसे में दूरसंचार विभाग (डीओटी) इस पर विचार कर रहा है कि जो गैर-टेलीकॉम कंपनियां कानूनी मामले में पक्षकार नहीं थीं, उनके लिए एजीआर की देनदारी जमा करने के लिए वह तारीख लागू होती है या नहीं। गेल इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जैसी गैर-टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर के मद में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये तक की देनदारी है।

सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले वर्ष अक्टूबर के फैसले के बाद डीओटी ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को भी एजीआर मद का बकाया भुगतान करने संबंधी नोटिस दिया था। उसके बाद टेलीकॉम कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर चली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते वह याचिका भी खारिज कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो सरकारी कंपनियां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं थीं और जिन्हें बकाया भुगतान के लिए कहा गया, वे 23 जनवरी तक भुगतान के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं या नहीं।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकारी गैर-टेलीकॉम कंपनियों पर लागू नहीं होता है। फिर भी, डीओटी इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहता है। एक सूत्र का कहना था कि यह तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजीआर की परिभाषा तय कर देने के बाद देनदारी सरकारी कंपनियों की भी बनती है।

लेकिन अगर वे 23 जनवरी तक बकाया भुगतान नहीं करती हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी, क्योंकि वे मामले में पक्षकार नहीं हैं। एक अन्य अधिकारी का भी कहना था कि पीएसयू के लिए समय-सीमा के कानूनी पहलुओं पर विचार चल रहा है। लेकिन भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को 23 जनवरी तक देनदारियों का भुगतान करना ही होगा।

आपूर्ति घटने पर उड़द दाल आयात बढ़ाने की तैयारी

मांग ▶ कारोबारियों ने कहा – आयात की सीमा खत्म करे सरकार

फसल नष्ट होने के चलते उड़द उत्पादन में करीब 50 प्रतिशत कमी की आशंका है

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार वित्त वर्ष में चार लाख टन तक उड़द दाल खरीदने की योजना को अगले तीन महीने तक बढ़ाने की योजना बना रही है। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय बाजार में दालों की संभावित कमी को देखते हुए सरकार यह फैसला कर सकती है।

इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आइपीजीए) ने सरकार से उड़द दाल आयात की सीमा खत्म करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्ष 2019 के खरीफ सीजन में क्षति की मात्रा ज्यादा है और उत्पादन में करीब 50 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका है। पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय ने उड़द आयात की सीमा चालू वित्त वर्ष के लिए 1.5 लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया था। हालांकि आयात की इजाजत केवल मिलों और रिफाइनरीज को दी गई थी।

सूत्रों का कहना है कि अब तक केवल दो लाख टन उड़द का आयात हो सका है। हाल ही में संबंधित मंत्रालयों ने स्थिति की समीक्षा की। इसमें सब इस बात पर एकमत दिखे कि चार लाख टन तक आयात के लिए अवधि तीन महीने तक बढ़ा देनी चाहिए। आइपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी ने हाल ही में कहा था कि देश में सालाना 25-30 लाख टन उड़द का उत्पादन होता है। खरीफ फसलों की क्षति को देखते हुए उत्पादन में करीब 50 प्रतिशत गिरावट की आशंका है। ऐसे में घरेलू बाजार में आपूर्ति की संभावित कमी को देखते हुए सरकार को आयात सीमा खत्म कर देनी चाहिए।

इस बीच, सरकार ने अपने बफर स्टॉक से करीब पांच लाख टन दाल राज्यों के हाथों और खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत एक लाख टन दाल राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर के भाव पर बेचा जाएगा। इसके अलावा करीब एक लाख टन दाल खुले बाजार में एमएसपी के ऊपर बेचा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दालों के चढ़ते भाव को देखते हुए राज्य सरकारें ज्यादा दालों की खरीद कर सकती हैं। इसके साथ ही कॉपरेटिव संस्था नैफेड भी बफर स्टॉक से होटलों और अन्य बड़े रिटेल स्टोर्स जैसे संस्थागत खरीदारों के हाथों दालों की बिक्री की योजना बना रही है।

ड्यूटी फ्री शॉप से अल्कोहल-सिगरेट खरीद पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स स्थित ड्यूटी फ्री शॉप्स से अल्कोहल और सिगरेट खरीद की मात्रा तय करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने बजट सुझावों के तहत वित्त मंत्रालय से यह आग्रह किया है। वाणिज्य मंत्रालय का सुझाव है कि ड्यूटी फ्री शॉप्स से एक बोतल (एक लीटर) से ज्यादा अल्कोहल खरीदने पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके साथ ही ऐसे शॉप्स से सिगरेट के कार्टन की खरीद को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए।
वर्तमान में भारत आ रहे यात्रियों के लिए इन स्टोर्स से दो बोतल अल्कोहल और एक कार्टन सिगरेट खरीदने की इजाजत है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे कई देश हैं, जिनके एयरपोर्ट्स के ड्यूटी फ्री शॉप्स से अधिकतम एक बोतल अल्कोहल खरीदने की इजाजत है। उनके मुताबिक भारत को भी यही नियम अपनाना चाहिए।
वाणिज्य मंत्रालय का यह सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को यथासंभव घटाकर कारोबारी घाटे को काबू करना चाहती है।

कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसद पर लाए सरकार

- सीआइआइ की मांग – 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी कर ले सरकार
- सभी छूट व इन्सेंटिव को हटाते हुए उठाया जा सकता है यह कदम
- बजट में इस संबंध में घोषणा से उद्योगों व निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी तरह के कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15 फीसद पर ले आना चाहिए। सभी अतिरिक्त छूट व इन्सेंटिव को हटाते हुए टैक्स की यह दर तय की जा सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने आगामी आम बजट में सरकार से इस संबंध में घोषणा की अपील की है। पहली फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी।

बजट की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, विभिन्न सेक्टर की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। हर सेक्टर अपनी जरूरतों के हिसाब से एलान की आस में है। इस बीच उद्योग संगठन सीआइआइ ने पूरे कॉरपोरेट सेक्टर की सामूहिक चिंता को सामने रखते हुए वित्त मंत्री से गुहार लगाई है। सीआइआइ ने अगले तीन साल में सभी तरह के कॉरपोरेट टैक्स की दर एकमुश्त 15 फीसद पर लाने की अपील की है। सीआइआइ के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने कहा, 'आम बजट में इसका खाका खींचा जा सकता है। इसके तहत सभी तरह की छूट और इन्सेंटिव को हटाते हुए कॉरपोरेट टैक्स की दरों को एकमुश्त 15 फीसद पर ला देना चाहिए। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।' उद्योग संगठन का कहना है कि अभी सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के कदमों का नतीजा जमीन पर संतोषजनक तरीके से नजर नहीं आया है। सरकार की ओर से सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का असर नहीं दिखने की एक वजह अलग-अलग टैक्स दरें होना भी है। इस कारण से मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर में टैक्स की दरों में असमानता है। सीआइआइ का कहना है कि बजट में 2023 तक कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसद कर दिए जाने का एलान उद्योग जगत और निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण होगा। यह एलान उद्योग जगत और निवेशकों को अभी फैसला लेने में मदद करेगा।

पिछले साल की थी कटौती

सरकार ने पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 से 22 फीसद करने का एलान किया था। इसके अलावा सरचार्ज व सेस यथावत रखे गए हैं। हालांकि इस टैक्स दर का लाभ लेने वाली कंपनियों को किसी अन्य तरह की छूट या इन्सेंटिव का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा पहली अक्टूबर, 2019 के बाद अस्तित्व में आई और 31 मार्च, 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को केवल 15 फीसद टैक्स देना होगा। इन पर सरचार्ज एवं सेस यथावत रहेंगे।

तीन दशक में आधी हो गई है दर

पिछले तीन दशक में भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर आधी की जा चुकी है। 1991-92 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 45 फीसद थी, जो अब 22 फीसद पर है। इन नई टैक्स दर ने भारत को काफी हद तक ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) तथा ब्रिक्स देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बना दिया है। समय के साथ टैक्स की कम दरों से पूंजीगत लागत कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

प्रकृति पर निर्भर है दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था

- प्रकृति को नुकसान हुआ तो खतरे में पड़ जाएंगे 44 लाख करोड़ डॉलर के उद्योग
- 15 फीसद उद्योगों की बहुत ज्यादा है प्रकृति पर निर्भरता, 37 फीसद पर मिलाजुला खतरा

दावोस, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन और सिमटती जैव विविधता दुनिया की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत घातक है। दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति से जुड़ी कोई भी समस्या सीधे अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। डब्ल्यूईएफ ने अपनी 50वीं वार्षिक बैठक से पहले नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट में विभिन्न प्रजातियों पर मंडराते खतरे और उनसे पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर चिंता जताई गई है। इसके मुताबिक, इंसानों की गतिविधियों के कारण हमारे करीब 25 फीसद वनस्पतियों एवं जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से कई प्रजातियां अगले कुछ दशक में ही विलुप्त हो जाएंगी। 163 इंडस्ट्री सेक्टर और उनके सप्लाई चेन के विश्लेषण में पाया गया कि दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधे से ज्यादा हिस्सा कम या ज्यादा प्रकृति व इससे जुड़ी सेवाओं पर निर्भर है। डब्ल्यूईएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर डोमिनिक वाघरे ने कहा, 'हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों को नए सिरे से तय करने की जरूरत है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति को होने वाले नुकसान से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मूल्य के आधार पर प्रकृति एवं इससे जुड़ी सेवाओं पर करीब 44 लाख करोड़ डॉलर के बराबर की निर्भरता है। प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के कारण इस पूरे ढांचे पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रकृति पर सर्वाधिक निर्भर क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन (चार लाख करोड़ डॉलर), कृषि (2.5 लाख करोड़ डॉलर) और खाद्य एवं पेय (1.4 लाख करोड़ डॉलर) प्रमुख तीन हैं। इनका आकार जर्मनी की कुल अर्थव्यवस्था का करीब दोगुना है। इस तरह के उद्योग या तो सीधे वनों, महासागरों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर हैं, या उपजाऊ मिट्टी, स्वच्छ जल, परागण व स्थिर जलवायु जैसे अन्य कारकों पर। जैसे-जैसे प्रकृति अपनी तरफ से इस तरह की सेवाएं प्रदान करने में अक्षम होती जाएगी, इन उद्योगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर उद्योगों का आकार करीब 13 लाख करोड़ डॉलर और कुछ कम निर्भर उद्योगों का आकार 31 लाख करोड़ डॉलर के बराबर है।

परोक्ष निर्भरता भी बहुत ज्यादा : डब्ल्यूईएफ ने पीडब्ल्यूसी यूके के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कई उद्योग ऐसे भी हैं जिनकी सप्लाई चेन परोक्ष रूप से प्रकृति पर काफी निर्भर है। प्रकृति को होने वाले नुकसान से इन उद्योगों पर अनुमान से ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। छह ऐसे उद्योग हैं जिनके कुल कारोबार का 15 फीसद से कम हिस्सा प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन उनकी सप्लाई चेन का 50 फीसद से ज्यादा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। इनमें केमिकल व मैटेरियल, उड्डयन व ट्रैवल एंड टूरिज्म, रियल एस्टेट, माइनिंग एंड मेटल, सप्लाई चेन व परिवहन तथा रिटेल, कंज्यूमर गुड्स व लाइफस्टाइल से जुड़े उद्योग शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

बड़ा देश, बड़ा खतरा

देश के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी का ज्यादा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में प्रकृति पर निर्भर उद्योगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था का 2.7 लाख करोड़ डॉलर हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। यूरोपीय यूनियन में 2.4 लाख करोड़ डॉलर और अमेरिका में 2.1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है।

मार्केट आउटलुक

बैंकिंग सेक्टर के कई नतीजे इस सप्ताह प्रस्तावित, निवेशकों को बड़ी उम्मीद, बजट से प्रभावित होने वाले सेक्टरों के स्टॉक्स पर भी रहेगी निवेशकों की नजर

तिमाही नतीजों और बजट उम्मीदों पर रहेगा दारोमदार

नई दिल्ली, एजेंसियां : तिमाही नतीजों के महीने में इस सप्ताह भी शेयर बाजारों की चाल कमोबेश चुनिंदा बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों और बजट की उम्मीदों पर ही निर्भर रहने वाली है। जानकारों का कहना है कि विदेशी बाजारों के संभावित चुनिंदा घटनाक्रम भले ही कुछ समय के लिए शेयर बाजारों को प्रभावित करें, लेकिन बाजार कमोबेश एक दायरे में कारोबार करता दिखेगा।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से बड़े इंडेक्स को पीछे छोड़ा है, वह सिलसिला जारी रह सकता है। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में पिछले सप्ताह 3.63 और स्मॉलकैप इंडेक्स में 3.97 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। जानकार मानते हैं कि मिडकैप और स्मॉलकैप का ऐसा प्रदर्शन लंबे अंतराल के बाद आया है और बाजार के लिए अच्छा संकेत है। पिछले सप्ताह पांच में से चार कारोबारी सत्रों में बीएसई के सेंसेक्स ने उछाल दर्ज किया। बीते सप्ताह सेंसेक्स में 345.65 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी में 95.55 अंकों की बढ़ोतरी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका-चीन की कारोबारी तनातनी कुछ कम होने और उनके बीच पहले चरण के कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से दुनियाभर के शेयर बाजारों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में निवेशकों को सभी बड़े नतीजों से सकारात्मक उम्मीद थी। हालांकि उनमें से शेयर बाजार की दो सबसे मूल्यवान कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और टीसीएस के नतीजे शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद आए जिसका असर सोमवार को दिखेगा। लेकिन विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों ने बाजारों का मनोबल ऊंचा बनाए रखा।

इस सप्ताह बैंकिंग सेक्टर के कई दिग्गजों के नतीजे आने हैं। इनमें आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) प्रमुख हैं। जानकारों का कहना है कि ये नतीजे कमोबेश जाहिर कर देंगे कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) में बैंकिंग सेक्टर की हालत कैसी रही है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख (रिटेल रिसर्च) सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि बाजार अपने लगभग सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं। ऐसे में स्टॉक-केंद्रित हलचल ही बाजार को दिशा देंगे। इसके साथ ही आगामी बजट को देखते हुए कृषि, फर्टिलाइजर, पीएसयू, इन्फ्रा और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स में निवेशक रुचि लेते दिख सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक बाजार में ऐसी धारणा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही ने अगले वित्त वर्ष में भी विकास को गति मिलने का आधार पेश कर दिया है। इसके अलावा निवेशक आगामी आम बजट से भी बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं। हालांकि सोमवार को ज्यादातर निवेशकों की नजरें आरआइएल और टीसीएस के शेयरों पर रहने वाली हैं।

प्रतीकात्मक

रिलायंस फिर बनी 10 लाख करोड़ रुपये की कंपनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बार फिर 10 लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया है। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स की 10 शीर्ष कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 62,772.95 करोड़ रुपये का उछाल दर्ज किया गया। इनमें आरआइएल का पूंजीकरण 20,890.58 करोड़ रुपये का उछाल दर्ज किया गया। इसके साथ ही कंपनी 10,02,009.11 करोड़ रुपये पूंजीकरण के साथ सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार शुरू करेगी। एचयूएल, आरआइएल, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में भी पिछले सप्ताह बढ़ोतरी हुई। एचयूएल के बाजार पूंजीकरण में 22,827.94 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,45,778.10 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों में सतर्कता बरत सकती है सरकार

नई दिल्ली, आइएएनएस : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सतर्कता बरत सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बहुत ज्यादा सकारात्मक अनुमान लगाने वाला दौर बीत गया है। बजट में वित्त मंत्री नॉमिनल जीडीपी की विकास दर 9.5 से 10 फीसद के करीब रहने का अनुमान पेश कर सकती हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस बार नॉमिनल जीडीपी का आकलन वास्तविकता के काफी करीब रखा जा सकता है। राजस्व संग्रह और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य भी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रखे जाएंगे। वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट आंकड़ों में पारदर्शिता रखने और बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं रखने की कोशिश में लगा है। नॉमिनल ग्रोथ का बहुत ऊंचा अनुमान निवेशकों, बाजार और रेटिंग एजेंसियों के सामने अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर पेश करने में भूमिका निभाता है।

09 लाख से अधिक लोग अमेरिका में हिंदी भाषा बोलते हैं। यहां भारतीय दूतावास में प्रभारी राजनयिक अमित कुमार ने एक समारोह में कहा कि यह उल्लेख करना सुखद है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंदी बोली और सिखाई जाती है।

न्यूज गैलरी

स्पेस एक्स के मानवरहित कैप्सूल का परीक्षण सफल

केप केनेवरल : एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के मानवरहित एस्ट्रोनॉट कैप्सूल की रविवार को हुई आपात लैंडिंग सफल रही। यह कैप्सूल दिन 10 .30 बजे लांच किया गया था। आठ मिनट बाद यह 32 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के केप केनेवरल में यह सफलतापूर्वक उतर गया। इस दौरान इसने समुद्र तल से 19 किलोमीटर ऊपर खुद को रॉकेट से भी अलग किया। अमेरिका के नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक जिम ब्रिडेंस्टीन ने मिशन को सफल करार दिया है। जिम ब्रिडेंस्टीन ने अपने ट्वीट में लिखा– इस मुश्किल परीक्षण ने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को अमेरिकी रॉकेट के जरिये अमेरिकी धरती से लांच करने की श्रेष्ठता को एक बार फिर से साबित किया है। इस दौरान स्पेस एक्स ने अपनी बचाव कार्यों का भी परीक्षण किया। इस मौके पर किसी अनहोनी से निपटने के लिए अमेरिकी वायुसेना की टीम भी मौजूद थी। स्पेस एक्स के मालिक मस्क भी परीक्षण की सफलता को लेकर आशंकित थे। परीक्षण से पहले उन्होंने इस आशय का ट्वीट भी किया था , लेकिन परीक्षण की सफलता के बाद उन्होंने संतोष और प्रसन्नता जाहिर की। (रायटर)

लीबिया से हफ्तार समर्थक बलों ने तेल निर्यात रोका

त्रिपोली : सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार समर्थक बलों ने लीबिया के प्रमुख बंदरगाहों से तेल निर्यात रोक दिया है। राष्ट्रीय तेल कंपनी यह जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि इस वजह से देश का कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन 13 लाख बैरल से घटकर पांच लाख बैरल रह जाएगा और इससे प्रतिदिन 5 .5 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। लीबिया के उत्तरपूर्व समुद्र तट पर निर्यात की पूरी श्रृंखला पर हफ्तार का नियंत्रण है। वर्ष 2006 से हफ्तार समर्थक सैन्य बलों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड (जीएनए) के बीच लड़ाई चल रही है। (एएफपी)

शी के नाम के गलत अनुवाद के लिए फेसबुक ने माफी मांगी

नेपीता : चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की म्यांमार यात्रा के दौरान फेसबुक पर उनके नाम का बर्मी भाषा से अंग्रेजी में हुए गलत अनुवाद के लिए फेसुबक ने माफी मांगी है। म्यांमार की राजधानी नेपीता की शी चिनफिंग की यह दो दिवसीय यात्रा किसी चीनी नेता की दो दशकों में पहली यात्रा है। म्यांमार के फेसबुक पेज पर शी के नाम का गलत अनुवाद हो गया था। फेसबुक पोस्ट में बर्मी भाषा से अंग्रेजी में हुए अनुवाद में शी चिनफिंग का नाम 'मिस्टर शिटहोल' लिखा गया था। (एएफपी)

ऑस्ट्रेलिया में कुआला बचाने की मुहिम

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग का सर्वाधिक असर वन्यजीवों पर पड़ा है। आग से करीब पचास करोड़ वन्यजीवों को प्राण गंवाने पड़े हैं। कंगारू द्वीप में कोआला की आबादी घटकर आधी रह गई है। अब कोआला को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कंगारू द्वीप में बने वाइल्डलाइफ इमरजेंसी रेस्पांस सेंटर में घायल कुआलाओं का उपचार किया जा रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आगजनी से लोगों को राहत मिली है। रायटर

अब शाही उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हैरी और मेगन

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन में शाही दर्जा छोड़ने का फैसला करने वाले प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल अब शाही उपाधि (हिज और हर रॉयल हाईनेस) का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोनों को शाही कर्तव्यों के लिए किसी प्रकार का सार्वजनिक कोष भी नहीं दिया जाएगा। बकिंघम पैलेस के अनुसार, यह नई व्यवस्था अगले कुछ दिनों में लागू होगी। हैरी और मेगन ने इस साल की शुरुआत में शाही दर्जा छोड़ने का फैसला किया था।

बीबीसी के मुताबिक ड्यूक ऑफ ससेक्स हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन अब औपचारिक रूप से महारानी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। दंपती को विंडसर कैसल स्थित घर की मरम्मत पर खर्च हुए करदाताओं के 24 लाख पौंड (22 करोड़ रुपये से ज्यादा) की राशि भी वापस करनी होगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हमें खुशी है कि परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर मेरे पोते और परिवार के लिए सृजनात्मक और सहयोगात्मक रास्ता तलाश लिया है। हैरी, मेगन और उनका बेटा आर्ची हमेशा मेरे परिवार के प्रिय सदस्य रहेंगे। मैं उन चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं जो उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान अनुभव की हैं। मैं उनके स्वतंत्र जीवन की इच्छा का समर्थन करती हूं। पूरे परिवार की तरफ से मैं यह उम्मीद करती हूं कि आज का समझौता उन्हें सुखी और शांतिपूर्ण जीवन शुरू करने में सहयोग करेगा।

▸ घर की मरम्मत पर खर्च हुई 22 करोड़ से ज्यादा की राशि भी करनी होगी वापस

पिता ने मेगन पर लगाया शाही परिवार की प्रतिष्ठा कम करने का आरोप : प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन के पिता थॉमस ने अपनी बेटी पर शाही परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है। चैनल 5 को दिए इंटरव्यू में थॉमस ने कहा, हर लड़की का सपना राजकुमारी बनने का होता है और उसका यह सपना पूरा भी हो गया था, लेकिन अब वह इससे दूर जा रही है।

डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मर्केल और ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी। फाइल/एपी

ट्रंप पर लगे आरोप निर्लज्ज और गैरकानूनी

महाभियोग मामला ▸ राष्ट्रपति के वकीलों ने जताया कड़ा विरोध, कहा– रची गई है साजिश

सीनेट के समन पर दाखिल किया जवाब, प्रस्ताव खारिज करने का अनुरोध

वाशिंगटन, प्रेट्र : ीनेट से मिले समन के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों पर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए दोनों आरोप निर्लज्जता से भरे और गैरकानूनी हैं। इन आधारहीन आरोपों के जरिये अमेरिकी मतदाताओं द्वारा चुने गए राष्ट्रपति को हटाने की साजिश रची गई है। ट्रंप पर निजी हित के लिए पद के दुरुपयोग और संसदीय जांच में बाधा पहुंचाने के आरोप में महाभियोग चलाया जा रहा है। प्रतिनिधि सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

संसद के उच्च सदन सीनेट में शुरू हुई महाभियोग की प्रक्रिया में ट्रंप को सफाई देने के लिए समन दिया गया है। ट्रंप की ओर से उनके वकीलों की टीम ने शनिवार को जवाब दाखिल किया। वकीलों ने छह पेज के अपने जवाब में कहा है कि यह कोशिश 2016 के चुनाव परिणाम को पलटने और 2020 के चुनाव का परिणाम प्रभावित करने के लिए हो रही है। ट्रंप विरोधियों की ओर से यह जल्दबाजी में उठाया गया बेहद पक्षपातपूर्ण कदम है। जवाब में सीनेट से अनुरोध किया गया है कि वह दो आरोपों वाले इस महाभियोग प्रस्ताव को अविलंब खारिज कर दे। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव सीनेट में भेजा है, जहां पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है।

ट्रंप सरकार के खिलाफ देशव्यापी मार्च : अमेरिका में देशव्यापी महिला मार्च के दौरान वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास व्हाइट हाउस के बाहर महिलाओं ने झंडे, बैनर और स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रंप सरकार की जलवायु परिवर्तन, इक्विटी भुगतान, गर्भपात कानून और आव्रजन नीति जैसे मुद्दों को लेकर मार्च निकाला गया था। सत्ता संभालने के बाद महिलाओं को लेकर ट्रंप की कथित टिप्पणी से नाराज होकर इस मार्च की शुरुआत की गई थी। एपी

प्रतिनिधि सभा ने अपने सात सदस्यों को ट्रंप पर लगे आरोपों को सीनेट के सामने रखने के लिए नामित किया है। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एडम स्किफ भी शामिल हैं। उन्होंने ही ट्रंप पर लगे आरोपों की जांच के लिए बनी समिति की अगुआई की थी। सीनेट में आरोपों और ट्रंप की सफाई पर बहस के बाद मंगलवार को ही मतदान होने की उम्मीद है। प्रस्ताव पारित होने के लिए 100 सदस्यों वाली सीनेट में 67 सदस्यों का समर्थन चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सदन में ऐसा होना लगभग असंभव है।

बता दें कि बिल क्लिंटन महाभियोग मामले को लेकर चर्चा में रहे केन स्टार और देश के सबसे बड़े सेलिब्रेटी वकील एलन देरशोविज भी सीनेट में ट्रंप के बचाव में उतरे हैं। उनकी टीम का नेतृत्व व्हाइट हाउस के वकील पैट सिपलोन करेंगे।

सांसदों पर अभूतपूर्व पाबंदी

महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सीनेट में अभूतपूर्व घोषणा हुई है। चर्चा के दौरान सांसदों को उपस्थित रहना है, शांत रहना है और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। पहली बार 1868 में तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन और दूसरी बार 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ आए महाभियोग प्रस्तावों पर बहस के दौरान पाबंदियों की घोषणा हुई थी। लेकिन उस समय स्मार्ट फोन चलन में नहीं था। इस लिहाज से इस बार की पाबंदियां अभूतपूर्व हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की चेतावनी पर ईरान के तेवर ढीले

दुबई, रायटर : प्रमुख यूरोपीय देशों के दबाव में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर विचार कर सकता है। वह देश के परमाणु संयंत्रों के संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण में भी सहयोग के लिए तैयार हो सकता है। इस बात के संकेत ईरानी संसद के स्पीकर अली लारीजानी ने दिए हैं।

लारीजानी का इस आशय का बयान 2015 के परमाणु समझौते पर दस्तखत करने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के कड़े रुख के बाद आया है। तीनों देशों ने कहा था कि अगर ईरान समझौते से हटता है और परमाणु कार्यक्रम को गति देता है तो उस पर फिर से पहले वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ये प्रतिबंध 2015 के परमाणु समझौते के परिणामस्वरूप हटे थे। 2018 में समझौते से अमेरिका के हटने के बावजूद ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन, रूस और चीन के साथ कई मामलों में संबंध सामान्य हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी लागू हो गए तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए यूरोपीय देशों की हालिया चेतावनी पर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने की अपनी घोषणा पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। साथ ही पूर्व की भांति संयंत्रों के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए भी सहमत होने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के अलावा समझौते में शामिल बाकी के पांच देश इसे बनाए रखने के पक्षधर हैं। अमेरिका से अलग सोच लेकर चल रहे यूरोपीय देश इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की बात न मानते हुए अभी तक ईरान के साथ बने हुए हैं।

▸ कहा, परमाणु संयंत्रों के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को तैयार

ईरान में गिराए विमान के 11 यात्रियों के शव यूक्रेन पहुंचे

कीव, एएफपी : राष्ट्रीय झंडे से लिपटे ताबूतों में यूक्रेन के 11 नागरिकों के शव रविवार को राजधानी कीव के एयरपोर्ट पहुंचे। ये शव उन लोगों के हैं जिनके विमान को बीती आठ जनवरी को तेहरान से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ईरानी सेना ने मिसाइल से मार गिराया था। इस हादसे में 176 लोग मारे गए थे। ईरानी सेना ने यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने को गलती बताया है। कीव पहुंचे शवों में नौ विमान के चालक दल के सदस्यों के हैं जबकि दो यात्रियों के हैं।

ब्लैक बॉक्स देने के बयान से पलटा : मार गिराए गए यात्री विमान का ब्लैक बॉक्स यूक्रेन को दिए जाने के बयान से ईरान पलट गया है। हादसे की जांच कर रहे ईरानी अधिकारी हसन रेजाफर ने कहा है कि डाटा रिकॉर्डर किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता।

हांगकांग में फिर सामने आए पुलिस और प्रदर्शनकारी

हांगकांग, रायटर : हांगकांग की पुलिस ने रविवार को यहां एक पार्क में एकत्र हुए हजारों लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मीडिया में आई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों का पीछा करती दिख रही है। कई को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बख्तरबंद वाहन और वाटर कैनन का भी इंतजाम किया था, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया।

'यूनिवर्सल सीज अगेंस्ट कम्युनिच्म' नामक इस प्रदर्शन के लिए आयोजकों ने आवेदन किया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ रैली की अनुमति दी थी। रैली शुरू होते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे। काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने छाते और मेज-कुर्सी लगाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और पत्थरों से स्ट्रीट लाइट तोड़ डालीं। पुलिस ने कहा है कि दो पुलिसकर्मियों पर छड़ी से हमला किया गया जिससे उनके सिर पर चोट आई। प्रदर्शनकारियों की तलाशी लेने का काम कर रहे पुलिसवालों पर पानी की बोतलें भी फेंकी गईं। बता दें कि यह आंदोलन आठ माह से जारी है।

नाइजीरिया में अपहृत 19 भारतीय मुक्त, एक की मौत

समुद्री लुटेरों ने एमवी ड्यूक नामक जहाज पर बोला था धावा। प्रतीकात्मक

▸ समुद्री लुटेरों ने व्यावसायिक जहाज से 15 दिसंबर को किया था अगवा

▸ भारतीय उच्चायोग ने नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों से मांगी थी मदद

अबुजा, प्रेट्र : अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट के पास से अपहृत 19 भारतीयों को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि, एक भारतीय की कैद के दौरान मौत हो गई। सभी भारतीय एक व्यावसायिक जहाज पर सवार थे और उनका बीच समुद्र से लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। नाइजीरिया के भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी।

उच्चायोग ने रविवार को ट्वीट के जरिये बताया कि अगवा 19 भारतीयों को समुद्री लुटेरों के कब्जे से शनिवार को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि, अपहरण के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में रखे जाने के कारण एक की मौत हो गई। भारत ने अपहृत भारतीयों को मुक्त कराने में मदद के लिए नाइजीरिया के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, 'समुद्री लुटेरों ने 20 भारतीयों का 15 दिसंबर को एमवी ड्यूक नामक जहाज से अपहरण कर लिया था। भारत सरकार और उच्चायोग ने नाइजीरिया सरकार के साथ मिलकर अपहृत लोगों को मुक्त कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर काम किया।' उल्लेखनीय है कि भारतीय उच्चायोग ने नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों से अपहृत लोगों को मुक्त कराने में मदद मांगी थी। उच्चायोग ने एक भारतीय की मौत पर दुख जताया है।

यमन में मस्जिद पर मिसाइल हमले में 100 सैनिकों की मौत

दुबई, एएफपी : यमन के मारिब प्रांत में हाउती विद्रोहियों द्वारा एक मस्जिद पर किए गए मिसाइल हमले में 100 से अधिक सैनिकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह हमला शनिवार को उस समय किया गया जब सैनिक शाम की नमाज अदा कर रहे थे।

यमन के राष्ट्रपति आबिद रब्बू मंसूर हादी ने इस कायराना हमले की निंदा की है। हादी ने कहा, हाउती विद्रोहियों के इस हमले ने साबित कर दिया है कि वह देश में शांति स्थापित करने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना चाहते। वे मौत और विनाश के अलावा कुछ और नहीं जानते। फिलहाल हाउती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हाउती विद्रोहियों ने 2014 के अंत में यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी के साथ वहां गृहयुद्ध शुरू हो गया।

तभी से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी द्वारा मान्यता प्राप्त यमन सरकार के सैनिक सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के साथ मिलकर विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं।

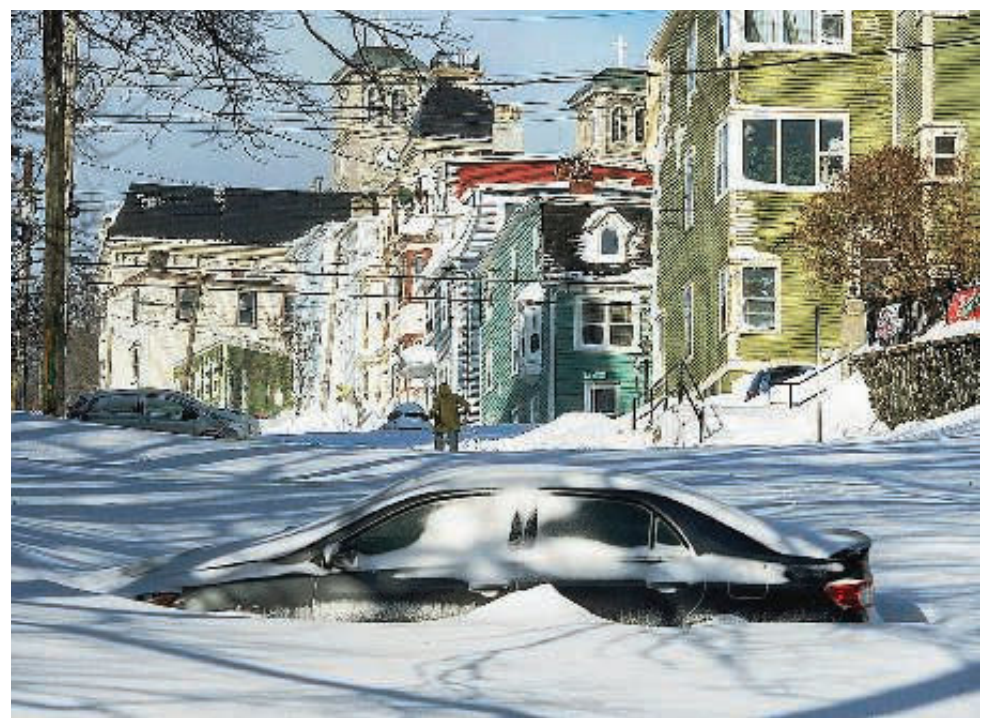

कनाडा में बर्फीला तूफान का कहर

कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रांत में बर्फीले तूफान का कहर टूट पड़ा है। यह तस्वीर अटलांटिक तट से सटे न्यूफाउंडलैंड के शहर सेंट जॉन्स की है, जहां सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी की वजह से आपातकाल घोषित किया गया है। यहां व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया और यातायात पूरी तरह से ठप है। एपी

चिंताजनक

वुहान शहर में 17 और लोग भी आए चपेट में, भारतीय शिक्षिका के पीड़ित होने की बात को पति ने नकारा, इसके कारण अब तक दो लोगों की हो चुकी है मौत

चीन में बढ़ रहा है वायरल न्यूमोनिया का प्रकोप

बीजिंग, प्रेट्र : चीन के शहर वुहान में 17 नए लोगों के वायरल न्यूमोनिया की चपेट में आने का पता चला है। इस तरह इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 62 हो गई है। अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 19 को इलाज के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। बाकी का इलाज चल रहा है। शेनजेन में एक भारतीय शिक्षिका के भी इससे पीड़ित होने का पता चला था, लेकिन बाद में उसके पति ने कहा कि वह वास्तव में स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण से पीड़ित थी।

शेनजेन के इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक प्रीति माहेश्वरी (45) को पिछले शुक्रवार को गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में व्यापारी पति अंशुमान खोवाल ने बताया कि प्रीति का आइसीयू में इलाज चल रहा है और उन्हें वेंटीलेटर सहित अन्य जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है। शुरुआत में प्रीति के कोरोनावायरस से पीड़ित होने का अंदेशा था, लेकिन बाद में पति ने कहा कि उसकी पत्नी स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण से पीड़ित थी। स्ट्रेप्टोकोकल के दो प्रकार हैं। ए और बी। दोनों के ही लक्षण कोरोनावायरस से मिलते-जुलते हैं। बता दें कि इसकी वजह एक नए प्रकार के कोरोना वायरस को माना जा रहा है। इसी तरह के एक वायरस से 2002 में सार्स (एसएआरएस) संबंधी बीमारी फैली थी। चीन के दक्षिणी इलाके से शुरू हुई इस बीमारी की चपेट में आकर दो दर्जन देशों के 800 लोगों की मौत हुई थी।

वाशिंगटन में यात्रियों का एयरपोर्ट छोड़ने से पहले गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एएफपी

भारत ने जारी की यात्रा एडवाइजरी : वुहान शहर में वायरल न्यूमोनिया के प्रकोप को देखते हुए भारत ने चीन जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत द्वारा जारी यात्रा चेतावनी में कहा गया कि चीन में संक्रामक नोवेल कोरोनावायरस का पता चला है। 11 जनवरी तक 41 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि वुहान के विश्वविद्यालयों के मेडिकल कॉलेजों में लगभग पांच सौ भारतीय छात्र पढ़ते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के चलते भारत आने के लिए निकले हैं।

क्या है कोरोना वायरस : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों में आमतौर पर जुखाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसे शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद ये लक्षण न्यूमोनिया में बदल जाते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी तक इस वायरस से निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है।

फेसबुक वीडियो ने 48 साल बाद बांग्लादेशी को परिवार से मिलाया

ढाका, आइएएनएस : फेसबुक वीडियो की मदद से एक बांग्लादेशी व्यक्ति 48 साल बाद अपने परिवार से फिर मिल सका। सीमेंट का व्यापार करने वाले हबीबुर रहमान काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे और तभी से लापता थे।

द डेली स्टार अखबार के मुताबिक हबीबुर सिलहट के बाजग्राम में रहते थे। जब वह लापता हुए उनकी उम्र 30 साल थी। परिजनों ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बीते शुक्रवार को अमेरिका में रहने वाले हबीबुर के बड़े बेटे की पत्नी ने फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसमें बांग्लादेश के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज की आर्थिक मदद की अपील की गई थी। बेटे की पत्नी ने हबीबुर को देखा तो नहीं था, लेकिन पति और सास से उनकी कई कहानियां सुनी थीं। इस पर उन्होंने वीडियो पति से शेयर किया। उन्होंने बांग्लादेश स्थित अपने भाइयों से अस्पताल जाकर मरीज का पता लगाने को कहा। शनिवार को उनके भाई अस्पताल गए और यह देखकर हैरान रह गए कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति उनके पिता हैं। हबीबुर के बेटे ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी मां और मेरे चाचा ने पिता को सालों खोजने का प्रयास किया। पिता का इंतजार करते-करते मां की वर्ष 2000 में मौत हो गई।' पता चला है कि पिछले 25 सालों से हबीबुर मौलवी बाजार के रायोसरी इलाके में रह रहे थे और रजिया बेगम नाम की महिला उनकी देखभाल करती थी। रजिया ने बताया कि उसके परिवार के लोगों को हबीबुर 1995 में हजरत शाहबुद्दीन की दरगाह पर बीमार हालत में मिले थे। वह खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। वह तब से हमारे साथ रह रहे हैं। बेहतर इलाज के लिए हबीबुर के बेटों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

▸ 30 साल की उम्र में कारोबार के सिलसिले में घर से निकलने के बाद हो गए थे लापता

बराबरी का मुकाबला

ये भी जानिए

भारतीय तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी ने लिस्ट-ए के 107वें मैच में 200 विकेट पूरे किए। इनमें से 143 विकेट उन्होंने 76 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में लिए हैं।

स्मिथ की मेहनत पर रोहित-कोहली ने फेरा पानी

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराया, शर्मा ने 119 व विराट ने बनाए 89 रन, टीम के काम नहीं आए स्टीव के 131 रन

ऑस्ट्रेलिया को रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीसरे वनडे मैच में हराने के बाद खिताबी ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी ● एपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : ऑस्ट्रेलिया (बल्लेबाजी)
परिणाम : भारत सात विकेट से जीता

मैन ऑफ द मैच : रोहित शर्मा
मैन ऑफ द सीरीज : विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया 286/9 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
डेविड वार्नर का. राहुल बो. शमी	03	07	00	00
आरोन फिंच रन आउट	19	26	01	01
स्टीव स्मिथ का. अय्यर बो. शमी	131	132	14	01
लाबुशाने का. कोहली बो. जडेजा	54	64	05	00
स्टार्क का. सब (चहल) बो. जडेजा	00	03	00	00
एलेक्स कैरी का. अय्यर बो. कुलदीप	35	36	06	00
एश्टन टर्नर का. राहुल बो. सैनी	04	10	00	00
एश्टन एगर नाबाद	11	13	00	00
पैट कमिंस बो. शमी	00	01	00	00
एडम जांपा बो. शमी	01	06	00	00
जोश हेजलवुड नाबाद	01	02	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-14, वा-13) 27, कुल : 50 ओवर में

नौ विकेट पर 286 रन
विकेट पतन : 1-18 (वार्नर, 3.2), 2-46 (फिंच, 8.5), 3-173 (लाबुशाने, 31.3), 4-173 (स्टार्क, 31.6), 5-231 (कैरी, 41.4), 6-238 (टर्नर, 43.6), 7-273 (स्मिथ, 47.1), 8-276 (कमिंस, 47.4), 9-282 (जांपा, 49.2)
गेंदबाजी :
बुमराह 10-0-38-0
शमी 10-0-63-4
सैनी 10-0-65-1
कुलदीप 10-0-62-1
जडेजा 10-1-44-2

भारत 289/3 (47.3 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. स्टार्क बो. जांपा	119	128	08	06
केएल राहुल एलबीडब्ल्यू बो. एगर	19	27	02	00
विराट कोहली बो. हेजलवुड	89	91	08	00
श्रेयस अय्यर नाबाद	44	35	06	01
मनीष पांडे नाबाद	08	04	02	00

अतिरिक्त : (लेबा-2, वा-8) 10
कुल : 47.3 ओवर में तीन विकेट पर 289 रन, विकेट पतन :

1-69 (राहुल, 12.3), 2-206 (रोहित, 36.4), 3-274 (विराट, 45.5)
गेंदबाजी : कमिंस 7-0-64-0
मिशेल स्टार्क 9-0-66-0
जोश हेजलवुड 9.3-1-55-1
एश्टन एगर 10-0-38-1
एडम जांपा 10-0-44-1
मार्नस लाबुशाने 1-0-11-0
आरोन फिंच 1-0-9-0

बेंगलुरु, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की शानदार पारियों की मदद से भारत ने यहां रविवार को तीसरे व अंतिम वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस साल की शुरुआत ही कोहली की टीम के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि उसका सामना मजबूत ऑस्ट्रेलिया से था। सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम को मुंबई में 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और लग रहा था कि भारत यह सीरीज गंवा देगा। लेकिन, फिर राजकोट में दूसरे वनडे में 36 रन से जीत हासिल करके टीम इंडिया ने सीरीज में वापसी की और अंतिम मैच जीतकर सीरीज भी जीत ली।

स्टीव स्मिथ के नौवें वनडे शतक के बाद भारत ने आखिरी 10 ओवर में शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 286 रन पर रोक दिया। स्मिथ ने लगभग तीन साल बाद वनडे में शतक जड़ा है। स्मिथ ने 132 गेंद में 131 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल सका। उनके अलावा मार्नस लाबुशाने ने 64 गेंद में 54 रन बनाए। मुहम्मद शमी ने अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। उन्होंने 10 ओवर में 63 रन देकर चार विकेट लिए। जवाब में रोहित (119) और कोहली (89) की मदद से भारत ने 47.3 ओवर में तीन विकेट पर 289 का स्कोर कर मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। उनके अलावा श्रेयस अय्यर (नाबाद 44) ने उपयोगी योगदान दिया।

रोहित ने जगाई उम्मीद: रोहित के साथ लोकेश राहुल भारतीय पारी का आगाज करने उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। राहुल (19) को एगर ने एलबीडब्ल्यू आउट करके मेजबान टीम को शुरुआती झटका दिया। हालांकि शुरुआती विकेट गिरने का असर रोहित पर नहीं दिखा और वह एक छोर से रन कूटते रहे। उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर एक रन लेकर अपने करियर का 29वां वनडे शतक पूरा किया। इसके बाद वह जांपा की गेंद पर स्टार्क को कैच देकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की। इसके बाद का काम कोहली और अय्यर ने पूरा किया।

कंगारुओं को शुरुआती झटका: इससे पहले लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, लेकिन इस बार बल्लेबाजी का फैसला किया। कोहली ने पिछला मैच जीतने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया, हालांकि रिषभ पंत चयन के लिए उपलब्ध थे। केएल राहुल लगातार दूसरे मैच में विशेषज्ञ विकेटकीपर के रूप में उतरे। ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाजों डेविड वार्नर (03) और आरोन फिंच (19) के विकेट जल्दी गंवा दिए। शमी ने वार्नर को बाहर जाती बेहतरीन गेंद पर पवेलियन भेजा। दूसरी ओर, फिंच के रन आउट के लिए स्मिथ कसूरवार रहे, जिन्होंने कप्तान को रन लेने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में मन बदल लिया। आम तौर पर शांत रहने वाले फिंच गुस्से में ड्रेसिंग रूम की तरफ गए।

स्मिथ-लाबुशाने का तालमेल: पहले पावरप्ले में ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 56 रन बनाए, जब स्मिथ और लाबुशाने क्रीज पर थे। दोनों ने 127 रन की साझेदारी में शानदार तरीके से आपसी तालमेल का परिचय दिया। राजकोट वनडे में 46 रन बनाने वाले लाबुशाने ने यहां अर्धशतक लगाया। वह बड़ी पारी की ओर अग्रसर लग रहे थे, लेकिन कोहली ने उनका दर्शनीय कैच लपका। रवींद्र जडेजा ने इसी ओवर में दूसरा विकेट लिया, जब एलेक्स कैरी से पहले भेजे गए मिशेल स्टार्क ने डीप मिडविकेट में कैच थमाया। स्मिथ और कैरी (35) ने पांचवें विकेट के लिए 58 रन जोड़े, लेकिन कैरी ज्यादा देर टिक नहीं सके। दूसरे वनडे में शतक से दो रन से चूके स्मिथ ने थर्डमैन पर एक रन लेकर तिहरा अंक छुआ। उन्होंने 46वें ओवर में नवदीप सैनी पर एक छक्का और एक चौका लगाया। इसके बाद बुमराह को लगातार दो चौके लगाए। वह डीप मिडविकेट पर श्रेयस अय्यर को कैच देकर लौटे। शमी ने आखिरी ओवरों में पैट कमिंस और एडम जांपा को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 10 ओवर में 63 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए।

नादकर्णी के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेली भारतीय टीम

बेंगलुरु, प्रेट्र: भारतीय टीम रविवार को यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में दिवंगत बापू नादकर्णी के सम्मान में अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर बापू का शुक्रवार को निधन हो गया था। वह 86 साल के थे।

चोटिल धवन ने नहीं की बल्लेबाजी

बेंगलुरु: भारतीय ओपनर शिखर धवन यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में चोटिल हो गए। क्षेत्ररक्षण करने के दौरान उनके बायें कंधे में चोट आई है। इसके बाद वह रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। ऑस्ट्रेलियाई पारी के पांचवें ओवर में धवन कवर क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और उन्होंने आरोन फिंच के शॉट को रोकने के लिए छलांग लगाई, जिससे उनका बायां कंधा चोटिल हो गया। बीसीसीआइ ने कहा, 'धवन को एक्स-रे के लिए ले जाया गया है।' उनके बाहर जाने के बाद युजवेंद्रा सिंह चहल मैदान पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे।

वनडे में एक टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के सर्वाधिक शतक

शतक	बल्लेबाज	बनाम
9	कोहली	वेस्टइंडीज
9	तेंदुलकर	ऑस्ट्रेलिया
8	कोहली	ऑस्ट्रेलिया
8	कोहली	श्रीलंका
8	तेंदुलकर	श्रीलंका
8	रोहित	ऑस्ट्रेलिया

131 रनों की पारी खेलने वाले स्मिथ ने भारत के खिलाफ तीसरा वनडे शतक लगाया

29 वनडे शतक के लिए पारी

पारी	बल्लेबाज	देश
185	कोहली	भारत
217	रोहित	भारत
265	तेंदुलकर	भारत
330	पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया

09 वां वनडे शतक जड़ा स्टीव स्मिथ ने। इस प्रारूप में उन्होंने पिछला शतक पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2017 में पर्थ में लगाया था। उस मैच में उन्होंने नाबाद 108 रन बनाए थे

सबसे कम पारी में 9000 वनडे रन

पारी	बल्लेबाज	देश
194	विराट कोहली	भारत
205	एबी डिविलियर्स	द. अफ्रीका
217	रोहित शर्मा	भारत
228	सौरव गांगुली	भारत
235	सचिन तेंदुलकर	भारत

7000 से ज्यादा रन वनडे में विराट कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 133 पारियों में बनाए हैं। उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर आता है जिन्होंने इतने रन के लिए 180 पारियां खेली थी

सबसे कम पारियों में 4000 वनडे रन वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

पारी	बल्लेबाज
93	डेविड वार्नर
102	डीन जोंस
105	आरोन फिंच
106	ज्यॉफ मार्श
106	स्टीव स्मिथ
110	मैथ्यू हेडन

9000 रन वनडे क्रिकेट में पूरे किए रोहित शर्मा ने। ऐसा करने वाले वह भारत के सातवें और कुल 20वें बल्लेबाज हैं

वनडे में सर्वाधिक शतक

शतक	बल्लेबाज	देश
49	तेंदुलकर	भारत
43	कोहली	भारत
30	पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया
29	रोहित	भारत
28	जयसूर्या	श्रीलंका
27	अमला	द. अफ्रीका
25	डिविलियर्स	द. अफ्रीका
25	क्रिस गेल	वेस्टइंडीज

2021 में भी धौनी सीएसके में बरकरार रहेंगे : श्रीनिवासन

चेन्नई, प्रेट्र: बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा कि महेंद्र सिंह धौनी भारत के लिए दोबारा खेलें या नहीं, लेकिन 2021 में आइपीएल नीलामी के दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) द्वारा उन्हें टीम में बरकरार रखा जाएगा। बीसीसीआइ के केंद्रीय अनुबंध में दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान को नहीं चुना गया, जिससे पिछले कुछ दिनों में उनके संन्यास लेने को लेकर अफवाहें तेज हो गईं।

इंडिया सीमेंट्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि धौनी अपनी फ्रैंचाइजी के लिए खेलना जारी रखेंगे। श्रीनिवासन ने इंडिया सीमेंट्स के कार्यक्रम में कहा, 'लोग कहते रहते हैं कि वह कब संन्यास लेंगे। वह कब तक खेलेंगे, आदि। वह खेलेंगे। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। वह इस साल खेलेंगे। अगले साल वह नीलामी में शामिल होंगे और उन्हें रिटेन किया जाएगा। किसी के मन में कोई संदेह नहीं है।' धौनी 2008 में आइपीएल के उद्घाटन सत्र के बाद से सीएसके का हिस्सा रहे हैं और जब फ्रैंचाइजी को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था तो ही वह उनके लिए नहीं खेले थे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टीम का नेतृत्व करते हुए तीन बार आइपीएल खिताब भी दिलाया।

बीसीसीआइ ने गुरुवार को केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से उन्हें बाहर कर दिया, जिससे भारत के पूर्व कप्तान के भविष्य पर संदेह पैदा हो गया, जो पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से नहीं खेले हैं। धौनी को हाल में झारखंड टीम के साथ नेट पर अभ्यास करते हुए देखा गया। 38 साल के धौनी केंद्रीय अनुबंध में ए कैटिगरी में थे जिसमें एक खिलाड़ी को वार्षिक रिटेनरशिप के रूप में पांच करोड़ रुपये मिलते हैं।

विश्वास

- कहा, वह नीलामी में शामिल होंगे और उन्हें रिटेन किया जाएगा
- बीसीसीआइ ने एमएस को केंद्रीय अनुबंध से कर दिया है बाहर

अंडर-19 विश्व कप में जीता भारत

ब्लोमफोंटेन (द. अफ्रीका), प्रेट्र: सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (59), कप्तान प्रियम गर्ग (56) और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (नाबाद 52) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से गत चैंपियन भारत ने रविवार को यहां आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को 90 रन से शिकस्त दी।

भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 50 ओवर में चार विकेट पर 297 रन बनाए और फिर श्रीलंका को 45.2 ओवर में 207 रन पर समेट दिया। भारतीय स्पिनरों सिद्देश वीर और रवि बिश्नोई एवं तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने दो-दो विकेट लिए।

भारत के लिए प्रियम ने 72 गेंद में दो चौके की मदद से 56 रन बनाए, जबकि यशस्वी ने 74 गेंद की पारी में आठ चौके लगाए। जुरेल थोड़े आक्रामक रहे, जिन्होंने 48 गेद की नाबाद पारी में तीन चौके व एक छक्का लगाया। सिद्धेश ने भी स्कोर को 297 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 27 गेंद में छह चौके और एक छक्के की मदद से 44 रन की नाबाद पारी खेली।

पृथ्वी ने शतक के साथ की वापसी, भारत-ए जीता

लिंकन (न्यूजीलैंड), प्रेट्र: पृथ्वी शॉ ने भारत-ए के लिए न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच के दौरान 100 गेंद में 150 रन की आक्रामक शतकीय पारी खेलते हुए चोट के बाद शानदार तरीके से वापसी की। भारतीय सीनियर टीम में वापसी की कोशिश में जुटे 20 साल के शॉ ने इस बेहतरीन पारी के दौरान 22 चौके और दो छक्के जमाए। भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 372 रन का स्कोर बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड एकादश की टीम सलामी बल्लेबाज जैक बॉयल की 130 रन की शतकीय पारी के बावजूद निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट पर 360 रन बनाकर मुकाबला 12 रन से हार गई।

शॉ की पारी से निश्चित रूप से चयनकर्ता खुश होंगे, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन करना है। पहला टेस्ट 21 फरवरी से हैमिल्टन के बेसिन रिजर्व में शुरू होगा और दूसरा मैच 29 फरवरी से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। आठ महीने के डोपिंग प्रतिबंध से वापसी करने के बाद शॉ शानदार फॉर्म में थे, लेकिन मुंबई के कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के शुरुआती दिन उनके कंधे में चोट लग गई, जिससे वह न्यूजीलैंड में भारत-ए के पहले अभ्यास मैच में नहीं खेल पाए।

चोट से उबरने के बाद शॉ ने इस शानदार पारी से अपने इरादे जाहिर कर दिए। शॉ ने मयंक अग्रवाल (32) के साथ पहले विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को हेजलडाइन ने मयंक को आउट करके तोड़ा। कप्तान शुभमन गिल (24), सूर्यकुमार यादव (26) और इशान किशन (14) के साथ शॉ ने स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा। शॉ के 35वें ओवर में आउट होने के बाद ऑलराउंडर विजय शंकर ने 41 गेंद में 58 रन की पारी खेली।

अभ्यास मैच

- शॉ ने 100 गेंदों पर बनाए आक्रामक 150 रन
- न्यूजीलैंड एकादश को भारत-ए ने 12 रनों से हराया

रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे मनजोत कालरा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के नायक रहे मनजोत कालरा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के नए लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को अंतरिम आदेश में रणजी ट्रॉफी में खेलने की अनुमति दी।

कालरा पर उम्र की हेराफेरी संबंधित आरोप लगे थे और इस कारण उन पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से एक सत्र का प्रतिबंध लगा था, लेकिन डीडीसीए लोकपाल ने इस आदेश को बदल दिया। दिल्ली के पूर्व कप्तान कीर्ति आजाद के गुट ने कालरा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी और अंडर-23 टूर्नामेंट में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। डीडीसीए के पूर्व लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बदर दुरेज अहमद ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कालरा को निलंबित करने का आदेश दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने आदेश दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुराने आदेश को बदला जाता है जिससे कालरा को अगले आदेश तक रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सभी मैचों में खेलने की अनुमति दी जाएगी।

स्मिथ, वार्नर के रहते जीत मिलना संतोषजनक : कोहली

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली को बहुत संतोष है कि उनकी टीम ने वनडे अंतरराष्ट्रीय में ऐसी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशाने जैसे खिलाड़ी हैं।

कोहली ने मैच के बाद कहा, 'यह ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली बार से बेहतर है। इसमें स्टीव, डेविड और मार्नस हैं। इसकी गेंदबाजी शानदार है। हम पिछली सीरीज में आखिरी तीन मैच हार गए थे, लेकिन यहां पहला मैच हारने के बाद बाकी दो मैच जीतना अधिक संतोषजनक है। हम यहां से आगे ही बढ़ना चाहते हैं। पिछले साल घरेलू सीरीज हारने के बाद यहां इस तरह वापसी करना शानदार है।' कप्तान को यकीन था कि उनके जैसी अनुभवी टीम चोटिल शिखर धवन की गैरमौजूदगी में भी लक्ष्य का पीछा कर लेगी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास अनुभव की कमी नहीं है। शिखर की कमी खली। हमें अच्छी शुरुआत मिली। केएल राहुल के आउट होने के समय हालात कठिन थे, लेकिन तभी अनुभव काम आया।'

हम कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम से नहीं खेले : शास्त्री

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने वनडे सीरीज जीतने के बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया पर भारत की टेस्ट सीरीज में जीत की सराहना नहीं करने वाले आलोचकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब कोई नहीं कह सकता कि हम कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम से खेले। शास्त्री ने कहा, 'इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। कोई नहीं कह सकता कि हम कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम से हारे। मुंबई में हारने के बाद लगातार दो मैच जीतना और इतनी यात्रा के बीच, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मैचों में टॉस जीता।' ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट सीरीज में जीत के बाद बीसीसीआइ के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि यह मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं थी। इस बार जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत है।

शानदार बुंडिशलीगा में डोर्टमंड ने अगसबर्ग को 5-3 से हराया, स्थानापन्न हालैंड ने 20 मिनट में पूरी की हैट्रिक

डोर्टमंड के लिए पदार्पण मैच में हालैंड ने लगाई हैट्रिक

बर्लिन, एएफपी: नॉर्वे के उभरते हुए स्टार इर्लिंग ब्राउट हालैंड ने स्थानापन्न के तौर पर उतरते हुए जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में अपने क्लब बोरुसिया डोर्टमंड के लिए महज 20 मिनट के अंदर शानदार हैट्रिक लगाई। पदार्पण मैच में हालैंड (59वें, 70वें व 79वें मिनट) की इस हैट्रिक के दम पर डोर्टमंड ने अगसबर्ग को 5-3 से करारी शिकस्त दी।

पिछले महीने जर्मन लीग क्लब से जुड़े 19 वर्षीय हालैंड जब इस मुकाबले के 56वें मिनट में स्थानापन्न के तौर पर उतरे तो उनकी टीम 1-3 से पिछड़ रही थी। हालांकि, उन्होंने अपने उतरने के 183 सेकेंड के अंदर ही डोर्टमंड के लिए अपना पहला गोल दागा और जल्दी-जल्दी दो और गोल करके मौजूदा सत्र में अपनी छठी हैट्रिक पूरी की। हालैंड की हैट्रिक के अलावा डोर्टमंड के लिए जूलियन ब्रांट (49वें मिनट) और जेडन सांतो (61वें मिनट) ने भी गोल किए। वहीं, अगसबर्ग के लिए फ्लोरियन नीदरलेचनर (35वें व 55वें मिनट) ने दो और मार्को रिचर (46वें मिनट) ने एक गोल किया। हालांकि, डोर्टमंड के मैनेजर ल्यूसेन फावरे ने कहा कि हालैंड इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से फिट नहीं थे। ल्यूसेन ने कहा कि हालैंड ने पूरे दिसंबर में अभ्यास नहीं किया। उसे चोट लगी थी। वह इस मैच के लिए पूरे 90 मिनट खेलने के लिए फिट नहीं था। वहीं, हालैंड ने कहा कि मैं एक बेहतरीन क्लब में बेहद अच्छे साथी खिलाड़ियों और अच्छे लोगों के बीच हूं। मैं यहां गोल करने आया हूं और यह मेरे लिए यहां एक शानदार पदार्पण रहा।

जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में हैट्रिक लगाने के बाद खुशी जाहिर करते बोरुसिया डोर्टमंड के खिलाड़ी इर्लिंग ब्राउट हालैंड ● रायटर

फुटबॉल डायरी

ईबर ने एटलेटिको को हराया

मैड्रिड, एएफपी: स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में ईबर ने शनिवार को एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया। इस्टेबान बर्गोस ने खेल के 10वें मिनट में गोल करके ईबर को शुरुआती बढ़त दिलाई और फिर 90वें मिनट में इडू एक्सपोसिटो ने गोल करके ईबर की जीत सुनिश्चित कर दी। इस हार ने एक बार फिर एटलेटिको के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं।

फियोरेंटीना के खिलाफ घरेलू मैदान पर नापोली की हार पर भड़के मैनेजर गातुसो

मिलान, एएफपी: इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में शनिवार को नापोली को अपने घरेलू मुकाबले में फियोरेंटीना के हाथों 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार से नापोली के मैनेजर गेनेरो गातुसो नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रशंसकों और शहर से माफी मांगनी चाहिए। यह एक बेहद शर्मनाक प्रदर्शन है। इस मैच में हम देखने लायक नहीं थे। एक टीम के तौर पर हमारी आत्म मर गई है। उधर, सिरो इमोबिल की हैट्रिक के दम पर लाजियो ने सांपडोरिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। जीत के साथ लाजियो ने खिताबी दौड़ में खुद को बनाए रखा।

न्यूकैसल से हारा चेल्सी: इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शनिवार को चेल्सी को न्यूकैसल युनाइटेड के हाथों से 0-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद चेल्सी के मैनेजर फ्रैंक लैंपार्ड ने स्वीकार किया कि वह एक नए स्ट्राइकर के साथ करार करना चाहते हैं। मुकाबला गोलरहित ड्रॉ होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन इसाक हेडन ने इंजुरी टाइम समाप्त होने के 20 सेकेंड पहले हेडर के जरिये गोल करके न्यूकैसल को रोचक जीत दिला दी। इस हार ने चेल्सी के प्रशंसकों को निराश कर दिया।

हरियाणा की पारी 176 रन पर सिमटी

नई दिल्ली, जेएनएन : शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद हरियाणा की टीम रोहित शर्मा और सुमित कुमार के अर्धशतकों से सेना के खिलाफ ग्रुप-सी मुकाबले के शुरुआती दिन पहली पारी में 176 रन बनाने में सफल रही। लेकिन, हरियाणा ने गेंदबाजों के दम पर वापसी करते हुए स्टंप तक सेना के 63 रन तक छह विकेट झटक लिए थे, जिसके लिए केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। विकास हाथवाला 13 और अर्जुन शर्मा एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मेहमान टीम की ओर से रोहित ने 87 गेंद में छह चौके से 57 रन बनाए और सुमित ने चार चौके और दो छक्के की मदद से 51 गेंद में 57 रन की पारी खेली। सेना के देवेश पठानिया ने 65 रन देकर पांच विकेट अपनी झोली में डाले, जबकि सच्चिदानंद पांडे और पूनम पूनिया को दो-दो विकेट मिले।

अक्शदीप ने उत्तर प्रदेश को संभाला: अक्शदीप नाथ (115) की नाबाद शतकीय पारी और रिंकू सिंह (71) के साथ से पांचवें विकेट के लिए 137 रन की अटूट साझेदारी के बूते उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-बी मुकाबले के शुरुआती दिन मुंबई के खिलाफ पहली पारी में चार विकेट पर 281 रन बना लिए। उत्तर प्रदेश ने 48 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। अक्शदीप और मुहम्मद सैफ (42) ने चौथे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।

गांव की माटी से निकलेगा सोना

दिलशाद सैफी ● मुजफ्फरनगर

बहादरपुर और खेड़ी विरान बनेंगे आदर्श मॉडल खेल गांव, खेल भावना जगाना और प्रतिभाओं को मंच देना है मकसद

शहर से करीब 12 किलोमीटर बसे बहादरपुर की आबादी 5500 व खेड़ी विरान की 3500 है। यहां के युवाओं में शिक्षा की ललक तो है, लेकिन अधिकांश लोगों की आजीविका खेती है। मेरी कॉम, साइना नेहवाल, दुति चंद और पीटी ऊषा कौन हैं और किस खेल से जुड़ी हैं, इन सब चेहरों और इनके खेल से गांव वाले अनजान हैं। गिनती के युवा खेलों में हाथ आजमा रहे हैं। प्रतिभाएं हर गली-घर में छिपी हैं। गांवों की गलियों और माटी से सोना निकालने की तैयारी है, ताकि यहां से निकले खिलाड़ी विश्व पटल पर छाप छोड़ सकें।

गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आइएमटी), एनजीओ स्पोर्ट्स ए-वे ऑफ लाइफ और श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज ने संयुक्त रूप से गांवों में खेलों को जिंदा करने का बीड़ा उठाया है। इसी तहत दोनों गांवों का मॉडल खेल के लिए चुने गए हैं। इसका मकसद लोगों में खेल भावना जगाने और प्रतिभाओं को नया मंच देना है। लोगों में खेल का ज्ञान बढ़ेगा, तभी खिलाड़ियों की पौध तैयार हो सकेगी।

गांव में खिलाड़ियों की पौध होगी तैयार: गांवों को खेल मॉडल बनाने के पीछे यहां एथलीटों की पौध तैयार करना है। पहले प्रचार-प्रसार होगा। इसके बाद खेलों की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। गांवों की आबादी मिश्रित है, ऐसे में यहां खेल की अपार संभावनाएं हैं। क्रिकेट के दीवाने अधिक हैं, मगर अन्य खेलों में रुचि कम है। ऐसे में खेलों के लिए ग्रामीणों को सामूहिक रूप से जागृत किया जाएगा।

कबड्डी खिलाड़ी आयुषवीर ● परिजन

मॉडल खेल गांव चयनित होने से उत्सुकता है। साथ ही गांवों के बच्चों को भी खेल के पटल पर नया मंच मिलेगा, जिसके दम पर वह आगे बढ़ सकेंगे। गांव में खेल मैदान के लिए जमीन चिन्हित की गई है। जल्द यहां काम शुरू होगा।

राधेश्याम, ग्राम प्रधान, बहादरपुर

कबड्डी और वॉलीबाल में चमक रहे युवा

गांव बहादरपुर निवासी धर्मेंद्र चहल का बेटा शशांक बचपन से ही वॉलीबाल का शौकीन है। गांव की माटी में खेल निखारकर अब वह प्रदेश स्तर पर प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। 10वीं कक्षा के छात्र शशांक पहले ग्रामीण स्तर और फिर जिले स्तर पर प्रतिभा दिखाने के बाद राज्य स्तर पर पहुंचे हैं। वह बताते हैं कि वर्ष 2019 में वह राज्य स्तर की प्रतियोगिता अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नेपाल आदि में प्रतिभाग कर चुके हैं। उनका लक्ष्य राष्ट्रीय टीम में जगह बनाकर देश का नाम रोशन करना है। वह कहते हैं कि गांव में कोई खेल अकादमी नहीं है। गांव में अकादमी खोलकर युवाओं को जागरूक करने के साथ प्रशिक्षित किया जाए। इसी गांव के आयुषवीर सिंह कबड्डी में हाथ आजमा रहे हैं। वह जूनियर अंडर-14 वर्ग आयु में द्वितीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। वह हरिद्वार में कबड्डी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं।

मुझे लगता है कि टेस्ट प्रारूप में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसे पांच दिवसीय ही रहने दिया जाए।
– ब्रेट ली, पूर्व तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया

आनंद ने कार्लसन को ड्रॉ पर रोका

विज्क आन जी, प्रेट्र : विश्वनाथन आनंद ने टाटा स्टील मास्टर्स के सातवें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से ड्रॉ खेला। सफेद मोहरों से खेलते हुए आनंद ने कार्लसन की गलतियों का पूरा फायदा उठाया। टूर्नामेंट के छह दौर बाकी हैं, जबकि आनंद, कार्लसन और तीन अन्य संयुक्त पांचवें स्थान पर हैं। 16 वर्षीय अलीरजा फिरोजा ने अमेरिका के जेफरी शियोंग को हराकर सिंगल बढ़त बना ली, जिनके सात में से पांच अंक हैं।

न्यूज गैलरी

युवाओं के प्रदर्शन पर नजर

चेन्नई : विश्व चैंपियन पीवी सिंधू सोमवार से यहां शुरू हो रहे प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) में अपनी टीम हैदराबाद हंटर्स के लिए जब कोर्ट में उतरेंगी तो उनके सामने कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी और चेन्नई सुपरस्टार्ज की गायत्री गोपीचंद की चुनौती होगी। पीबीएल के पांचवें सत्र में छह करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के लिए अवध वॉरियर्स, बेंगलुरु रैप्टर्स, मुंबई रॉकेट्स, हैदराबाद हंटर्स, चेन्नई सुपरस्टार्ज, नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स और पुणे सेवेन एसेज की टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगे। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता के लिए हैदराबाद हंटर्स के साथ यह लगातार दूसरा साल होगा। (प्रेट्र)

महाराष्ट्र शीर्ष पर

गुवाहाटी : असम की शिवांगी शर्मा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रविवार को तैराकी में चौथा स्वर्ण जीता, जबकि महाराष्ट्र ने ऑलराउंड प्रदर्शन करके शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। शिवांगी ने तरणताल में चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने महिलाओं के अंडर-21 वर्ग में सौ मीटर फ्री स्टाइल का पीला तमगा 59 .26 सेकेंड में जीता। महाराष्ट्र ने 60 स्वर्ण समेत 193 पदक अपने नाम कर लिए हैं। महाराष्ट्र के मिहिर आंब्रे, रूद्रानीश मिश्रा और आरोन फर्नांडिस ने चार गुणा 100 मीटर रिले में टीम को कर्नाटक पर 0 .24 सेकेंड से जीत दिलाई। महाराष्ट्र की अंडर-17 खो खो टीमों, दो पहलवानों और तीन भारोत्तोलकों ने भी रविवार को स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा को उसके पहलवानों ने तीन स्वर्ण पदक दिलाए। दिल्ली 30 स्वर्ण लेकर तीसरे स्थान पर है। (प्रेट्र)

सुधा सिंह फिर चैंपियन

मुंबई : सेना के श्रीनू बुगथा और गत चैंपियन सुधा सिंह ने रविवार को यहां आयोजित मुंबई मैराथन के 17वें चरण में भारतीयों में क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अर्जुन पुरस्कार हासिल कर चुकीं सुधा सिंह ने 2 :45 :30 सेकेंड के समय से खिताब जीता। सुधा मैराथन में ओवरऑल 10वें स्थान पर रहीं। ज्योति गवाटे (2 :49 :14) दूसरे और श्यामली सिंह (2 :58 :44) तीसरे नंबर पर रहीं। सेना के श्रीनू बुगथा ने 2 :18 :44 सेकेंड के समय से पहला स्थान प्राप्त किया। वह ओवरऑल 13वें स्थान पर रहे। शेर सिंह 2 :24 :00 सेकेंड के समय से दूसरे और सेना के दुर्गा बहादुर बुद्धा तीसरे स्थान पर रहे। (प्रेट्र)

नोवाक व सेरेना खिताब के प्रबल दावेदार

ऑस्ट्रेलियन ओपन ▶ आज से शुरू हो रहा है साल का पहला ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट

अनुभवी खिलाड़ियों को मिलेगी युवा खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर

मेलबर्न, एएफपी : सर्बिया के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स सोमवार से यहां शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में युवा पीढ़ी का इंतजार बढ़ाकर खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगे।

हाल में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग का धुआं मेलबर्न में अब लगभग खत्म हो गया है जिसको लेकर खिलाड़ियों को काफी परेशानी थी। जोकोविक और रिकॉर्ड 24वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने की कोशिश में जुटी सेरेना सट्टेबाजों के लिए प्रबल दावेदार होंगी। वहीं शीर्ष वरीय स्पेन के 33 वर्षीय राफेल नडाल तीसरे दशक में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बनने का जश्न मना रहे हैं, जबकि 38 वर्षीय स्विस स्टार रोजर फेडरर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। फेडरर अपना 21वां ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम करने की कोशिश में उतरेंगे। पहले दौर में सोमवार को जोकोविक और फेडरर अपनी अपनी दावेदारी पेश करने उतरेंगे, जबकि नडाल को मंगलवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

ऑस्ट्रेलियन ओपन की पूर्व संध्या पर मेलबर्न में अभ्यास सत्र के दौरान सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। रायटर

10 साल से बिग थ्री का जलवा : साल 2020 की शुरुआत 2010 से अलग नहीं है जब फेडरर और नडाल ने चार ग्रैंडस्लैम खिताब साझा किए थे, जबकि अमेरिकी स्टार सेरेना ने मेलबर्न और विंबलडन में ट्रॉफी हासिल की थी। 10 साल बाद पुरुष वर्ग में 'बिग थ्री' जिन्होंने 2004 के बाद से दो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब को छोड़कर सभी ट्रॉफी जीती हैं और ये तीनों रैंकिंग में शीर्ष तीन स्थान पर काबिज हैं। वहीं सेरेना सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड से महज एक कदम दूर हैं। 2003 में जब फेडरर ने अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था तब से पुरुष खिलाड़ियों का वर्चस्व बरकरार है। तब से केवल पांच मेजर फाइनल ऐसे रहे हैं जिसमें स्विट्जरलैंड का यह खिलाड़ी, नडाल या जोकोविक नहीं खेले हैं। वहीं सेरेना के 2017 में मेलबर्न में 23वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के बाद से नौ महिलाओं ने मेजर खिताब अपने नाम किए हैं।

इनका टाइम आएगा : पिछले साल जहां जोकोविक और नडाल ने खिताब जीते तो वहीं डोमिनिक थिएम, डेनिल मेदवेदेव और फैबियो फोगनिनी ने अपनी पहली मास्टर्स ट्रॉफी हासिल की, जबकि 21 वर्षीय स्टीफानोस सितसिपास पिछले 18 वर्षों में एटीपी फाइनल्स चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। जोकोविक ने अगली पीढ़ी के मेजर खिताब जीतने के बारे में कहा कि वे बहुत करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि वे काफी दूर हैं जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में था। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से खिताब के भूखे होंगे। वे चुनौती पेश करते हैं। वे बस जीत के इंतजार में हैं।

अनुभवी बनाम युवा : अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत सोमवार को पहले दौर में दिखेगी जब 39 वर्षीय वीनस विलियम्स का सामना 15 साल की उभरती हुई स्टार कोरी गॉफ से होगा। कोरी तब पैदा भी नहीं हुई थीं जब उनकी हमवतन वीनस ने 2000 में अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था। वहीं जापान की नाओमी ओसाका लगातार दूसरे ग्रैंडस्लैम में खिताब का बचाव करेंगी। दुनिया की नंबर एक एश्ले बार्टी पर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें टिकी होंगी जो 1978 के बाद से स्वदेश में पहली महिला विजेता बनना चाहेंगी।

एफआइएच लीग : भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को किया शूटआउट

▶ निर्धारित समय तक 3-3 से बराबर रहा था मुकाबला, दो मैचों में पांच अंक लेकर शीर्ष पर भारत

भुवनेश्वर, प्रेट्र : भारतीय हॉकी टीम ने एफआइएच प्रो लीग में शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया की तीसरे नंबर की टीम नीदरलैंड्स को दूसरे मैच में शूटआउट में 3-1 से हराया, जबकि नियमित समय तक स्कोर 3-3 से बराबर था। दुनिया की पांचवें नंबर की टीम भारत ने इससे पहले शनिवार को शुरुआती मैच में नीदरलैंड्स को 5-2 से मात दी थी। भारत अब दो मैचों में पांच अंक लेकर शीर्ष पर है, लेकिन नियमित समय तक स्कोर बराबर रहने के कारण नीदरलैंड्स को भी एक अंक मिल गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए नियमों के अनुसार हर टाई मैच का नतीजा निकलना जरूरी है। ड्रॉ रहने पर मैच शूटआउट में जाएगा। विजयी टीम को दो और हारने वाली टीम को एक अंक मिलेगा।

दूसरे मैच में मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम 1-3 से पीछे चल रही थी। चौथे और आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह (51वां) और रुपिंदर पाल सिंह (55वां) ने गोल करके टीम को बराबरी तक पहुंचाया। इससे पहले ललित उपाध्याय ने 25वें मिनट मे भारत के लिए पहला गोल किया था। नीदरलैंड्स के लिए मिंक वान डेर वीडेन (23वें), जेरोन हर्ट्सबर्ग (26वें) और ब्योर्न केलेरमैन (27वें) ने गोल किए। शूटआउट में विवेक सागर प्रसाद, आकाशदीप सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए, जबकि हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर चूक गए। डच टीम के लिए मिरको प्रूइसर ने गोल दागा, जबकि ग्लेन शरमैन, थियरे ब्रिंकमैन और जेरोन हर्ट्सबर्ग के निशाने चूके। भारत ने शनिवार के मैच वाली अपनी लय कायम रखते हुए शुरू से ही कई मौके बनाए, लेकिन नीदरलैंड्स ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके बढ़त बना ली। डेर वीडेन ने पेनाल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया। भारतीय टीम ने अगले ही मिनट वापसी की, जब ललित ने करीब से मैदानी गोल किया। न्यूजीलैंड ने 26वें मिनट में एक और गोल करके फिर बढ़त बना ली। हर्ट्सबर्ग के इस गोल के बाद ब्योर्न ने 27वें मिनट में डच टीम के लिए तीसरा गोल किया। दो गोल से पिछड़ने के बाद आखिरी क्वार्टर में भारत ने प्रयास तेज किया, जिसका फायदा भी मिला। पहले मनदीप ने 51वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर नाकाम रहने पर रिबाउंड पर गोल किया। इसके चार मिनट बाद भारत को मिला पेनाल्टी कॉर्नर रुपिंदर ने गोल में तब्दील किया। आखिरी सीटी बजने से दो मिनट पहले नीदरलैंड्स को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत ने उसे बचा लिया।

अब विश्व चैंपियन बेल्जियम आठ और नौ फरवरी को यहां खेलेगी, जबकि 22 और 23 फरवरी को मेजबान को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है।

बजरंग और रवि ने जीते स्वर्ण पदक

▶ रोम रैंकिंग सीरीज के टूर्नामेंट में पूनिया ने फाइनल में ओलिवर को कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया

रोम, प्रेट्र : भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पूनिया हालांकि अपने सर्वश्रेष्ठ के करीब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने और रवि कुमार दहिया ने यहां रोम रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक वर्ष में शानदार शुरुआत की।

बजरंग ने शनिवार रात 65 किग्रा के फाइनल में अमेरिका के जोर्डन माइकल ओलिवर के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 4-3 से जीत हासिल की। रवि अपने नियमित 57 किग्रा के बजाय 61 किग्रा वर्ग में भाग ले रहे हैं। उन्होंने फाइनल में कजाखिस्तान के नुरबोलाट अब्दुलीयेव पर 12-2 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

सोनीपत के 23 साल के इस पहलवान ने मोलदोवा के एलेक्सांद्रू चिरतोआका और कजाखिस्तान के नुरीस्लाम सानायेव पर शानदार जीत के बाद फाइनल दौर में प्रवेश किया था। भारत ने इस तरह टूर्नामेंट से सात पदक हासिल किए। विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने महिला स्पर्धा में अपने वजन वर्गों में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं, ग्रीको रोमन में गुरप्रीत सिंह (82 किग्रा) ने स्वर्ण, सुनील कुमार (97 किग्रा) ने रजत जबकि साजन भानवाल (77 किग्रा) ने कांस्य पदक हासिल किया था। गुरप्रीत ग्रीको रोमन में रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं।

बजरंग ने स्वीकार किया कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे। उन्होंने कहा, 'हां, मुकाबले करीबी थे, यह सत्र का पहला ही टूर्नामेंट था इसलिए मैं इतना फुर्तीला नहीं था। टूर्नामेंट में जाने से पहले मुझे लग रहा था कि मेरा प्रदर्शन थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाएगा। लेकिन, करीबी मुकाबले होना चिंता की बात नहीं है, यह अच्छा है। इससे मैं सतर्क रहता हूं।'

बजरंग को हालांकि पहले दौर में अमेरिका के जैन एलेन रदरफोर्ड के खिलाफ पसीना बहाना पड़ा था, लेकिन वह 5-4 से जीत हासिल करने में सफल रहे थे। क्वार्टर फाइनल में शीर्ष भारतीय पहलवान ने एक और अमेरिकी जोसफ क्रिस्टोफर मैक केना को 4-2 से और फिर सेमीफाइनल में यूक्रेन के वासिल शुपतार को 6-4 से शिकस्त दी थी। वहीं, सत्यव्रत कादियान (97 किग्रा) और सुमित मलिक (125 किग्रा) पदक दौड़ में पहुंचने में नाकाम रहे थे।

आदित्य के आगे दिल्ली का शीर्षक्रम डगमगाया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

रणजी ट्रॉफी डायरी

आदित्य ठाकरे के चार विकेट की मदद से विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप-ए मैच के पहले दिन रविवार को दिल्ली को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। इससे पहले इशांत शर्मा और सिमरजीत सिंह ने उम्दा गेंदबाजी करके विदर्भ को 179 रन पर आउट कर दिया था। दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही और 12 ओवर में उसने 41 रन के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए। ये चारों विकेट ठाकरे ने लिए, जिन्होंने कुणाल चंदेला (06), हितेन दलाल (14), ध्रुव शौरी (00) और जोंटी सिद्धू (08) को पवेलियन भेजा। इससे पहले विदर्भ के लिए अनुभवी वसीम जाफर (83) को छोड़कर कोई नहीं चल सका। जाफर ने 131 रन की अपनी पारी में 11 चौके लगाए। विदर्भ के छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके। दिल्ली के लिए इशांत ने 14 ओवर में 45 रन देकर तीन और सिमरजीत ने 16.5 ओवर में 39 रन देकर चार विकेट चटकाए।

भार्गव मेराई का पंजाब के खिलाफ शतक: भार्गव मेराई के 130 रन की मदद से गुजरात ने पंजाब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 277 रन बनाए। मेराई को छोड़कर हालांकि कोई बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सका। मेराई ने 220 गेंदों का सामना करके अपनी पारी में 17 चौके लगाए। वहीं, पीयूष चावला ने 66 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 42 रन की पारी खेली। पंजाब के लिए सिद्धार्थ कौल और बलतेज सिंह ने चार-चार विकेट लिए।

शुभम की शानदार गेंदबाजी : शुभम शर्मा के पांच विकेट की मदद से राजस्थान ने केरल को पहली पारी में 90 रन पर आउट कर दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर राजस्थान ने चार विकेट पर 173 रन बना लिए थे।

जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ओडिशा की टीम 161 रन पर सिमटी

कटक : ओडिशा की टीम अकीब नबी (5/39) की गेंदबाजी के सामने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में महज 161 रन पर सिमट गई। लेकिन, उसने अपने गेंदबाजों की मदद से स्टंप तक जम्मू-कश्मीर के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था जिसने तीन विकेट गंवाकर 38 रन बना लिए। जम्मू-कश्मीर की टीम 123 रन से पिछड़ रही है। ओडिशा के लिए कप्तान सुभ्रांशु सेनापति ने 42 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज अनुराग सांगरी ने 33 रन का योगदान दिया।

विविध

विशेष परियोजना तैयार, नागरी प्रचारिणी सभा का लौटेगा वैभव

▶ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार आर्ट के विशेष प्रोजेक्ट में काशी

▶ संस्कृति मंत्रालय पांडुलिपियों को करेगा संरक्षित, प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी

परतंत्र भारत में हिंदी को संरक्षित करने वाली नागरीप्रचारिणी सभा काशी का वैभव लौटने वाला है। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने पहल की है। प्रदेश सरकार इसमें भारतेंदु अकादमी खोलने की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसमें सहेजी दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करेगा। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार आर्ट की विशेष परियोजना के तहत संवारा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय में सचिव का ओहदा प्राप्त सीईओ डेवलपमेंट आफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेज राघवेंद्र सिंह को दिया गया है।

इसके लिए शनिवार को बनारस दौरे पर आए सीईओ राघवेंद्र सिंह भले ही नागरी प्रचारिणी सभा तक नहीं जा पाए, लेकिन सभा के अपर सचिव सभाजीत शुक्ला से फोन पर वार्ता कर जानकारी ली। उन्होंने वस्तु स्थिति जानने के लिहाज से जल्द ही निरीक्षण का भरोसा दिया। नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से स्थापित आर्य भाषा पुस्तकालय में हजारों पत्र-पत्रिकाओं की फाइलें, लगभग 50 हजार हस्तलेख व हिंदी के अनुपलब्ध ग्रंथों का विशाल संग्रह है। साथ ही सभा की ओर से प्रकाशित शब्दकोश व अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। हिंदी को सम्मान दिलाने और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तब नौवीं के छात्र रहे बाबू श्यामसुंदर दास, पं. रामनारायण मिश्र व शिवकुमार सिंह ने 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उस समय इसकी बैठकें सप्तसागर के सभास्थल घुड़साल में हुआ करती थीं।

कुछ ही समय में संस्था के स्वतंत्र भवन ने आकार लिया और पहले ही साल में महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जार्ज ग्रियर्सन, अंबिकादत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे विद्वान इससे जुड़ गए। सभा ने स्थापना के सात साल में ही हिंदी आंदोलन चलाया। इससे राजा-महाराजाओं समेत 60 हजार विशिष्ट जनों को जोड़ते हुए न्यायालयों व सरकारी दफ्तरों में देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रयोग की अनुमति का दबाव बनाया। पं. मदन मोहन मालवीय व बाबू श्यामसुंदर दास के नेतृत्व वाले आंदोलन को हिंदी का पहला सत्याग्रह माना गया। कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए।

मालगाड़ी की बोगी की सील तोड़कर ग्रामीणों ने लूटीं गेहूं की बोरियां

▶ बंगाल के रामपुरहाट से भागलपुर जा रही थी मालगाड़ी

▶ रामपुर से पहुंची आरपीएफ की टीम ने बरामद की 15 बोरियां

जागरण संवाददाता, शिकारीपाड़ा (दुमका)

बंगाल के रामपुरहाट से बिहार के भागलपुर जा रही मालगाड़ी इंजन में अचानक आई खराबी के कारण चायपानी गांव के समीप रुक गई। इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मालगाड़ी की बोगी की सील तोड़कर उसमें रखीं गेहूं की करीब 200 बोरियां लूट लीं। इधर, चालक की सूचना पर रामपुरहाट से पहुंची आरपीएफ की टीम ने पटरी के किनारे पड़ी गेहूं की 15 बोरियां बरामद कर ली हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ग्रामीणों ने कुल कितनी बोरियां लूट ली हैं। मालगाड़ी के भागलपुर पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। इधर, घटना के दो घंटे बाद दूसरे इंजन के सहारे गाड़ी को भागलपुर के लिए रवाना किया गया।

बताया जाता है कि रविवार सुबह करीब नौ बजे मालगाड़ी चायपानी के पास पहुंची तो चढ़ाई की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। चालक ने गाड़ी वहीं पर रोक दी। इसके बाद बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। एक बोगी में करीब 200 बोरियां रखी जाती हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने दूसरी बोगी की सील भी तोड़ दी, जिसे देख चालक ने गाड़ी को वापस दस किलोमीटर पीछे हरिनसिंघा स्टेशन पहुंचा दिया। इस बीच चालक ने शिकारीपाड़ा के स्टेशन मास्टर सुनील मरांडी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद रामपुरहाट से आरपीएफ के इंस्पेक्टर अनूप गिरि और शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। करीब ग्यारह बजे रामपुरहाट से एक अन्य इंजन पहुंचने के बाद मालगाड़ी भागलपुर के लिए रवाना हुई।

> गिनती के बाद ही पता चलेगा कि कुल कितनी बोरियों की लूट हुई है। एक बोगी में करीब दो सौ बोरियां होती हैं। गिनती पूरी होने के बाद शिकारीपाड़ाथाने में मामला दर्ज कराया जाएगा।
> – अनूप गिरी, आरपीएफ इंस्पेक्टर

पहले भी हो चुकी है इस तरह की लूट की घटना : पिछले साल चायपानी के पास ही मालगाड़ी की बोगी तोड़कर दो बार लूट हुई थी। पहली बार चावल तो दूसरी बार खाद की बोरियां लूट ली गई थीं।

दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के चायपानी के पास खुली मालगाड़ी की बोगी। ग्रामीणों ने एक पूरी बोगी खाली करने के बाद इस बोगी में रखी आधी बोरियां भी लूट लीं। जागरण

सेना के जवान को ड्रोन बेचने वाला गाजियाबाद से गिरफ्तार

▶ ड्रोन बेचते समय आरोपित रिषभ ने डीजीसीए के मानदंड नहीं किए थे पूरे

▶ पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियार और हेरोइन मंगवाने के मामले में अब तक की छठी गिरफ्तारी

नवीन राजपूत, अमृतसर

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियार और हेरोइन की खेप मंगवाने के मामले में घरिंडा थाने की पुलिस ने गाजियाबाद के रिषभ नाम के एक युवक को रविवार रात गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियार और हेरोइन मंगवाने के मामले में यह छठी गिरफ्तारी है। इससे पहले सेना के जवान राहुल चौहान समेत पांच को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आरोप है कि रिषभ ने कुछ दिन पहले सेना के नायक राहुल चौहान को ड्रोन बेचा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। पुलिस का आरोप है कि पकड़े गए आरोपित रिषभ ने ड्रोन बेचते समय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के मानदंड पूरे नहीं किए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपित को सोमवार की सुबह तक अमृतसर ले आएगी।

कुछ दिन पहले अमृतसर देहात पुलिस ने अंबाला कैंट निवासी सेना के जवान राहुल चौहान को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया था कि राहुल के भाई रोहित चौहान के बैंक खाते से ड्रोन खरीद का भुगतान किया गया था। इससे पहले पुलिस अमृतसर के धनोआ खुर्द गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह, जेल में बंद बलकार सिंह व दो अन्य आरोपितों को फताहपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर चुकी थी। जब पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो सारा मामला साफ हो गया। सेना के जवान राहुल ने पुलिस हिरासत में स्वीकार किया था कि उसने कुछ दिन पहले दो ड्रोन ऑनलाइन खरीदे थे। इन्हें वह पाकिस्तान से हेरोइन और हेरोइन तस्करी में इस्तेमाल करने वाला था। पाकिस्तान के तस्करों से हेरोइन और हथियार मंगवाने के लिए फताहपुर जेल में बंद बलकार सिंह संपर्क में था। पुलिस ने जेल में बंद बलकार सिंह और दो अन्य कैदियों से तीन मोबाइल भी बरामद किए थे। तीनों आरोपित हेरोइन तस्करी मामले में जेल में बंद हैं।

रिषभ पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर

रिषभ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर उस पर टिक गई है। पता लगाया जा रहा है कि रिषभ विगत में कुल कितने ड्रोन इस तरह बेच चुका है और यह ड्रोन अभी तक किन हाथों में चल रहे हैं। सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अमृतसर (देहात) के सीआइए स्टाफ में आरोपित रिषभ से पूछताछ के लिए पहुंचेंगे।

नशीली दवाओं की खेप पकड़ी, गिरोह के तीन तस्कर दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नशीली दवाओं (साइकोट्रॉपिक दवा) की तस्करी के मामले में दिल्ली की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट ने अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। यूनिट ने पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय गिरोह के तस्करों की गिरफ्तारी आगरा और लुधियाना से की है। इनके कब्जे से 7 लाख 24 हजार 840 गोलियां, 1400 इंजेक्शन और सीबीसीएस (कोडीन बेस्ड कफ सिरप) की 80 बोतलें बरामद की गई हैं। आरोपितों की पहचान लुधियाना के मॉडल टाउन निवासी मनोज कुमार, आगरा के श्याम नगर निवासी गौरव कुमार अग्रवाल और आगरा के शाहगंज निवासी मोहित के रूप में हुई है।

ये दवाएं फार्मा कंपनियों से डीलर और खुदरा विक्रेताओं को पहुंचाने के बजाय तस्करों को उपलब्ध कराई जाती थीं। आगरा और लुधियाना से इन दवाओं की आपूर्ति करने वालों को गिरफ्तार किया गया। दवाओं की सबसे पहली खेप दिल्ली में पकड़ी गईं, जो कूरियर के माध्यम से आगरा और फिर पंजाब भेजी जानी थी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोनल यूनिट के जोनल डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध व्यापार में शामिल कुछ लोगों को साइकोट्रॉपिक दवाएं कोरियर के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। इस पर दिल्ली में ट्रामाडोल की 50 हजार गोलियों वाले एक पार्सल को रोका गया। सत्यापन के बाद एक टीम ने लुधियाना में छापा मारा, जहां इस खेप को पहुंचना था। कूरियर भेजने वाला आगरा में था। आगरा में इस पार्सल के रिसीवर का नाम मनोज कुमार पता लगा जो लुधियाना का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि आगरा के रहने वाले गौरव कुमार अग्रवाल से ऐसे पार्सल प्राप्त करता है। आगरा में टीम ने गौरव को गिरफ्तार किया और फिर उसके गिरोह में शामिल आगरा के ही मोहित को भी दबोच लिया।

पूछताछ में मनोज ने बताया कि वह लुधियाना में केमिस्ट की दुकान चलाता है। साइकोट्रोपिक दवाओं में भारी मुनाफा होने के चलते वह पंजाब के विभिन्न हिस्सों में इनकी आपूर्ति करता है। पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह आगरा के दवा बाजार में थोक दवा डीलरों के लिए एक एजेंट का काम करता था।

इन दवाओं के सेवन से होता है हेरोइन जैसा नशा

जासं, नई दिल्ली : एम्स के एक प्रोफेसर के मुताबिक जब्त दवा शेड्यूल एच/एच-1/एक्स ड्रग्स की है। जिसे फार्मासिस्ट से खरीदने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) की जरूरत होती है। जब्त दवाएं नार्को ड्रग्स हैं, जिन्हें तनाव, शामक, दर्द निवारक के लिए उपयोग की जाती हैं। इन दवाओं को नियमित खाने की आदत ही नशे की आदत बनती है। जब्त दवाओं में पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल और नशामुक्ति केंद्रों दोनों में उपयोग होता है। मस्तिष्क पर इन दवाओं का प्रभाव हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों के समान है। उन्होंने बताया कि ट्रामाडोल का उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के उपचार में किया जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, ट्रामाडोल का उपयोग कुछ हफ्तों से अधिक समय तक करने पर इसकी आदत हो जाती है।

संपत्ति विवाद में डॉक्टर को कुत्ते से कटवाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विवेक विहार इलाके में संपत्ति विवाद में पड़ोसी ने एक महिला डॉक्टर को जर्मन शेफर्ड पालतू कुत्ते से कटवा दिया। कुत्ते के काटने से 53 वर्षीय डॉ. सुमन महाजन बुरी तरह जख्मी हो गईं। कुत्ते ने उनकी दोनों टांगों के साथ ही कमर पर भी बुरी तरह काटा है। कुत्ते के काटने पर डॉक्टर ने शोर मचाया तो उनके परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपित कुत्ते को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस पीड़िता की शिकायत पर केस दर्जकर आरोपित कुलदीप रावल की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार डॉ. सुमन महाजन परिवार के साथ विवेक विहार के सी-ब्लॉक में रहती हैं। सुमन के मुताबिक पिछले काफी समय से उनके परिवार का कुलदीप से झगड़ा चल रहा था।

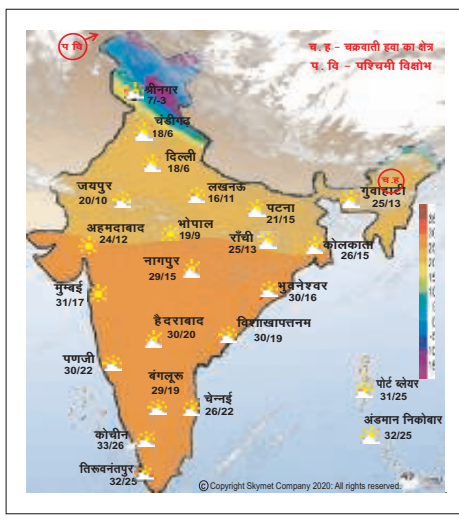

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी होगी। दिन के तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में ठंडी सुबह में मध्यम कोहरा व कुहासा रहेगा। आंशिक बादलों के साथ हल्की धूप खिली रहेगी। शुष्क मौसम के साथ दिन शीतल रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/16/आंबा	अहमदाबाद	30/10/आंबा
कोलकाता	25/13/आंबा	बड़ौदा	32/12/सा
चेन्नई	30/24/आंबा	नागपुर	30/16/आंबा
हैदराबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
सोमवार 20 जनवरी 2020
www.jagran.com

एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर का हुआ था उद्घाटन

आज ही के दिन 1957 में मुंबई के ट्रांबे में देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने किया था। यह एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। 9 साल बंद रहने के बाद 2018 में फिर शुरू किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण का दिन

आज का दिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण का दिन है। 1937 में फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस दिन शपथ ली थी। इसके बाद सभी राष्ट्रपतियों ने इसी दिन शपथ ली। अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख 20वें संशोधन के तहत किया गया।

देश के 'संकटमोचक' एनएसए अजीत डोभाल

आज ही के दिन 1945 में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री ली और 1968 में केरल कैडर से आइपीएस बने। 1972 में इंटेलीजेंस ब्यूरो में पहुंचे और 2005 में रिटायर हुए। मिजोरम और पंजाब में अलगाववाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया। 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। 2014 से देश के एनएसए की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

इधर-उधर की

वर्जीनिया में लाइटर ने शख्स को दिलाई लाखों की लॉटरी

वर्जीनिया, एजेंसी : कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर जाने का आपका मन नहीं होता लेकिन वहां पहुंचकर आप बेहद खुश होते हैं। ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जिसे उसकी पत्नी ने लाइटर लाने के लिए भेजा था। हालांकि जब वो शख्स लाइटर लाने गया तो पूरे परिवार के लिए लाखों की खुशियां लेकर लौटा। उसे लॉटरी में 5 लाख डॉलर (करीब साढ़े तीन करोड़) का खजाना मिल गया। हैरलैंड डोडसन ने बताया कि स्थानीय 7-इलेवन स्टोर में जाने का कारण पत्नी के लिए लाइटर खरीदना था, लेकिन जब वह स्टोर पर था तभी नजर वर्जीनिया लॉटरी के टिकट पर पड़ी। डोडसन ने चार टिकट खरीद जिनमें दो पत्नी के लिए और दो खुद के लिए थे। इनमें से ही एक टिकट को स्क्रैच किया तो उसकी पांच लाख डॉलर की लॉटरी लग चुकी थी। यह देखकर वह खुशी से फूला नहीं उठाया।

मलेरिया के परजीवी के भीतर आसान होगी जीन डिलीवरी

- वैज्ञानिकों ने विकसित की 'लाइस-फिल विद डीएनए-रिसील'
- इस पद्धति के जरिये उनके अनुवांशिक तंत्र के बारे में बढ़ाई जा सकती है समझ

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ताजा अध्ययन में मलेरिया के परजीवी प्लासमोडियम फैल्सीपैरम की कोशिकाओं के भीतर जीन डिलीवरी की उन्नत और किफायती पद्धति विकसित की है। लाइस-फिल विद डीएनए-रिसील नामक यह पद्धति प्लासमोडियम फैल्सीपैरम के जैविक एवं अनुवांशिक तंत्र के बारे में गहरी समझ विकसित करने में उपयोगी हो सकती है, जिससे मलेरिया नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

जीन्स की कार्यप्रणाली में बदलाव और उनके अध्ययन के लिए लक्षित कोशिकाओं में जीन डिलीवरी कराना एक आम पद्धति है। लेकिन, प्लास्मोडियम के अनुवांशिक अध्ययन में कई चुनौतियां हैं। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) में जब प्लास्मोडियम बढ़ता है, तो यह मलेरिया का कारण बनता है। ऐसे में, परजीवी को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं इसकी रक्षा करती हैं। यह स्थिति मलेरिया जीवविज्ञानी के लिए एक प्रमुख चुनौती होती है, क्योंकि

प्रतीकात्मक

प्लास्मोडियम के जीन्स तक पहुंचने के लिए चार कोशिका झिल्लियों को पार करना होता है।

जीन डिलीवरी के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक उपयोग की जाती है। इस तकनीक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके कोशिका झिल्ली की परतों में अस्थायी छिद्र बनाए जाते हैं, ताकि डीएनए जैसे वांछित रसायन कोशिका के भीतर प्रवेश कराए जा सकें। यह एक महंगी तकनीक है और इसमें काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। हालांकि, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम की कोशिकाओं में जीन डिलीवरी की यह नई विधि परंपरागत तकनीक के मुकाबले किफायती है, जिसे हैदराबाद स्थित कोशकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है।

हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के संपर्क में आने से (सॉल्यूशन जिसमें लवण की मात्रा कोशिका के भीतर से कम हो) लाल रक्त कोशिकाओं में छेद हो जाता है, जिससे वांछित डीएनए कोशिका में प्रवेश कराया जा जाता है। सॉल्यूशन में लवण की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो विच्छेदित लाल रक्त कोशिका दोबारा सील हो जाती है। वैज्ञानिकों ने वांछित डीएनए युक्त पुनः सील हुई इन रक्त कोशिकाओं को प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम से संक्रमित कराया है। ऐसा करने पर देखा गया कि प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम आरबीसी के अंदर जाकर आरबीसी से डीएनए प्राप्त करता है और अंततः डीएनए अपने जीन के साथ परजीवी के नाभिक में समाप्त हो जाता है।

10 गुना कम डीएनए की होती है जरूरत : साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. पूरन सिंह सिजवाली ने बताया कि प्लासमोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया के गंभीर रूपों के लिए जिम्मेदार है। प्लासमोडियम फैल्सीपैरम को नियंत्रित करने के लिए ऐसे जीन्स पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिन्हें लक्ष्य बनाकर उसी के अनुरूप प्रभावी दवाएं विकसित की जा सकें। परंपरागत इलेक्ट्रोपोरेशन विधि की अपेक्षा जीन डिलीवरी की इस पद्धति में दस गुना कम डीएनए की जरूरत पड़ती है।

किफायती है नई पद्धति : नई पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि इसके लिए महंगी इलेक्ट्रोपोरेशन मशीन और अन्य ट्रेडमार्क सामानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मलेरिया के प्रकोप से ग्रस्त दूरदराज के अधिकतर इलाकों में पर्याप्त संसाधनों से युक्त प्रयोगशालाएं कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसे इलाकों में, नई पद्धति से कम संसाधनों की मदद से प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम के अनुवांशिक अध्ययन किया जा सकता है और इसके बारे में हम अपनी समझ को और विकसित कर सकते हैं।

देश के पूर्वी और मध्य भाग में देखे जाते हैं ज्यादा मामले

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की एक बड़ी आबादी पर मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। भारत में मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। मलेरिया के अधिकांश मामले देश के पूर्वी और मध्य भाग में देखे गए हैं। इनमें मुख्य रूप से वन, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। मलेरिया से ग्रस्त राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्य जैसे- त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम शामिल हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि लाइस-फिल विद डीएनए-रिसील नामक यह पद्धति की मदद से हम मलेरिया के परजीवी को विकसित होने से रोक सकते हैं और वैश्विक स्तर पर कई देशों के लिए महामारी बन चुकी इस बीमारी का सफाया कर सकते हैं। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में डॉ. पूरन सिंह के अलावा गोकुलप्रिया गोविंदराजू, जेबा रिजवी और दीपक कुमार शामिल थे।

एंड्रॉयड पर 500 करोड़ बार डाउनलोड किया गया वाट्सएप

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप वाट्सएप को एंड्रॉयड फोन में अब तक 500 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह दूसरा गैर-गूगल एप बन चुका है। एंड्रॉयडपुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा सिर्फ प्लेस्टोर से डाउनलोड किए गए एप का नहीं है, बल्कि इसमें सैमसंग और हुआवे जैसे सेलफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए एप की संख्या भी शामिल है।

स्टेटिस्टा के अनुसार, वाट्सएप दुनियाभर में सबसे अधिक लोकप्रिय मोबाइल मैसेंजर एप है। मासिक तौर पर इसके 1.6 अरब सक्रिय यूजर्स हैं। इसके बाद 2019 में 1.3 अरब की संख्या के साथ फेसबुक मैसेंजर के यूजर्स और 1.1 अरब की संख्या के साथ वीचैट के यूजर्स हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद दुनियाभर में यह तीसरा सर्वाधिक लोकप्रिय एप है। गूगल प्ले स्टोर के अनुसार, दक्षिणी कोरिया में 2019 में इस एप की डाउनलोडिंग में 56 फीसदी इजाफा हुआ था। पांच साल में पहली बार पिछले साल की अंतिम तिमाही में फेसबुक टॉप एप्स में पहले नंबर पर था।

किंग एडवर्ड-8 की तस्वीर वाला सिक्का 13 लाख डॉलर में बिका

ब्रिटेन के किंग एडवर्ड-8 की तस्वीर वाला सोने का सिक्का। एपी

लंदन, एपी : ब्रिटेन के किंग एडवर्ड-8 के सत्ता छोड़ने से पहले की तस्वीर वाला एक सोने का सिक्का 10 लाख पाउंड या 13 लाख डॉलर में बिका है। इसे दुनिया के बेहद दुर्लभ सिक्कों में से एक माना जाता है। किसी ब्रिटिश सिक्के की बिक्री का यह एक नया रिकॉर्ड है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चाचा किंग एडवर्ड-8 ने एक अमेरिकी विधवा वेलिस सिंपसन से विवाह करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी थी।

राजगद्दी छोड़ने से पहले की उनकी तस्वीर वाले इस सिक्के को खरीदने वाला एक निजी संग्रहकर्ता है जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है। उसने एक ब्रिटिश समाचार समूह को बताया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। शाही टकसाल में संग्रह सेवाओं की प्रमुख रेबेका मॉर्गन ने कहा कि इस सिक्के की रिकॉर्ड कीमत आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। यह सिक्का बेहद दुर्लभ सिक्कों में से एक है।।

स्पाइडर मैन की तरह चढ़ाई करेंगे रोबोट

तकनीक ▸ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने विकसित की जीरो-प्रेशर डिफरेंस सक्शन डिवाइस

गगनचुंबी इमारतों में आगजनी से होने वाले नुकसान को कम करने में मिलेगी मदद

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक खास तरह की डिवाइस बनाई है, जिसकी मदद से स्पाइडर मैन की तरह चढ़ाई करने वाले रोबोट बनाए जा सकते हैं और इन रोबोटों की हाथों से चीजों को पकड़ने की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खुरदुरी सतह पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के रोबोट की मदद से गगनचुंबी इमारतों में सफाई के साथ-साथ आगजनी के खतरे को भी कम किया जा सकता है।

अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (एआइपी) के वैज्ञानिकों के अनुसार, पारंपरिक सक्शन (खिंचाव) तरीकों से खुरदुरी सतह पर खिंचाव बल के प्रयोग करने में दिक्कतें आती हैं। यह हवा की लीकेज की वजह से होता है, जिससे सक्शन ठीक से काम नहीं करता है। यह शोध फिजिक्स ऑफ फ्लूड्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें नई डिवाइस के बारे में विस्तार से बताया गया है।

प्रतीकात्मक

जानमाल का जोखिम होगा कम

शोधकर्ताओं ने कहा, 'सक्शन यूनिट से लैस रोबोट ऊंची इमारतों में होने वाली आगजनी के नुकसान को कम कर सकते हैं। क्योंकि गगनचुंबी इमारतों में आग लगने पर दमकल कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार वे समय रहते वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में काफी जन-धन की हानि होने का जोखिम रहता है। लेकिन सक्शन रोबोट इस खतरे को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।'

शोधकर्ताओं ने कहा कि जीरो-प्रेशर डिफरेंस (जेडपीडी) एक ऐसी पद्धति है, जो वैक्यूम लिकेज नहीं होने देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, नई तकनीक में सतह और डिवाइस के सक्शन कप के बीच हाईस्पीड रोटेटिंग वाटर रिंग का प्रयोग होता है, जो खुरदुरी सतह पर पकड़ मजबूत करने वाला बल उत्पन्न करता है। यह बल वैक्यूम की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है।

एआइपी के शोधकर्ता और अध्ययन के सह-लेखक जिन ली ने बताया, 'इस डिजाइन का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि दीवार पर चढ़ाई करने वाला रोबोट सबसे अधिक उपयोगी होगा।' ली ने बताया, 'दीवार पर चढ़ाई करने वाले अन्य रोबोट की तुलना में जेडपीडी से लैस सक्शन वाले रोबोट की कार्यक्षमता में आश्चर्यजनक सुधार देखे गए।' वैज्ञानिकों के अनुसार, जेडपीडी सक्शन यूनिट पारंपरिक रूप से प्रयोग होने वाले सक्शन डिवाइस से हल्की होती है। इसमें पर्याप्त ऊर्जा भी होती है।

ऊर्जा की कम होती है खपत : शोधकर्ताओं ने अध्ययन में लिखा है, 'हमारे प्रयोग से पता चलता है कि 0.8 किलोग्राम की जेडपीडी सक्शन यूनिट खुरदुरी सतह पर 245 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में 400 वाट से कम की ऊर्जा खपत होती है।' इसके विपरीत, इसी आकार की पारंपरिक सक्शन यूनिट इतना ही बल उत्पन्न करने के लिए कई किलोवाट और दर्जनों किलोग्राम के वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ती है।

पानी की खपत कम करना लक्ष्य : वैज्ञानिकों ने जेडपीडी यूनिट को तीन अलग-अलग आकार वाले सक्शन के साथ प्रयोग किया। इसमें एक चीजों को पकड़ने के लिए रोबोटिक हाथ पर प्रयोग किया। दूसरा, दीवार चढ़ने वाले रोबोट पर किया। ली ने बताया, 'इस शोध में अगला कदम पानी की खपत को कम करना है। अगर पानी की खपत कम की जा सके, तो सक्शन यूनिट काफी लंबे समय तक काम कर सकता है।'

वैज्ञानिकों ने खोजा बिच्छू का सबसे पुराना जीवाश्म

- साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ अमेरिकी शोधकर्ताओं का अध्ययन

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे पुराने बिच्छू के जीवाश्म का खोज निकाला है। माना जाता है कि आज से लगभग 43.7 करोड़ साल पहले इन बिच्छुओं का अस्तित्व मौजूद था। शोधकर्ताओं मानना है कि इस अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता लग सकता है कि पृथ्वी के निर्माण के बाद जीव-जंतुओं ने खुद को कैसे जमीन पर रहने के अनुकूल बनाया होगा।

पेरियोस्कॉर्पियो वेनेटर (पी. वेनेटर) नामक इस बिच्छू के बारे में साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यह बिच्छू अब तक का सबसे पुराना बिच्छू है, जो अपने समुद्री निवास स्थानों को छोड़ने के साथ-साथ जमीन पर भी उतरने में सक्षम था। अमेरिका की ओटेरबिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एंड्रयू वेंडरुफ ने कहा कि बिच्छू ऐसे जानवरों में शुमार है जो समुद्र से जमीन पर चले गए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके पास सीमित जीवाश्म रिकॉर्ड हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वे

प्रतीकात्मक

कब और कैसे स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हुए होंगे।

इस अध्ययन के लिए वेंडरुफ और उनके सहयोगियों ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में खोजी गई एक अज्ञात प्रजाति के बिच्छू के दो संरक्षित नमूनों का आकलन किया, ये नमूने 43.7 करोड़ साल पहले सिलुअरी काल के हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस पी. वेनेटर में वे सभी खूबियां मौजूद हैं जो एक समुद्री जीव में होती हैं। इसके अलावा इसके पास आधुनिक बिच्छुओं की तरह डंक मारने वाली एक पूंछ भी होती थी।

फोटो न्यूज

कबूतर के पंखों के सहारे उड़ता है 'पिजनबॉट'

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने कबूतर के 40 वास्तविक पंखों से तैयार विंग्स के साथ रेडियो कंट्रोल्ड रोबोट बनाया है। उड़ने वाले इस रोबोट को 'पिजनबॉट' नाम दिया गया है। यह कई मायनों में पक्षी जैसा है तो कुछ विमान की तरह भी, बल्कि यह दोनों का मिलाजुला रूप है। इस रोबोट में विमान का ढांचा और प्रोपलर भी है। यह अपना रास्ता खुद तय करने, दिशा बदलने और कलाबाजी में भी सक्षम है। फाइल /एएफपी

कम सक्रिय रहने वाले नवजात शिशुओं में बढ़ जाता है मोटापे का खतरा

शोध अनुसंधान

अगर आपके नवजात शिशु को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल पाता है तो संभल जाएं। हालिया शोध के मुताबिक, ऐसे बच्चों के शरीर में वसा जम जाती है और उनमें मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। शोध के दौरान 506 नवजातों की शारीरिक सक्रियता पर नजर रखी गई। इसके लिए तीन, छह, नौ और 12 महीने की उम्र पर चार-चार दिन तक एक डिवाइस की मदद से उनकी सक्रियता मापी गई। शोधकर्ताओं ने कहा, 'जो बच्चे जल्दी सरकना और घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं तथा जिन्हें दिनभर ज्यादा आजादी से चहलकदमी का मौका मिलता है, उनमें मोटापे का खतरा उतना ही कम होता जाता है।' वैज्ञानिकों ने कहा कि वर्तमान समय में शिशुओं का ज्यादा समय कार की सीट, ऊंची कुर्सी या स्ट्रॉलर आदि पर बैठे-बैठे बीत जाता है, जिसके चलते उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है। - आइएएनएस

कोशिकाओं के बीच जोड़ को निशाना बनाकर कैंसर का इलाज हो सकता है संभव

वैज्ञानिकों ने विभिन्न कोशिकाओं के बीच के जोड़ को लेकर नई जानकारी हासिल की है। ताजा शोध के मुताबिक कोशिका से कोशिका के बीच का जोड़ ही कोशिकाओं को अलग-अलग तरह के तनाव सहने की ताकत देता है। तनाव की स्थिति में कोशिकाओं के सुरक्षित बने रहने में इस जोड़ की अहम भूमिका होती है। हालांकि कैंसर कोशिकाएं इसी खूबी को आधार बनाकर अपना विस्तार करने लगती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कैंसर कोशिकाओं के बीच जोड़ की इस खूबी को कम किया जाए, तो दवाओं का असर बढ़ सकता है। इस दिशा में जीन रेगुलेटिंग प्रोटीन एचएसएफ2 की भूमिका अहम पाई गई है। दो कोशिकाओं के बीच के जोड़ का माध्यम बनने वाले जीन को सक्रिय करने में इस प्रोटीन की भूमिका रहती है। कैंसर कोशिकाओं में इस प्रोटीन को निशाना बनाते हुए नई दवा ईजाद की जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विधि अगर सभी स्तरों के परीक्षणों में सफल हो जाती है तो आगामी समय में कैंसर के मरीजों का उपचार आसन हो सकता है। - एएनआइ

स्क्रीन शॉट

मैंने टाइगर को डांस सिखाया है : श्रद्धा कपूर

सात सवाल

'एबीसीडी 2' के बाद अब वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की जोड़ी रेमो डिसूजा निर्देशित 'स्ट्रीट डांसर 3 डी' से वापसी कर रही है। 'एबीसीडी 2' में किया गया डांस का अभ्यास श्रद्धा को 'स्ट्रीट डांसर 3डी' की शूटिंग में भी काम आया। श्रद्धा के मुताबिक, इस बार फिल्म में डांस ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। उनसे बातचीत :

- **डांस के प्रति आपका कितना लगाव रहा है?**

- जब मैं छोटी थी, तब आईने के सामने डांस किया करती थी। जब प्रभुदेवा सर की गाना मुकाबला... आया था, तब मैं और भाई उस गाने के दीवाने हो गए थे। जब रेमो सर 'एबीसीडी 2' के लिए हीरोइन ढूंढ़ रहे थे, तब वरुण ने उन्हें बताया था कि मुझे डांस करना पसंद है। वरुण और मैं बचपन में बर्थडे पार्टीज पर एक-दूसरे से डांस मुकाबला किया करते थे। मैंने स्कूल में टाइगर को भी डांस सिखाया है। हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम होता था, जिसे मैं लीड कर रही थी। मैंने उन्हें एक पल का जीना... गाने पर डांस सिखाया था। अब देखिए टाइगर किस तरह का डांस करते हैं। अब मुझे टाइगर से डांस सीखना पड़ेगा।

- **प्रभुदेवा के साथ जब 'मुकावला' गाने पर डांस करने का मौका मिला तो वह पल कैसा था?**

- प्रभुदेवा सर डांस के लंबे शॉट एक ही टेक में दे रहे थे। उनको देखकर लगा कि हमें तो घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे मुकाबला... गाने में उनके साथ पांच सेकेंड मिले। रेमो सर ने मेरा शॉट ओके कर दिया था।

- **फिल्म भारत-पाक के प्रतियोगियों के बीच डांस युद्ध पर है। दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है...**

-सिनेमा की खासियत यही है कि यहां कोई सीमा नहीं है। जो कहना है, वह सिनेमा के जरिए दिखाया जा सकता है। मैं पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा रही हूं, जो लंदन में पली-बढ़ी है। उसे घमंड है कि वह सामने वाले से अच्छा डांस करती है।

- **बचपन में किन चीजों को लेकर घमंड रहा है?**

- बचपन में मुझे अपनी बार्बी डॉल्स के कलेक्शन पर घमंड था। फिर मैं उनको छोड़कर टॉम ब्वॉय बन गई। भैया की साइकिल, बाइक चलानी थी। सो वह घमंड भी कुछ ही दिनों का था।

- **स्ट्रीट डांसर्स के प्रति नजरिया कितना बदला है?**

- हमारे देश में अपार प्रतिभा हैं। जरूरी नहीं कि कुछ बनने के लिए केवल पैसों की ही जरूरत हो

और कौन-सी फिल्में कर रही हैं?

-'बागी 3' के बाद लव रंजन की फिल्म कर रही हूं। मैं रणबीर कपूर के साथ पहली बार काम कर रही हूं।

- **आपकी बकेट लिस्ट में और क्या-क्या है?**

- आज मैं लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में हूं। मैं वह करना चाहती हूं, जिसमें यकीन रखती हूं और कुछ ऐसा, जिससे किसी के चेहरे पर हंसी ला पाऊं। -प्रियंका सिंह

संजय दत्त ने मिलवाया 'कराटे चैंपियन' बेटे से

संजय दत्त का बेटा शाहरान कराटे सीख रहा था और अब उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। बेटे की इस उपलब्धि पर पिता को गर्व होना ही था। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद जब बेटे शाहरान ने कराटे की अच्छी प्रस्तुति दी तो संजय उसके बारे में सभी को बताने को बेताब हो गए। संजय ने इंस्टाग्राम पर अपने 9 साल के बेटे के बारे में जिक्र किया और उसे 'लिटिल कराटे किड' लिखा। अपने फोटो के कैप्शन में संजय ने लिखा, 'उसने आखिरकर 'फुल स्प्लिट' कर ही दिखाया। माई लिटिल कराटे किड'। संजय के इस फोटो पर पत्नी मान्यता ने भी कमेंट करते हुए लिखा, 'मॉई ब्वॉय'। संजय दत्त इन दिनों 'सड़क 2' में काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होनी है। वह यशराज की 'शमशेरा' में भी काम कर रहे हैं। वे परिवार से जुड़ने का ऐसा मौका निकाल ही लेते हैं।

श्वेता ने सास के लिए लिखा : आपको याद करेंगे...

अपनी सास रितु नंदा के निधन के चंद दिनों बाद उनकी बहू श्वेता नंदा ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उन्होंने सास और अपनी बेटी नव्या नवेली नंदा की मुस्कुराती हुई फोटो को साझा करते हुए लिखा- हम आपको बहुत याद करेंगे। श्वेता की इस पोस्ट पर जोया अख्तर, अंगद बेदी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रख्यात फिल्ममेकर राज कपूर की बेटी रितु पिछले करीब सात साल से कैंसर से जूझ रही थीं। गत मंगलवार को उनका निधन हो गया था।

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' है पूरी तरह पारिवारिक फिल्म : आयुष्मान

लगातार सात हिट देने वाले आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' है। उनका कहना है कि एक महत्वपूर्ण संदेश वाली यह फिल्म पूरी तरह पारिवारिक मनोरंजन है। फिल्म में आयुष्मान एक समलैंगिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। आयुष्मान कहते हैं, 'मैं ऐसी फिल्में चुनता हूं, जिसे पूरा परिवार एक साथ थियेटर में जाकर देख सके। तब बड़ी खुशी होती है, जब फिल्म देखने के बाद कलाकार लोगों को एंजॉय करते हुए देखता है और उसके संदेश की चर्चा करता है।

अनिल के लिए सही लुक पाना चुनौतीपूर्ण था

अनिल कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'मलंग' के रोल के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह रोल काफी चुनौतीपूर्ण है। उनका कहना था कि यह भूमिका उनके साथ बहुत दिनों तक बनी रही। जबसे 'मलंग' का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तभी से अनिल उसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगे। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी मुख्य भूमिकाओं में हैं और फिल्म में अनिल कपूर और कुणाल खेमू की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अनिल कपूर इसमें एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहे हैं या कातिल की? इस सवाल पर वह कहते हैं, 'फिल्म में मैं एक सनकी पुलिस अधिकारी बना हूं। यह अपने मिशन को पाने में लगा है। इस फिल्म में इस लुक को पाना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। अपने इस किरदार के साथ न्याय करने के लिए मुझे कुछ किलो वजन कम करना था। मैंने अपने बालों के साथ भी प्रयोग किया और टैटू भी करवाए। यह निश्चित ही ऐसा रोल है, जो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा। मैंने इसमें खूब मेहनत की है।' अनिल कपूर ने चार दशक लंबे अपने करियर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं की हैं। उनकी भूमिकाओं की प्रशंसा होती रही है और वह इसे अपना नसीब मानते हैं। वह कुछ अलग करना चाहते थे, जो प्रशंसकों को भी चौंका दे। अनिल का मानना है कि 'मलंग' के गाने पार्टियों में छा जाएंगे। वह खुद भी इस रोमांस थ्रिलर को देखना चाहते हैं। इसके टाइटल ट्रैक को 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा व्यू मिल गए थे।

एमजीआर बने अरविंद स्वामी का फर्स्ट लुक जारी

फिल्म 'थलाइवी' में तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। तमिल सिनेमा के सुपर स्टार अरविंद स्वामी फिल्म में एमजीआर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले फिल्म से कंगना रनोट के जयललिता लुक को जारी किया गया था। उनके लुक की काफी चर्चा हुई थी। फिल्म में एमजीआर की भव्य जिंदगी और

उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। एमजीआर ने बतौर अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक राजनेता के रूप में भी विराट सफलता हासिल की है। ऐसे में फिल्म के निर्माता विष्णु वर्धन इंदूरी और शैलेश आर सिंह ने अरविंद स्वामी का फर्स्ट लुक जारी करते हुए कहा है कि उनकी तरफ से यह एमजीआर को ट्रिब्यूट है। एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

फिल्म के निर्देशक विजय ने कहा, 'मेरे लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि मुझे ऐसे लेजेंड्स पर फिल्म करने का मौका मिला है, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित किया। कंगना को हमने जयललिता के किरदार में चुना है, उनके बाद हम एमजीआर के किरदार के लिए कलाकार खोज रहे थे। अंततः हमें अरविंद स्वामी परफेक्ट लगे। हमने अरविंद को अपनी रिसर्च दी थी, मगर उन्होंने इस किरदार के लिए खुद काफी मेहनत की है।' एमजीआर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।